# जमानत की घृणित शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की कुछ अदालतों की ओर से जमानत देते समय, खासकर दलित और आदिवासी आरोपियों से पुलिस थाने की सफाई कराने जैसी शर्तें लगाने पर कड़ी नाराजगी जतायी है. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दरअसल उन आदेशों पर फूट पड़ी, जिनमें खनन विरोधी प्रदर्शनों में शामिल आदिवासी और दलित समुदायों के लोगों के लिए जमानत पाने की शर्त के तौर पर पुलिस थानों की सफाई करना अनिवार्य किया गया था.

**ओडिशा की कुछ अदालतों की ओर से जमानत देते समय, खासकर दलित और आदिवासी आरोपियों से पुलिस थाने की सफाई कराने जैसी शर्तें लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जतायी है.**

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी शर्तें घृणित, अपमानजनक और जातिगत पूर्वाग्रह को दर्शाने वाली हैं, इंसाफ के खिलाफ हैं और आरोपी की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं. गौरतलब है कि 2023 से ओडिशा के तिजिमाली इलाके के आदिवासी और दलित समुदाय वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित एक बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं. यह विरोध तब शुरू हुआ, जब कंपनी को तिजिमाली बॉक्साइट ब्लॉक आवंटित किया गया, ताकि वह ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित लांजीगढ़ एल्युमीनियम रिफाइनरी के लिए कच्चा माल जुटा सके. हाल में आयी कई मीडिया रिपोर्टों में यह खुलासा हुआ था कि ओडिशा की कई अदालतें और स्वयं उच्च न्यायालय भी इस मामले में जमानत देते समय अजीब-ओ-गरीब शर्तें लगा रहे हैं. जैसे, लक्ष्मण नायक मामले और अन्य मामलों में आरोपियों को जमानत के लिए दो महीने तक पुलिस स्टेशन साफ करने जैसी अभूतपूर्व शर्तें लगायी गयी थीं. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले छह महीनों में ओडिशा हाई कोर्ट ने ही ऐसे 50 आदेश जारी किये थे. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया और कहा कि ओडिशा की राज्य न्यायपालिका ने औपनिवेशिक मानसिकता की ओर कदम बढ़ाया है. अदालत ने कहा, रिपोर्टों से लगता है कि ये शर्तें खास तौर पर दलित और आदिवासी आरोपियों पर ही लगायी जा रही थीं, जो चिंताजनक है. साधन संपन्न और अमीर लोगों को जमानत देते समय कभी ऐसी शर्तें नहीं लगायी जातीं. चीफ जस्टिस का कहना था कि 2026 में न्यायपालिका से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती. ऐसी शर्तें घृणित, अपमानजनक और जातिगत पूर्वाग्रह को दर्शाने वाली हैं, इंसाफ के खिलाफ हैं और आरोपी की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं. किसी आरोपी को दो महीने तक थाने की सफाई करने का निर्देश देना मानवाधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है और यह मानकर चलता है कि आरोपी पहले से दोषी है, जबकि कानून में ऐसा नजरिया स्वीकार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी जमानत शर्तों को अमान्य और निरस्त घोषित कर दिया.

# बंगाल में डेढ़ दशक की निराशा का अंत

**अंशुमान बनार्जी**
वरिष्ठ पत्रकार
bonnerjee57@gmail.com

**जब ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा सरकार के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था, तब बंगाल के समाज ने राहत की सांस ली थी. लोगों ने उन्हें ऐसी साफ-सुथरी सरकार चलाने का जनादेश दिया था, जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और 'सिंडिकेट राज' से मुक्त हो. एक ऐसा जनादेश, जिसके जरिये विकास, औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर, शिक्षा और तेजी से बिगड़ती कानून-व्यवस्था को फिर से बहाल किया जा सके. पर उस महिला ने यह सब कुछ गंवा दिया. विकास की उम्मीदें प्रतिगामी नीतियों की भेंट चढ़ गयीं, उद्योगों के बंद होने का सिलसिला और तेज हो गया. कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी.**

आखिरकार यह हो ही गया! चालीस डिग्री से भी ज्यादा तापमान वाली भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बावजूद पश्चिम बंगाल के वोटर बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले. वे जानते थे कि हर वोट मायने रखता है. और अब, बंगाल ने राहत की सांस ली है... हालांकि, माहौल शांत होने और स्थिरता आने में अभी थोड़ा समय लगेगा! पंद्रह साल की वह बेचैनी, जिसने बंगाल के आम लोगों को निराशा, मोहभंग और अभाव के भंवर में फंसा रखा था, अब जड़ से खत्म हो गयी है.

जब ममता बनर्जी ने सत्ता में जोरदार दस्तक दी थी- और माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था-जो आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बेमिसाल और असंभव-सा लगने वाला कारनामा था, तब बंगाल के समाज के हर तबके के लोगों ने राहत की सांस ली थी. लेकिन यह बात विडंबनापूर्ण तो है ही! लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को एक ऐसी साफ-सुथरी सरकार चलाने का जनादेश दिया था, जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और 'सिंडिकेट राज' से मुक्त हो. एक ऐसा जनादेश, जिसके जरिये विकास, औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर, शिक्षा और तेजी से बिगड़ती कानून-व्यवस्था को फिर से बहाल किया जा सके. पर उस महिला ने यह सब कुछ गंवा दिया. विकास की उम्मीदें प्रतिगामी नीतियों की भेंट चढ़ गयीं, उद्योगों के बंद होने का सिलसिला और तेज हो गया, और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां राज्य छोड़कर चली गयीं. रोजगार के अवसरों की जगह और ज्यादा बेरोजगारी ने ले ली, हजारों स्कूल या तो पूरी तरह बंद हो गये या फिर बहुत कम कर्मचारियों के सहारे किसी तरह घिसटते रहे, क्योंकि सैकड़ों शिक्षकों के पद खाली पड़े थे और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी, जबकि गुंडे और बलात्कारी पूरे राज्य में बेखौफ घूमते रहे-ठीक उस समय, जब पुलिस के हजारों पदों पर भर्ती का काम अधर में लटका हुआ था. वर्ष 2016 में उनके सत्ता में लौटने के तुरंत बाद एक छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण खबर ने दुनियाभर के बंगालियों को चौंका दिया. खबर यह थी कि 2017 में पश्चिम बंगाल में 'रामधनु' (बांग्ला में इंद्रधनुष के लिए प्रयुक्त शब्द) का नाम बदलकर 'रंगधनु' कर दिया गया था. पाठ्यक्रम में इस बदलाव ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. बांग्लादेश ने हिंदू प्रभावित शब्दावली से दूर हटने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तकों में बहुत पहले ही 'रंगधनु' को अपना लिया था. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2017 में कक्षा सात की 'पर्यावरण और विज्ञान' की पाठ्यपुस्तक में 'रंगधनु' को शामिल किया, ताकि एक तथाकथित 'धर्मनिरपेक्ष' स्वर को बढ़ावा दिया जा सके. ममता की रणनीति बांग्लादेश से आने वाले अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के प्रवेश को आसान बनाना था. केंद्रीय गृह मंत्रालय के बार-बार अनुरोधों के बावजूद अगस्त, 2025 तक 2,216.7 किलोमीटर लंबी पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा का लगभग 569.004 किलोमीटर हिस्सा बिना बाड़ के ही बना रहा.

नौ अगस्त, 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बेरहम यौन हिंसा और हत्या ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया. इसके चलते सीबीआइ जांच शुरू हुई और सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया. इस मामले का पश्चिम बंगाल में गहरा राजनीतिक और सामाजिक असर पड़ा. इसकी वजह से महिलाओं के वोटों का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल से हटकर भाजपा की तरफ चला गया. पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले में राज्य द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 24,640 पदों के लिए 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं शामिल थीं. लगभग 23 लाख उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, इस उम्मीद में कि उन्हें एक स्थिर सरकारी नौकरी मिलेगी. पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगभग 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा. जांच में इस धोखाधड़ी वाली भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की हेराफेरी का खुलासा हुआ, जिनमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी मेरिट लिस्ट और खाली उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर की गयी नियुक्तियां शामिल थीं. जिन लोगों को नौकरियां मिलीं, उनमें से कई पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जगह पक्की करने के लिए रिश्वत दी थी. यह चयन प्रक्रिया राज्य के सबसे हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों में से एक बन गयी. कई शिक्षकों ने दावा किया कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ इस प्रक्रिया का पालन किया था, और अब वे एक 'व्यवस्थागत विफलता' का खामियाजा भुगत रहे हैं. फरवरी, 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह कर्मचारियों को 2008-2019 तक के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करे, कोर्ट ने 'अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' के आधार पर महंगाई भत्ता पाने के कर्मचारियों के अधिकार को भी बरकरार रखा. इस निर्णय का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता दरों के बीच के अंतर को पाटना है.

राज्य के मुसलमानों ने भी ममता सरकार को बड़े पैमाने पर नकार दिया है, क्योंकि उनकी धारणा बन गयी है कि ममता सरकार ने उनके सशक्तीकरण या उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है. सुंदरबन के संदेशखाली गांव में महिलाओं के साथ लंबे समय तक हुए बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं के कारण या मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा 'बांग्लादेश शैली' की भीड़-हिंसा की घटनाओं के दोहराये जाने के कारण हिंदू समुदाय काफी समय से ममता बनर्जी के शासन में खुद को 'असुरक्षित' महसूस करने लगा था. ममता सरकार में घोटाले की शुरुआत 'शारदा चिट फंड घोटाले' से हुई थी, जिसने पूरे राज्य में सुर्खियां बटोरी थीं, यह तब हुआ था, जब अप्रैल, 2013 में शारदा कंपनी बंद हो गयी. उसके बाद 2014-16 में 'नारद स्टिंग ऑपरेशन' सामने आया, जिसमें एक पत्रकार ने तृणमूल के कई बड़े नेताओं और एक पुलिस अधिकारी को एक फर्जी कंपनी के पक्ष में नकद रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया था. बाद के वर्षों में अनगिनत अन्य घोटाले सामने आये, जिनमें रियायती राशन की आपूर्ति को खुले बाजार में बेच देना, मवेशियों और कोयले की तस्करी तथा अवैध रेत-खनन जैसे मामले शामिल थे. इन सबने ममता बनर्जी की सरकार के पतन में बड़ी भूमिकाएं निभायीं.

**(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

# अमेरिकी भारतीयों से श्रीधर वेंबु की अपील के मायने

**डॉ अश्विनी महाजन**
राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
ashwanimahajan@
rediffmail.com

**हाल ही में जानी-मानी सॉफ्टवेयर कंपनी 'जोहो' के प्रमोटर एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्रीधर वेंबु ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को खुला पत्र लिखकर देश वापस आकर भारत के भविष्य निर्माण हेतु सहायता की अपील की है. हालांकि, भारत में कुछ लोगों ने इस अपील को बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया है, और वे श्रीधर वेंबु की आलोचना कर रहे हैं. पर कई उनका समर्थन भी कर रहे हैं.**

हाल ही में जानी-मानी सॉफ्टवेयर कंपनी 'जोहो' के प्रमोटर एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्रीधर वेंबु ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को खुला पत्र लिखकर देश वापस आकर भारत के भविष्य निर्माण हेतु सहायता की अपील की है. इस तरह उन्होंने देश-दुनिया में एक नयी बहस छेड़ दी है. लंबे समय से भारत ने दुनिया को अपनी प्रतिभा का निर्यात किया है, जिसे 'ब्रेन ड्रेन' कहा जाता है. उस समय भारत वैश्विक स्तर की प्रौद्योगिकी के निर्माण में पिछड़ गया. पर आज भारत के पास क्षमता है कि वह विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी विकास की राह में आगे बढ़ सके. लेकिन उसे जल्द कर सकने की पहली शर्त है कि शेष दुनिया में बसे भारतीय, जो अवसरों के अभाव में देश छोड़ गये थे, वापस आयें.

इससे पहले भी समय-समय पर भारतीयों के वापस आने की अपील प्रमुख व्यक्तित्वों द्वारा की गयी है, लेकिन उस पर इतनी बहस कभी नहीं छिड़ी, जितनी श्रीधर वेंबु के आह्वान के बाद छिड़ी है. इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय मूल के लोगों को लेकर अशोभनीय वक्तव्य देना है. पिछले काफी समय से ट्रंप कह रहे हैं कि विदेशियों के कारण अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर घट रहे हैं. इसलिए उन्होंने एच-1बी वीजा के नियमों को कड़ा कर दिया है और विदेशी कार्मिकों की सख्ती से जांच-पड़ताल भी शुरू कर दी है. गौरतलब है कि एच-1बी वीजा के माध्यम से अमेरिका गये अधिकांश भारतीय अमेरिका में सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों में कार्यरत हैं. दिलचस्प है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक समय भारतीय लोगों और भारतीय नेतृत्व के प्रशंसक रह चुके हैं. लेकिन हाल में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर भारतीय लोगों और भारत के बारे में अपशब्द भी कहे हैं, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा अज्ञानतापूर्ण व अनुचित बताया गया है.

श्रीधर वेंबु की भारतीयों को वापस आकर अपने देश के प्रौद्योगिकी विकास में मदद करने की अपील आज के संदर्भ में दो कारणों से अधिक महत्व रखती है. पहला, बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में अमेरिकी प्रशासन, विशेष तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और कार्रवाई से अमेरिका में भारतीयों के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग रहा है. दूसरा, भारत प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रगति करने के लिए केवल तत्पर ही नहीं है, उसकी संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं. एक समय था जब भारत प्रौद्योगिकी की दृष्टि से काफी पीछे था, और हमारे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों से निकले ग्रेजुएट, प्रबंधन विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और पेशेवर भारत में प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार नहीं पा सकते थे. ऐसे में प्रतिभाशाली युवाओं ने विदेश का रुख कर लिया. इन युवाओं ने उन देशों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है. वे अपनी मेहनत, शिक्षा और सामर्थ्य के कारण औसत अमेरिकी से कई गुना ज्यादा कमाते हैं. अमेरिका के राजस्व में उनका हिस्सा छह प्रतिशत है. अमेरिका के सबसे ज्यादा आमदनी वाले प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में भारतीयों की मजबूत उपस्थिति है. उनकी शिक्षा और पेशेवर कुशलता अधिक है. उद्यमशीलता और व्यवसायों के स्वामित्व के नाते भी उनकी विशेष भूमिका है.

हालांकि, भारत में कुछ लोगों ने इस अपील को बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया है, और वे श्रीधर वेंबु की आलोचना कर रहे हैं. पर कई उनका समर्थन भी कर रहे हैं. जाहिर है कि भारतीय मूल के जो लोग वहां एक या अधिक पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनके लिए अपना सामान समेटकर भारत वापस लौटना आसान नहीं है. बहुत-से लोग ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, जीवन स्तर, नौकरी और व्यवसाय के अवसर भारत की तुलना में अमेरिका में कहीं बेहतर हैं. कुछ लोग तो अपने बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से अमेरिका गये हैं. इसलिए, श्रीधर वेंबु की अपील का अमेरिका में रुके रहने के उनके निर्णय पर सीमित असर पड़ सकता है. लेकिन, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेहतर शिक्षा और उसके बाद अच्छी नौकरी के लिए भारत छोड़ा था, पर अब उन्हें अमेरिकी प्रशासन से बुरा बर्ताव मिल रहा है-खासकर वीजा से जुड़ी अनिश्चितता तथा अन्य पाबंदियों के मामले में.

वहीं, ऐसे भी बहुत-से लोग हैं जो भारत में अवसर देखते हैं-यहां के फलते-फूलते स्टार्टअप और व्यावसायिक अवसरों और भारत की नवाचार, तकनीकी विकास और तेजी से बेहतर होते बुनियादी ढांचे की दिशा में हो रही प्रगति के कारण. ऐसे भी बहुत-से लोग हैं जिनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना है और उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है, तथा वे भारत वापस लौट भी रहे हैं. ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते बनाये हुए हैं-वे तकनीक के विकास में मदद कर रहे हैं, व्यवसायों और स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं. यह सब रातों-रात तो नहीं होगा, पर देर-सवेर भारतीय मूल के लोग भारत की ओर आकर्षित हो सकते हैं. हमें समझना होगा कि यह समय 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) के बजाय 'ब्रेन गेन' (प्रतिभा लाभ) के लिए बहुत उपयुक्त अवसर है.

**(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

**देश | दुनिया**

## आपराधिक नेटवर्कों को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

ढाका में आपराधिक गिरोहों द्वारा हाल में अंजाम दी गयी हिंसा की घटनाओं से राजधानी में संगठित अपराध के फिर से उभरने का संकेत मिलता है. 'प्रोथोम आलो' की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पांच अगस्त, 2024 को हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद कमजोर कानून व्यवस्था ने संगठित अपराधियों को फिर से सक्रिय होने का मौका दिया. उस समय कई बड़े अपराधियों को जमानत मिल गयी थी. अब उनमें से कई ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के लिए पूरे शहर में हिंसा फैला दी है. बीते 21 महीनों में पेशेवर अपराधियों से जुड़ी कम से कम 23 घटनाएं सामने आयी हैं. इनमें से कई घटनाओं की योजना विदेश में छिपे भगोड़े सरगनाओं द्वारा बनायी गयी थी. पुलिस का कहना है कि इसके लिए आपराधिक समूह वैसे स्थानीय बेरोजगार और कमजोर युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है. वास्तव में, वर्चस्व की यह लड़ाई अपराध संचालित अर्थव्यवस्था में निहित है, जहां अवैध आय के स्रोत सत्ता के समीकरण तय करते हैं. आपराधिक समूह वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं, जबकि आम व्यापारी प्रतिशोध के डर और कानूनी सुरक्षा में अविश्वास के कारण चुपचाप जबरन वसूली की मांगों को पूरा कर रहे हैं. इन संगठित आपराधिक नेटवर्कों को खत्म करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. पुलिस से अपेक्षा है कि वह अपराधियों और उनके ठिकानों की पहचान करने के लिए बेहतर खुफिया समन्वय को प्राथमिकता देगी, सीमा पार से उनकी पहुंच को खत्म करेगी, ऐसे धन के प्रवाह को रोकेगी, जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और जमानत पर रिहा किये गये अपराधियों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगी. इतना ही नहीं, इन अपराधियों और इन्हें राजनीतिक संरक्षण देने वालों के बीच के संबंधों को भी तोड़ना होगा. साथ ही, जागरूकता अभियान और रोजगार के अवसर के लिए तत्काल योजना बनानी होगी, ताकि बेरोजगार युवा पैसों के लिए आपराधिक समूहों में शामिल न हों.

The Daily Star

**बोधि | वृक्ष**

## तनाव से छुटकारा

तनाव से कैसे छुटकारा पाया जाये? यह आज का सबसे बड़ा प्रश्न है. इसका जवाब पाने की जगह आजकल 'स्ट्रेस मैनेजमेंट' पर वर्कशॉप, वेबिनार और व्याख्यान आयोजित किये जा रहे हैं. इतने मैनेजमेंट के बावजूद तनाव का ग्राफ तेजी से आसमान छूता जा रहा है. कारण क्या है? आप कभी मकड़जाल पर गौर कीजियेगा. जाल पर मकड़ी फर्राटे से दौड़ती है, पर मक्खी, मच्छर या अन्य कीड़े-मकोड़े उसमें कैद हो जाते हैं. चाहकर भी उस जाल से निकलकर भाग नहीं पाते. बात यह है कि जाल एक तरफ से चिपचिपा होता है और दूसरी तरफ सूखा रहता है. मकड़ी समझदारी से उसी तरफ चलती है, जिधर चिपचिपाहट नहीं होती. बेचारे कीड़े-मकोड़े चिपचिपे हिस्से में फंस जाते हैं. समझना होगा कि मुक्ति अलग चीज होती है और प्रबंधन अलग चीज. इसी तरह, इस माया रूपी जगत के भी एक तरफ 'और' पाने की चिपचिपाहट है. अफसोस! हमारा मन अधिकाधिक धन, ऐश्वर्य और रुतबा चाहता है. इस 'और' के जाल में चिपक जाता है. फिर सोच इसी में अटक जाती है- यदि यह 'और' न मिला तो? यह अटकन ही हमें घोर तनाव की भटकन में धकेल देती है. इसलिए धन, वस्तु, ऐश्वर्य, पद से इतना लगाव न करें कि उनके न मिलने या छिन जाने पर अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठें, तनावग्रस्त हो जायें. इच्छित वस्तु मिले या न मिले, अध्यात्म हमें दोनों ही परिस्थितियों में समता रखना सिखाता है. भौतिक विज्ञान के अनुसार तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- तनाव बराबर दबाव/क्षेत्रफल, यानी जितना दबाव बढ़ेगा, तनाव भी उसी अनुपात से बढ़ता चला जायेगा. वहीं जिस क्षेत्र पर जब दबाव पड़ रहा है, वह बड़ा होता जायेगा, तो तनाव कम होता जायेगा. आत्मिक स्तर का जागरण, अध्यात्म का ही अर्थ होता है. चूंकि ईश्वर अनंत है और हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए आत्मा का क्षेत्रफल भी असीम हुआ. इसलिए जब हम आध्यात्मिक साधना द्वारा असीम आत्मिक स्तर से जुड़ जाते हैं, तब दबाव सहन करने का अपना सामर्थ्य भी अनंत हो जाता है.

**-आशुतोष महाराज जी**

**कुछ | अलग**

## कैमरे के सामने मुस्कराने की कला

**विनोद कुमार विक्की**
व्यंग्यकार
vinodvicky5382@gmail.com

गहन शोध और पूरे आत्मविश्वास के साथ खुलासा हुआ है कि सिटी लाइट्स फिल्म का लोकप्रिय गीत 'मुस्कराने की वजह तुम हो' वाला 'तुम' कोई मानवीय काया नहीं, एक प्रभावशाली, किंतु भावशून्य उपकरण है. यह उपकरण कुछ और नहीं, बल्कि कैमरे का लेंस है. जी हां वही लेंस, जिसके सामने आते ही मनुष्य अपने समस्त दुख-दर्द समेट लेता है. जैसे ही पेशेवर स्टूडियो के फोटोग्राफर द्वारा 'स्माइल प्लीज' का निर्देश प्राप्त होता है, या सेल्फी स्टिक पर टिके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन होता है, चेहरे पर जमी चिंता की धूल झट से उड़ जाती है और होंठों पर मुस्कान स्वतः स्थापित हो जाती है.

यह मुस्कान इतनी अनुशासित होती है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग- सब सीमाएं पार कर जाती है. सबके चेहरे पर एक समान 'फोटो फ्रेंडली' लोकतंत्र दिखाई देता है. यह मुस्कान उतनी ही टिकाऊ होती है, जितने चुनावी वादे. क्लिक होते ही मुस्कान का पुष्पक विमान सीधे वास्तविकता की शोक वाटिका में क्रैश लैंडिंग कर देता है. फोटो में हम जितने खुश दिखते हैं, असलियत में उतने ही त्रस्त होते हैं. भागदौड़ भरी जिंदगी और अति व्यस्तता के बीच आज अधिकांश लोगों की मुस्कान ने स्वैच्छिक अवकाश ले रखा है. ऐसे में बेचारा मनुष्य जब-तब मुस्कराने के लिए अवसर ढूंढता फिरता है. तभी संकटमोचक बनकर प्रकट होता है कैमरे का लेंस. वह बिना किसी शर्त के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, 'आओ लल्ला, कुछ सेकंड के लिए थोबड़े पर मुस्कराहट लाओ, ताकि हम उस छवि को कैद कर सकें.' बस फिर क्या, जो मुस्कान महीनों से हड़ताल या अवकाश पर थी, वह भी तुरंत ड्यूटी जॉइन कर लेती है और चेहरे पर 'इमरजेंसी स्माइल' लागू हो जाती है.

इस कृत्रिम मुस्कराहट के नवीनीकरण की जिम्मेदारी अब तो शहरों में लगी तख्तियों ने भी अपने ऊपर ले रखी है- 'मुस्कराइए, आप झुमरी तिलैया में हैं', 'मुस्कराइए, आप गमगीन नगर में हैं.' असल में ये कोई साधारण संदेश नहीं, सांस्कृतिक अनुस्मारक हैं- 'भाई, यहां मुस्कराना मत भूल जाना, वरना लोग पहचान लेंगे कि तुम परेशान हो.' मनोचिकित्सक भी सलाह देते हैं- 'हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए.' इसी सलाह को उद्योग का रूप देते हुए लाफ्टर शो, हास्य कवि सम्मेलन और अब रील संस्कृति भी मैदान में उतर चुकी है. मुस्कान अब भाव नहीं, एक प्रोजेक्ट बन चुका है- जिसका उद्घाटन कैमरे के सामने होता है और समापन तुरंत बाद. गला-काट प्रतिस्पर्धा, कर्ज, महंगाई, तनाव, प्रदूषण के बीच भी आप डटे हुए हैं- मुस्कराने के लिए यही वजह पर्याप्त है. निष्कर्ष यही है कि सामने कैमरे का लेंस हो या लोग, जनाब मुस्कराइए क्योंकि आप सच में जीवित हैं!

**आपके | पत्र**

### मानवता को झकझोरने वाली घटना

बीते दिनों ओडिशा के क्योंझर जिले से मानवता को झकझोरने वाली एक घटना सामने आयी. एक गरीब आदिवासी जीतू मुंडा को अपनी बहन के बैंक खाते में जमा लगभग 19,000 रुपये निकालने के लिए कब्र खोदकर अपनी बहन का कंकाल कंधे पर लेकर बैंक जाना पड़ा, क्योंकि यह पैसा ही गरीब परिवार के जीवनयापन का सहारा था. न जाने कितने जीतू मुंडा यूं ही रोज संवेदनहीन सिस्टम का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों हमारे सिस्टम में गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती?

**राजेंद्र टेटे**, हजारीबाग

### बढ़ती गर्मी बढ़ा रही जल संकट

बढ़ती गर्मी के साथ देश के जलाशयों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है. आने वाले महीनों में पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर इसका असर पड़ सकता है. यदि समय रहते जल संरक्षण और जल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है. अनियंत्रित जल दोहन और वर्षा जल संचयन की कमी इस संकट को और बढ़ा रही है. अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति जल बचाने के लिए छोटे-छोटे प्रयास करे, तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है.

**रश्मि मांझी**, ईमेल से

**पोस्ट करें :** प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

संपादकीय

# निश्चय केलेल्या विजयचा विजय !

**एक लोकप्रिय** चित्रपट अभिनेता दोन वर्षांपूर्वी राजकीय पक्ष स्थापन करतो. स्वाभाविकपणे त्या पक्षाकडे प्रस्थापित पक्षांसारखी संघटनात्मक बांधणी नसते. त्या अभिनेत्याचे राज्यभर पसरलेले फॅन क्लबच संघटनेची जागा घेतात. तो नवा पक्ष तात्पुरत्या चिन्हावर निवडणूक लढतो आणि वर्षानुवर्षांपासून पाय रोवून बसलेल्या प्रस्थापित पक्ष, आघाड्यांना चारीमुंड्या चीत करत, थेट बहुमतापर्यंत पोहोचूनच थांबतो ! ही एखाद्या चित्रपटाची कथावस्तू वाटते; पण चित्रपटवेड्या तामिळनाडूत ते प्रत्यक्षात घडले आहे. सुपरस्टार विजय जोसेफ यांचा 'तमिळग वेट्री कळगम' (टीव्हीके) पक्ष विधानसभेच्या २३४ पैकी १०८ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. एम. जी. रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधी अशा चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींना मुख्यमंत्री करण्याची परंपरा असलेल्या तामिळनाडूने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, तिथे रूपेरी पडद्यावरील नायक प्रत्यक्ष जीवनातही नायकच असतो. पण विजय यांचे यश केवळ 'ग्लॅमर'मुळे नव्हे, तर त्यापलीकडे जात, मोठ्या सामाजिक-राजकीय प्रवाहांवर स्वार होऊन आले आहे. स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचे धाडस 'थलपती विजय' यांनी केले आणि द्रविड मुन्नेत्र कळगम व अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळगमसारख्या प्रस्थापित पक्षांना अक्षरश: लोळवले ! तामिळनाडूचे राजकारण १९७२ पासून द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातच फिरत राहिले. दोन्ही पक्षांवर भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे आरोप सातत्याने झाले. एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारने २०२१ मध्ये मोठ्या बहुमताने सत्ता मिळवली होती; पण पाच वर्षांत अपेक्षा आणि कामगिरी यांच्यातील दरी रुंदावली. 'प्रस्थापितविरोधी लाट' हा शब्द राजकारणात नेहमी वापरला जातो; पण तामिळनाडूत तो यावेळी खऱ्या अर्थाने प्रकट झाला. विजय यांच्या विजयाचे श्रेय केवळ तामिळ जनतेच्या चित्रपटप्रेमाला देणे अर्धसत्य ठरेल. रजनीकांत, कमल हसन, 'कॅप्टन' विजयकांत यांसारख्या चित्रपट अभिनेत्यांनीही राजकारणाची स्वप्ने जोपासली; पण कोणाला पदार्पणापूर्वीच माघार घ्यावी लागली, तर कोणाच्या पदरी अपयश आले ! मग विजय यांनी वेगळे काय केले? त्यांनी चित्रपटांसोबतचे नाते पूर्णपणे तोडले! एका चित्रपटासाठी सुमारे २५० कोटी रुपये मानधन आकारणाऱ्या अभिनेत्याचा हा त्याग जनतेला भावला. दुटप्पीपणा नाही, अर्धवट वचनबद्धता नाही ! जनतेने त्यावर विश्वास ठेवला. 'टीव्हीके'ची संघटनात्मक बांधणी अनोखी आहे. विजय यांनी २००९ मध्येच त्यांच्या ८५ हजारांहून अधिक फॅन क्लबना 'विजय मक्कल इयक्कम' या छत्राखाली आणले होते. त्यामुळे स्थापनेवेळीच पायाभूत संघटना तयार होती. 'टीव्हीके'ने 'मध्य-डाव्या' विचारधारेचा स्वीकार करत, आंबेडकर, पेरियार, कामराज यांना प्रेरणास्थान मानले. 'धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही' हा त्रिसूत्री जाहीरनामा विजय यांनी २०२४ मध्ये घोषित केला. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला 'वैचारिक विरोधक' आणि द्रमुकला 'भ्रष्टाचार व घराणेशाहीमुळे राजकीय प्रतिस्पर्धी' संबोधत नि:संदिग्ध भूमिका घेतल्याने, मतदारांना स्पष्ट पर्याय मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत ८५.१ टक्के मतदान झाले. तामिळनाडूच्या इतिहासातील सर्वाधिक ! त्याचा अर्थ हा, की निराश युवा मतदार मतदानासाठी बाहेर पडला. 'टीव्हीके'च्या जाहीरनाम्यातील नशामुक्त तामिळनाडू, रोजगार हमी, शिक्षण कर्जमाफी आणि विद्यार्थ्यांना मासिक आर्थिक मदत, हे मुद्दे तरुणांच्या हृदयाला स्पर्श करणारे होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये विजय यांच्या रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत ४१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ती दुर्घटना राजकीयदृष्ट्या विनाशकारी ठरू शकली असती; पण विजय यांनी तत्काळ माफी मागितली, पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली आणि प्रचार तात्पुरता थांबवला. मतदारांनी विजय यांच्या त्या संवेदनशीलतेला दाद दिली. खऱ्या नेतृत्वाची परीक्षा संकटात होते. विजय ती उत्तीर्ण झाले ! 'टीव्हीके'ला बहुमतासाठी १० जागा कमी पडत असल्याने सरकार गठनासाठी तडजोडी कराव्या लागतील. ती विजय यांची मोठी परीक्षा असेल. मोठ्या अपेक्षा निर्माण केलेले नवे पक्ष सत्तेत आल्यानंतर जुन्याच मार्गाने चालू लागतात, ही रीत बदलून मतदारांचा विश्वास जपणे हे त्यांच्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान असेल. जनतेने रुपेरी पडद्यावरील नायकाला प्रत्यक्षातील नायक बनवले आहे. आता त्याचा 'खलनायक' न होऊ देण्याची जबाबदारी विजय यांची आहे. त्यांचे यश हा एका 'सेलेब्रिटी'चा नव्हे, तर व्यवस्था बदलण्याचा निश्चय केलेल्या माणसाचा विजय आहे. जनतेशी प्रामाणिक आणि निश्चय अटल असल्यास, कोणताही प्रस्थापित गड अजिंक्य नाही, हा संदेश 'टीव्हीके'च्या विजयाने सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना दिला आहे !

# राहुल गांधींनी 'विजय' आधीच हेरला होता; पण..

## तामिळनाडूतील द्रमुकबरोबरची आघाडी मोडून राहुल गांधींना सिनेस्टार विजयसोबत जायचे होते.. पण सोनिया गांधींनी हा निर्णय फिरवला !

हरीश गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

**अधीर** झालेले राहुल गांधी तामिळनाडूमध्ये एक राजकीय जुगार खेळू पाहत होते. द्रविड मुन्नेत्र कळगमशी (द्रमुक) पक्षाशी असलेला जुना घरोबा बाजूला सारून 'तमिळग वेट्री कळगम'शी (टीव्हीके) हातमिळवणी करण्याचे धाडसी पाऊल ते टाकू पाहत होते. या 'टीव्हीके'चे मुखंड म्हणजे अलीकडेच अभिनेत्याचे पुढारी झालेले विजय.

राहुल यांचा बाण अचूक होता.. राहुल यांनी जानेवारीच्या प्रारंभी सेन्सॉरशिपच्या वादात विजय यांची बाजू घेतली, त्यामागे राजकीय अर्थ होता. पडद्यामागे बोलणी चालू आहेत, असे काँग्रेसमधील अंतस्थ सूत्रे सांगत असताना दक्षिणेकडे नवी कहाणी लिहिली जात होती. पक्षाचे दूत अंदाज घेत होते. द्रमुकबरोबर 'धाकटा भाऊ' ही भूमिका पार पाडण्याचा पक्षाच्या राज्यशाखेला कंटाळा आला होता. त्यामुळे नव्या प्रयोगाला विरोध नव्हता.

- पण या हालचालींनी अस्वस्थ झालेल्या द्रमुकच्या ज्येष्ठ नेत्या कनिमोळी दिल्लीला जाऊन धडकल्या. दहा जनपथवर जाऊन त्यांनी स्पष्ट सांगितले, 'बोटीला भगदाड पाडू नका.' तरी राहुल मागे हटले नाहीत. कोंडी आणखी बिकट झाली. तामिळनाडूतील आघाडीची गणिते विस्कटण्याच्या बेतात आली. अशा स्थितीत सोनिया गांधी यांनी हस्तक्षेप केला. ३ मार्चला त्यांनी याविषयी अंतिम भूमिका घेतली. काही फोन झाले. रूपरेषा ठरली आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्याशी थेट बोलणे झाले. 'द्रमुकशी आघाडी चालू राहील, कोणताही धोका पत्करायचा नाही', असा स्पष्ट संदेश दिला गेला. अशा प्रकारे राहुल यांचा प्रयोग सुरू होण्याच्या आधीच समाप्त झाला.

...नाखुशीत का होईना पक्ष पुन्हा पहिल्या रस्त्यावर आला. जागावाटप झाले. राहुल गांधी यांनी कुठल्याही सयुक्तिक मेळाव्यात भाषण केले नाही, स्वतःला दूर ठेवले ही गोष्ट वेगळी. परंतु राजकारणाला एक निष्ठुर असे वेळेचे भान असते. आता निकाल लागले आहेत. जे इतरांना दिसले नाही ते राहुल यांना नेमके दिसले होते असे आता बोलले जाऊ लागले आहे. टीव्हीकेचा उदय बदलत्या राजकीय वास्तवाची चाहूल देत असतानाही काँग्रेसने त्याचा फायदा उठवला नाही. शिस्तीने आतला आवाज दडपून टाकला. राहुल यांनी थांबायचे ठरवले. सोनियांनी निर्णय घेतला. राहुल यांनी आपली योजना पुढे ढकलली. तामिळनाडूत एक संधी मात्र नकळत निसटली.

### केजरीवालांचा किल्ला कसा कोलमडला?

गेली दहा वर्षे आम आदमी पक्षाकडे राज्यसभेतल्या दहा खासदारांचा एकसंध, लढवय्या

असा गट होता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला त्याची वारंवार ठेच लागायची. स्वाती मालीवाल यांच्यामुळे या किल्ल्याला काही भेगा गेल्या. पण तरीही तो अभेद्य राहिला. नंतर कहाणीला वळण देणारा क्षण आला. एकेकाळी अरविंद केजरीवाल यांचे डावपेच आखणारे धुरीण साथीदार राघव चढ्ढा यांचे पक्षातील स्थान डळमळीत झाले आणि धक्के बसायला सुरुवात झाली. अस्वस्थतेला विशिष्ट दिशा मिळाली. दिल्लीतल्या राजकीय जाणकारांना काय घडणार आहे याची चाहूल लागली होती. जे घडले ते मासलेवाईक होते.

दिल्लीतल्या एका रात्री नेहमीच्या सगळ्या राजकीय घडामोडी पार पडल्यानंतर 'आप'चे सात खासदार अमित शहा यांच्या घरी आले. तेथे त्यांची बंद दाराआड बोलणी झाली. ती निर्णायक होती असे अंतस्थ सूत्रे आता सांगतात. औपचारिकता फक्त बाकी होती. शाह यांनी मग त्यांच्या खास शैलीत एक राजकीय विधान केले. 'पंजाबमध्ये कारभार ठप्प आहे, केंद्राच्या योजनांना अडथळे येतात आणि 'आप'मध्ये बऱ्याच विसंगत गोष्टी चाललेल्या आहेत.' दरम्यान मध्यरात्र उलटत असतानाच सगळे काही ठरले. आवाजापेक्षाही दिल्लीत आकडे महत्त्वाचे असतात. तेच झाले. खासदारांच्या गटातले दोनतृतीयांश खासदार पक्षांतर विरोधी कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत बाहेर आले.

केजरीवाल यांचा किल्ला गाजावाजा करत ढासळला नाही... शांतपणे तो आतल्या आतच कोलमडला. दिल्लीतल्या सत्ता सारीपाटावर हे जे घडले त्यात बंड कमी होते. मध्यरात्रीची जलद, गुपचूप; पण मोठा परिणाम करणारी अशी ती धाड होती.

### बंगालमध्ये महिला मुख्यमंत्री होईल?

भाजपने पश्चिम बंगाल काबीज केल्यानंतर आता प्रकाशझोत 'ममता बॅनर्जी यांच्या जागी कोण येणार?' या प्रश्नाकडे वळला आहे. भाजप मुख्यालयात अर्थातच हा विषय ऐरणीवर आहे. पश्चिम बंगालला पहिली महिला मुख्यमंत्री भाजपकडून मिळेल काय? अठरा राज्यात भाजप स्वबळावर सत्तेवर आहे. भाजप मुख्यालयात पंतप्रधानांनी काही संकेत दिलेही आहेत. पक्षाच्या राजकारणात स्त्रीशक्ती ही केंद्रस्थानी असेल, विशेषतः महिला आरक्षण पुढे नेताना त्यावर भर दिला जाईल, असे मोदी म्हणाले आहेत. त्यामुळे काय घडते याकडे लक्ष आहे.

महिला मुख्यमंत्री दिल्यास विरोधकांच्या हल्ल्यांची धार कमी होईल आणि भाजपच्या महिला अभिमुखतेला बळकटी येईल. अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली यांची नावे सध्या चर्चेत आहेत. पण निर्णय व्हायला अजून वेळ लागेल. शुभेंदू अधिकारी, दिलीप घोष यांच्यासारखे मातब्बर नेते प्रतीक्षेत आहेतच. दुसरे म्हणजे राज्यात भाजपकडे प्रभावशाली महिला नेतृत्वही नाही.

harish.gupta@lokmat.com

अन्वयार्थ

# हे भोंदू बुवा आणि बाबा इतके का आणि कसे बोकाळले?

## सर्वसाधारण व्यक्तीलाही त्यातला फोलपणा ओळखता यावा, असे अचाट दावे करून गावोगावचे भोंदू बाबा लोकांना जाळ्यात ओढतात, ही चिंतेची बाब आहे.

कृष्णा चांदगुडे
कार्यवाह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

**राज्यात** खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणानंतर एकाच महिन्यात पोलिसांनी राज्यभरातल्या १६ भोंदू बाबांचा दरबार उधळून लावला आहे. यात बहुतेक प्रकरणात महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात भोंदूंचे पेव किती फुटले आहे, हेच या आकडेवारीवरून सिद्ध होते.

अंधश्रद्धेमुळे समाजातील फसवणूक रोखण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने १८ वर्षे लढा दिला. या प्रदीर्घ संघर्षानंतर २०१३ मध्ये 'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०१३' हा कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले असले, तरी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आपल्या पातळीवर या कायद्याबाबत समाजाचे प्रबोधन, प्रचार, प्रसार करत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहेत.

नाशिक येथे भोंदू अशोक खरातचे प्रकरण उघडकीला आल्यावर एक महिन्यात राज्यात एकूण १६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्राला चिंतेत टाकणारी व विचार करायला लावणारी ही घटना आहे. या फसवणुकीत सर्व स्तरातील लोक दिसतात. त्यात ग्रामीण भागातले गरीब, असहाय स्त्री-पुरुष आहेत, तसेच सुशिक्षित, शहरी नागरिकही आहेत. ग्रामीण भागातील सधन, शिक्षित कुटुंबे, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गातील लोकही या भोंदू बाबांच्या नादी लागलेले दिसतात. सर्वसाधारण बुद्धीच्या व्यक्तीलाही सहज फोलपणा ओळखता यावा, असे अचाट दावे करून गावोगावच्या भोंदूंनी या लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढलेले दिसते. ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. यात महिलांच्या शारीरिक शोषणासह आर्थिक लुटीचे प्रमाण अधिक आहे. आपली फसवणूक झाल्याचे पुष्कळ उशिरा लक्षात येते आणि ते उमगते तेव्हा पुढे येऊन तक्रार करावी, तर

सामाजिक प्रतिष्ठा आड येते. शिवाय भीती असते ती वेगळीच! खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांमध्ये लढण्याची हिंमत निर्माण झालेली दिसत आहे. आपल्याला न्याय मिळू शकतो, ही खात्री/अपेक्षाही वाढताना दिसते. वाईटातून चांगले जन्माला येत असेल, तर ते हे! अशा फसवणुकीकडे पाहण्याची सामाजिक नजरही मंद गतीने का असेना, पण निश्चितपणे बदलत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी उत्स्फूर्त, तर काही ठिकाणी अंनिसच्या प्रयत्नाने गुन्हे दाखल झाले आहेत. इतर पीडितांनीही पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या एक महिन्यातील दाखल गुन्ह्यामध्ये अशोक कुमार खरात (नाशिक), राजेंद्र गडगे (संगमनेर), चेतन सुनील मुळे (मूर्तिजापूर, जि. अकोला), पंकज देवराम घोलप (येडगाव, पुणे), मनोहर मामा भोसले ( कुर्डुवाडी, सोलापूर), नाना बर्डे (आळे फाटा, पुणे), ऋषिकेश वैद्य (वसई), अल्ताफ रईस खान (मालाड, मुंबई), रिधम पांचाळ (मालाड, मुंबई), गणेश शिंदे (श्रीरामपूर, अहिल्यानगर), अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा (नवी मुंबई), विठोबा वाल्मीक जाट (सातपूर, नाशिक), किसन तळपे मंदोशी (खेड, पुणे), महेशगिरी महेश काकडे (निफाड, नाशिक), अब्दुल राशीद शेख (खालापूर, रायगड), इरफान नियाज अहमद (कांदिवली, मुंबई) यांचा समावेश आहे.

जादूटोणा विरोधी कायद्याची सरकारी पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अंधश्रद्धेचे प्रमाण कमी होईल. परंतु, सरकार याबाबतीत उदासीन आहे. या कायद्याची शासकीय कमिटी कागदावरच राहिली आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दक्षता अधिकारी नेमणे या कायद्यान्वये जरूरीचे आहे, पण तशी नेमणूक कुठे झालेली नाही. त्यामुळे गुन्हा नोंदवताना पोलिसांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. परिणामी पीडितांना जलद व सत्वर न्याय मिळत नाही. पोलिसांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, अशी प्रशिक्षण शिबिरे घेऊ इच्छिते.

अंनिस मानधनाची अपेक्षा ठेवत नाही, पण सरकारची अनुकूलता व यंत्रणा मिळणे आवश्यक आहे. हा कायदा संमत होऊन १४ वर्षे झाली, पण या कायद्याचे नियम अजून बनविले गेलेले नाहीत. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष करणे आवश्यक आहे. हे सारे झाले, तर राज्यात बुवाबाजी व अंधश्रद्धेला चाप लावण्याचे प्रयत्न अधिक यशस्वी होतील.

krishnachandgude@Gmail.com

जगभर

# आईसाठी खरेदी केलं जगातलं सर्वांत महाग घर !

**एखाद्या** व्यक्तिगत घराची किंमत किती असावी आणि कोणी ते किती रुपयांना खरेदी करावं? आश्चर्यानं डोळे पांढरे होतील, असा एक व्यवहार युरोपात घडला आहे. आजपर्यंत एखाद्या व्यक्तीनं स्वत:साठी खरेदी केलेल्या घराचा सर्वाधिक किमतीचा जगातील हा सर्वांत मोठा सौदा आहे. हे घरही कोणी खरेदी करावं? - तर सध्या युद्धाच्या होरपळीनं अतोनात नुकसान झालेल्या युद्धग्रस्त युक्रेनमधील एका उद्योजकानं!

आघाडीचे उद्योगपती आणि बँकिंग क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून रिनात अख्मेतोव यांची युक्रेनमध्ये ख्याती आहे. युरोपातील मोनाको येथे त्यांनी पाच मजली आलिशान अपार्टमेंट खरेदी केलं आहे. त्याची किंमत आहे तब्बल ५,१३७ कोटी रुपये! जागतिक स्तरावर लक्ष वेधलं आहे. २०२४ मध्ये पूर्ण झालेला हा व्यवहार इतिहासातील सर्वात मोठा एकल निवासी मालमत्ता व्यवहार आहे.

मोनाकोच्या अधिकृत मालमत्ता नोंदी आणि लीक झालेल्या ई-मेल्सच्या तपासातून या व्यवहाराची माहिती समोर आली आहे. या खरेदीमागे संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या त्यांच्या आयुष्याची कहाणी आणि आईवरचं निस्सीम प्रेम दडलेलं आहे.

१९६६ मध्ये युक्रेनमधील डोनेत्स्क येथे एका साध्या कामगार कुटुंबात जन्मलेल्या रिनात यांचं बालपण अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत गेलं. त्यांचं घर म्हणजे तरी काय, तर २१५ चौरस फुटांची एक लहानशी, मोडकळीस आलेली खोपटी. खरं तर त्याला घर म्हणावं का, असाही प्रश्न पडावा. कारण, अत्यंत मूलभूत आणि गरजेच्या सुविधाही तिथे नव्हत्या.

लहानपणीचा एक प्रसंग मात्र त्यांच्या हृदयावर कायमचा कोरला गेला. एकदा आईसोबत ते दवाखान्यात गेले होते. डॉक्टरांकडून परतताना त्यांनी सहज म्हणून आईची पर्स उघडून पाहिली. त्यात अक्षरश: काही म्हणजे काहीच नव्हतं. एक फुटकी

कवडीही त्यात नव्हती. त्या क्षणानं त्यांच्या मनावर खोल परिणाम केला. त्याच वेळी त्यांनी निर्धार केला, काहीही करून मोठं व्हायचं आणि आईची पर्स पैशांनी भरून टाकायची!

याच निर्धारानं प्रेरित होऊन त्यांनी व्यवसायाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकलं. १९९० च्या दशकात 'आर्स' या कंपनीची स्थापना करून कोळसा व्यापार सुरू केला. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना चांगला पैसा मिळाला. पुढे त्यांनी ऊर्जा, स्टील आणि बँकिंग क्षेत्रात विस्तार करत स्वतःचं औद्योगिक साम्राज्य उभं केलं. सध्या 'सिस्टम कॅपिटल मॅनेजमेंट' या होल्डिंग कंपनीच्या माध्यमातून ते विविध उद्योगांचं संचालन करतात. त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा आज लाखो कोटींच्या घरात आहे.

अब्जाधीश झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या जुन्या घराच्या जागी आईसाठी भव्य महाल उभारून दिला. आता त्यांनी जे घर खरेदी केलं, त्यामागेही आईनं ज्या खस्ता खाल्ल्या त्यातून उतराई होण्याचाच प्रयत्न आहे. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रिनात यांनी आपल्या उद्योगांचं रूपांतर समाजोपयोगी कामांकडे केलं. त्यांच्या स्टील प्लांट्समध्ये टँकविरोधी अडथळे, बंकर आणि सुरक्षित स्टील शेल्टर्स तयार करण्यात आले. याच काळात त्यांनी सुमारे १.७० लाख बुलेटप्रूफ जॅकेट्स तयार करून युक्रेनच्या सैन्याला विनामूल्य पुरवले! यापूर्वीही २०११ मध्ये त्यांनी लंडनमधील 'वन हाइड पार्क' येथे एक आलिशान पेंटहाऊस खरेदी केलं होतं, जे त्या काळात ब्रिटनमधील सर्वात महागड्या निवासी व्यवहारांपैकी एक ठरलं होतं. याशिवाय, त्यांच्या ताफ्यात हजारो कोटी रुपयांची आलिशान यॉटही आहे.

जनमन

# उन्हाळा आणि शाळा, यांचा विचार व्हावा!

**नवीन** शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात १५ जूनपासून होणार आहे. अपवाद म्हणून विदर्भातील शाळा उशिरा सुरू करण्याची पद्धत यंदा रद्द करण्यात आली आहे. राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना २ मेपासून अधिकृतपणे उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांनी २८ मार्च रोजी काढलेल्या परिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, इतर मंडळांच्या शाळांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरवर्षी विदर्भातील उष्णतेची लाट बघता शाळा २६ जूनपासून सुरू केल्या जातात. याउलट या वर्षी उष्णतेचा पारा विदर्भात एप्रिल महिन्यातच चटके देत होता तर मे आणि जूनमध्ये तापमानाचे प्रमाण जास्त असणार आहे. विदर्भातील तापमानाचा विचार करता, शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील शाळांची वेळ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. १५ ते २७ जूनदरम्यान या शाळा सकाळी ०७ ते ११:४५ या वेळेतच भरतील. त्यानंतर ३० जूनपासून नियमित वेळापत्रक लागू होईल, असे पत्रकात जाहीर केले असले तरी, स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या तापमान वाढते असून, मागील आठवड्यात तापमान ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढे हे तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण मंडळांनी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा शाळा २६ जून रोजीच सुरू कराव्यात.

**- प्रज्ञानंद श्रीकृष्ण थोरात**

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

पर्पजफुल

# कोणते देश किती आनंदी आहेत, हे ठरवण्याचे निकष कोणते?

## 'वर्ल्ड हॅप्पीनेस रिपोर्ट'मध्ये सोशल मीडिया वापराच्या आनंदावर होणाऱ्या (विपरीत) परिणामाचे विस्तृत विवेचन केले आहे. काय सांगतात हे निष्कर्ष?

अमृत बंग
'निर्माण' या युवा उपक्रमाचे प्रमुख

**'वर्ल्ड हॅप्पीनेस** रिपोर्ट २०२६' नुकताच जाहीर झाला आहे. रिचर्ड लेयार्ड, जेफ्री सॅक्स, जॉन हेलिवेल इ. दिग्गज शास्त्रज्ञांनी हा अहवाल तयार केला आहे. २०१० सालच्या पहिल्या जागतिक अहवालानंतर आलेला हा चौथा अहवाल. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, गॅलप व युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्क याद्वारे १४७ देशांतील एक लक्षहून अधिक लोकांचा एकत्रितपणे केलेला हा अभ्यास जागतिक 'वेलबिइंग' - स्वास्थ्य व आनंद - याबाबतचा जगातील सर्वात मोठा व अग्रगण्य अहवाल आहे.

या १४७ देशांत भारताचा क्रमांक ११६ आहे. पाकिस्तानचा क्रमांक १०४, तर चीनचा ६५ आहे. एकूण जीवनविषयक समाधानाच्या मूल्यमापनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'कॅन्ट्रिल लॅडर' या पद्धतीमध्ये ० (सर्वात वाईट) ते १० (सर्वात चांगले) यादरम्यान स्कोअर मिळतो. जगात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या फिनलंडचा स्कोअर ७.७६४ आहे, भारताचा ४.५३६ आहे, तर सर्वात खाली असलेल्या सिएरा लियोनचा ३.२५१ आणि शेवटच्या स्थानावरच्या अफगाणिस्तानचा १.४४६ आहे. सर्वात वरच्या आणि सर्वात खालच्या क्रमांकावर असलेल्या देशांमधील ही प्रचंड तफावत नक्कीच चिंतेची बाब आहे.

या एकूणच अभ्यासात एकूण सहा मुद्दे समाविष्ट आहेत : आधारासाठी कोणीतरी असणे (सोशल सपोर्ट), दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी), उत्तम आयुर्मान, आयुष्यातील निवडी करण्याचे स्वातंत्र्य, औदार्य व इतरांना मदत करणे आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्ती. भारताचा स्कोअर वाढायचा

असेल, तर या सहा बाबींवर काम करणे आवश्यक ठरेल. हा अहवाल सोशल मीडिया वापराचा लोकांच्या आनंदावर होणाऱ्या (विपरीत) परिणामाचे विस्तृत विवेचन करतो. विशेषत: उत्तर अमेरिका आणि पश्चिम युरोपमध्ये, तरुण पिढी १५ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी आनंदी आहे. याच काळात सोशल मीडियाच्या वापरात तिकडे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अमेरिकेतील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना वाटते की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अस्तित्वातच नसावेत. इतर लोक वापरत असल्यामुळे ते त्यांचा वापर करतात, पण प्रत्यक्षात कोणीही त्यांचा वापर करू नये, असे त्यांना अधिक पसंत आहे. लॅटिन अमेरिकेतील आकडेवारीवरून दिसून येते की, प्रामुख्याने शिकणे व संवादाला चालना देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या तुलनेत, अल्गोरिथमिक फीड्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सना स्थान देणारे प्लॅटफॉर्म जीवन समाधानावर नकारात्मक परिणाम करण्याची अधिक शक्यता असते.

सोशल मीडियाचा अतिवापर नैराश्य आणि तणावाच्या वाढत्या प्रमाणाशी संबंधित आहे. सर्वात समस्याप्रधान प्लॅटफॉर्म ते आहेत जिथे मुख्य वापर निष्क्रिय (पॅसिव्ह) असतो आणि मुख्य सामग्री दृश्यात्मक (व्हिज्युअल) असते (जी सामाजिक तुलनेला प्रोत्साहन देते) आणि बहुतेकदा ती इन्फ्लुएन्सर्सकडून आलेली असते. या पार्श्वभूमीवर आपला व आप्त-मित्रांचा इन्स्टाग्राम, फेसबुक व यूट्यूबचा वापर नेमका कसा आहे? २५ वर्षांखालील व्यक्तींच्या आनंदातील बदलांच्या क्रमवारीत, १३६ देशांच्या यादीत अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड १२२ ते १३३ व्या क्रमांकावर आहेत. भारत सोडून या देशांत 'सेटल' होण्याचा धोशा आपल्या मुलांमागे लावणारे अनेक उच्च मध्यमवर्गीय पालक या डेटाकडे लक्षपूर्वक बघताहेत का?

amrutabang@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

# भारत-नेपाल लिपुलेख विवाद

**पड़ोसी** देश नेपाल की घरेलू राजनीति भारत के साथ उसके संबंधों में कई बार आड़े आती रही है। भारत और नेपाल में भी सीमा विवाद का अपना इतिहास जटिलताओं से मुक्त नहीं है। नेपाल के राजनीतिक दलों ने सीमा बिन्दुओं का राजनीतिक समाधान करने की बजाय अपने घरेलू राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। सीमाओं के ऐतिहासिक महत्व को जानना भी जरूरी है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी लेकिन बालेन शाह ने लिपुलेख विवाद को हवा देकर राष्ट्रवादी कार्ड खेल दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। काठमांडौ ने इस संबंध में भारत और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज कराया है। नेपाल ने भारतीय राजदूत को इस मामले में तलब भी किया है। नेपाल के दावों को लेकर भारत ने भी सख्त रुख अपनाया है।

भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर का पुराना रास्ता रहा है और इस रास्ते से यात्रा दशकों से होती रही है। जहां तक इलाके के दावों की बात है भारत ने हमेशा कहा है कि ऐसे दावे न तो सही हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। लिपुलेख दर्रे के दावों को इस तरह एकतरफा बनावटी तरीके से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। यद्यपि नेपाल और भारत ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। नेपाल की सख्त प्रतिक्रिया के पीछे 1816 में की गई सुगौली की संधि है। 1816 की सुगौली संधि के साथ एंग्लो-नेपाल युद्ध खत्म हुआ था और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया था। इस संधि के तहत काली नदी जिसे महाकाली भी कहा जाता है उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। 1990 के दशक से नेपाल का लगातार यही रुख रहा है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसलिए उस उद्गम स्थल के पूर्व में स्थित सारी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी शामिल हैं नेपाल की है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर पश्चिमी हिमालय के एक ऐसे हिस्से को कवर करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल, भारत और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। नई दिल्ली का तर्क है कि इस नदी का असली उद्गम स्थल और भी पूर्व में लिपुखोला सहायक नदी के पास स्थित है। ऐसा होने पर कालापानी और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं और वे वहां से कभी नहीं हटे। दशकों बीतने के साथ-साथ यह क्षेत्र 'विवादित' से बदलकर केवल 'प्रशासित' क्षेत्र बन गया। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता रहा जबकि नेपाल ने वर्षों तक इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी।

> **भारत का कहना है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर का पुराना रास्ता रहा है और इस रास्ते से यात्रा दशकों से होती रही है। जहां तक इलाके के दावों की बात है भारत ने हमेशा कहा है कि ऐसे दावे न तो सही हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। लिपुलेख दर्रे के दावों को इस तरह एकतरफा बनावटी तरीके से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। यद्यपि नेपाल और भारत ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है।**

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी भारत-नेपाल संबंधों में तनाव के बीच यह मुद्दा उठाया था। बाद में के.पी. शर्मा ओली ने भी इस मुददे को काफी हवा दी। उन्होंने तो लिपुलेख दर्रे, लिम्पिया धुरा दर्रे और काला पानी क्षेत्रों पर नेपाल का दावा जताते हुए देश का नया मानचित्र भी जारी कर दिया था। भारत ने तब भी नेपाल के नए नक्शे को खारिज करते हुए नेपाल के दावे को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर हैं। सन् 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला-लिपुलेख सड़क का उद्घाटन करने के बाद विरोध तेज हो गया। यह 80 किलोमीटर लंबी सड़क धारचूला के घटियाबगढ़ से शुरू होकर लिपुलेख में समाप्त होती है। नेपाल का दावा है कि यह सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। क्षेत्र को लेकर नेपाल में तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के.पी. ओली का पुतला जलाकर उन पर भारतीय परियोजना का मुकाबला करने के लिए समय पर कदम न उठाने का आरोप लगाया। नेपाल में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री ओली की इस बात के लिए आलोचना की कि वे शासन में अक्षमता या कोविड-19 से निपटने के अप्रभावी उपायों की आलोचनाओं को दबाने के लिए उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। फिर भी, अधिकांश लोगों ने राष्ट्रवाद की आवाज का समर्थन किया और सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की सराहना की।

नेपाल में लिपुलेख दर्रे का मुद्दा वहां की जनता के लिए भावनात्मक मुद्दा बन चुका है और सरकारों का ऐसे मुद्दों पर जनभावनाओं के विपरीत जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत की धर्म प्रेमी लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक और आस्थावान मुद्दा है। हर साल श्रद्धालुओं का जत्था कैलाश मानसरोवर की दुर्गम और कठिन यात्रा पर जाता है। इस बार बालेन शाह सरकार का अंदाज कुछ अलग है, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ-साथ चीन को भी अपने लपेटे में ले लिया है। जबकि पहले के.पी. शर्मा ओली ने सिर्फ भारत से ही आपत्ति जताई थी और उन्होंने नेपाल को पूरी तरह से चीन की गोद में डाल दिया था। बालेन शाह ने इस संवेदनशील मुद्दे को उठाकर अपनी छवि को चमकाने का ही प्रयास किया है, जो न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही न्याय संगत। कैलाश मानसरवर यात्रा में अड़ंगा लगाकर उन्होंने कोई राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दिया है। भारत से संबंधों में कड़वाहट पैदा कर नेपाल को नुक्सान ही होगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई कूटनयिक समाधान निकलता है और यात्रा क्या मोड़ लेती है।

## कोहेनूर की चमक में भी...

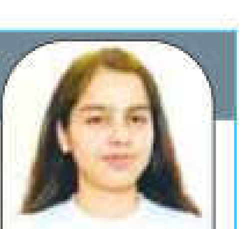
गीता पाढा

हमारी विरासत और संस्कृति हमें बाकी मुल्कों से भिन्न बनाती है,
देशभक्ति की खुशबू भारत के कोने-कोने से आती है,
अहिंसा परमो धर्मः इस देश की मिट्टी हमें यही सिखलाती है,
इतिहास गवाह है कि प्रथम आक्रमण की नीति यहां अनुचित बतायी जाती है,
कोहेनूर की चमक में भी इतिहास की गहराई नज़र आती है,
कुछ बयान उसे लौटाने की बात करते, तो कुछ में सियासत झलक जाती है,
पर सच ये है कि धरोहर केवल पत्थर नहीं, भावनाओं से जुड़ जाती है,
हर भारतीय के दिल में अपनी विरासत की लौ सदा ज्वलंत पाती है...।।

# भारत का ऑपरेशन सिंदूर : रणनीतिक विजय का एक वर्ष

रवि मुरुगन
मेजर जनरल
(सेवानिवृत्त)

**आज** से एक साल पहले, 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसने सिर्फ नीति की घोषणा से आगे बढ़कर उसे निर्णायक कार्रवाई में बदल दिया। यह भारत की धरती पर दशकों से जारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने के तरीके में बड़ा बदलाव था। कई मायनों में ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस लंबे संघर्ष में एक अहम मिसाल बन गया जिसमें पाकिस्तान द्वारा गैर-राज्य तत्वों को प्रॉक्सी हिंसा के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जवाब दिया गया। इस अभियान के पीछे भारत का राजनीतिक इरादा पूरी तरह साफ और अडिग था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों के बर्बर हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ प्रतीकात्मक या सीमित नहीं थी। यह पूरी तरह योजनाबद्ध, समयबद्ध और स्पष्ट उद्देश्य वाली कार्रवाई थी। 88 घंटे तक चले इस अभियान ने साफ दिखाया कि भारत ने तय लक्ष्यों के साथ सुनियोजित जवाबी रणनीति अपनाई और अपने उद्देश्य पूरे करने के बाद अपनी शर्तों पर इसे समाप्त किया।

राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से इस अभियान की दो बातें खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं। पहली, हमलों का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। लक्ष्य सिर्फ नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे। यह एक सोची-समझी रणनीतिक बढ़त थी, जिसने पाकिस्तान की कथित परमाणु सीमाओं और उसकी प्रतिरोधक नीति को सीधे चुनौती दी।

दूसरी, इस अभियान ने दिखाया कि आज के सूचना युग के युद्धों में तकनीक कितनी केंद्रीय भूमिका निभाती है। क्रूज़ मिसाइलों, लोइटरिंग हथियारों, नेटवर्क आधारित प्रणालियों और बहु-स्तरीय वायु एवं मिसाइल रक्षा तंत्र के इस्तेमाल ने साफ किया कि अब युद्ध सटीकता, तेज़ी और बेहतर समन्वित युद्धक्षेत्र समझ पर आधारित हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह भारत की उस नई युद्ध रणनीति का प्रदर्शन भी था, जिसमें दूर से मार करने की क्षमता, तेज़ निर्णय प्रक्रिया और कई मोर्चों पर एकीकृत कार्रवाई प्रमुख है।

7 मई 2025 को शुरू हुआ यह अभियान पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ढांचे पर तेज़, सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई थी। यह भारत की समन्वित सैन्य क्षमता का नियंत्रित लेकिन बेहद प्रभावशाली प्रदर्शन था, जिसका मकसद दुश्मन पर कीमत थोपना था, बिना संघर्ष को बेवजह बढ़ाए। एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर भारत की बढ़ती रणनीतिक परिपक्वता का प्रमाण माना जाता है-यानी परमाणु शक्ति से लैस दुश्मन को जवाबदेह ठहराने की क्षमता, वह भी स्पष्ट उद्देश्य, मजबूत इरादे और संतुलित रणनीति के साथ।

आज के कई युद्ध जहां लंबे और अनिर्णायक बन जाते हैं, वहीं ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट लक्ष्य और ठोस कार्रवाई के लिए अलग दिखा। इसका राजनीतिक उद्देश्य साफ था-आतंकवाद के ढांचे और उसे समर्थन देने वालों पर सीधी और ठोस चोट करना। लक्ष्य पूरा होते ही अभियान को सीमित रखा गया। टारगेट चुनने में भी संयम और दृढ़ता दोनों दिखे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, ताकि उनकी क्षमता कमजोर हो, लेकिन आम नागरिकों को नुकसान और अन्य सहायक क्षति न्यूनतम रहे।

सैन्य संचालन के स्तर पर यह अभियान भारत की दूर से सटीक हमला करने वाली युद्ध क्षमता के और परिपक्व होने का संकेत था। लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों और प्रिसिजन हथियारों से लैस राफेल, साथ ही ब्रह्मोस प्रणाली से जुड़े सुखोई एसयू-30एमकेआई जैसे प्लेटफॉर्म ने बड़े दायरे में गहराई तक समन्वित हमले संभव बनाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आगे बढ़कर पाकिस्तान के पंजाब के भीतर तक कार्रवाई का विस्तार इस बात का संकेत था कि भारत ने अपनी पुरानी स्व-निर्धारित सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए कथित सुरक्षित ठिकानों को भी चुनौती दी। इस अभियान की रक्षा व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही।

एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन या मिसाइलों के जरिए किसी भी जवाबी हमले को प्रभावी ढंग से निष्फल कर दिया। आक्रामक मारक क्षमता और मजबूत रक्षात्मक सुरक्षा के इस मेल ने साफ दिखाया कि आधुनिक युद्ध में नेटवर्क आधारित समन्वय और बहु-स्तरीय सुरक्षा कितनी जरूरी हो चुकी है।

रणनीतिक सिद्धांत के स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर ने एक साथ तीन अहम सीमाएं पार कीं। जिम्मेदार लक्ष्य चयन, संतुलित सैन्य बल का इस्तेमाल और स्पष्ट दबावकारी संदेश। इसने दिखाया कि जब कार्रवाई साफ राजनीतिक इरादे, सटीक सैन्य लक्ष्य और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के साथ की जाए तो दुश्मन को सज़ा दी जा सकती है बिना हालात को अनियंत्रित युद्ध में बदले। भारत ने युद्ध का दायरा पूरी तरह बढ़ाने के बजाय उसे सीमित लेकिन प्रभावी तरीके से फैलाया, जिससे पूर्ण युद्ध से बचते हुए भी दुश्मन पर ठोस कीमत थोपी गई।

इस अभियान की एक और बड़ी खासियत थी-तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और पूरे रक्षा तंत्र का एकीकृत संचालन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की स्थापना के बाद विकसित नई रक्षा संरचना का असर साफ दिखा। समुद्री मोर्चा, वायु शक्ति और ज़मीनी लक्ष्य-ये अलग-अलग अभियान नहीं थे, बल्कि एक ही संयुक्त रणनीति के हिस्से थे।

इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बढ़ती ताकत ने और मजबूत बनाया। स्वदेशी प्लेटफॉर्म, सटीक हथियार प्रणालियां, काउंटर-ड्रोन तकनीक और आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस) जैसी घरेलू क्षमताओं की बढ़ती भूमिका ने दिखाया कि भारत धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी गहराई का भी प्रमाण था। अब मजबूत रक्षा तैयारी सीधे देश की औद्योगिक क्षमता से जुड़ चुकी है।

कूटनीतिक स्तर पर भी यह अभियान बेहद सोच-समझकर चलाया गया। भारत ने अपनी कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जवाब और आत्मरक्षा के दायरे में रखकर पेश किया जिससे ऑपरेशन सिंदूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नैतिक और रणनीतिक आधार बना। सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक संदेशों के बीच यह तालमेल भारत के लिए रणनीतिक स्पेस बनाए रखने में बेहद अहम साबित हुआ।

आखिरकार, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत उसका सही समय पर और स्पष्ट तरीके से समाप्त होना था। अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद भारत ने तय समयसीमा के भीतर अभियान रोक दिया जिससे वह उन लंबे और दिशाहीन संघर्षों से बचा रहा जो आज कई आधुनिक युद्धों की पहचान बन चुके हैं। इसकी शुरुआत, संचालन और समापन, तीनों में दिखाई गई स्पष्टता और सटीकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी पहचान रही।

एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर की असली विरासत सिर्फ दुश्मन को हुए नुक्सान में नहीं, बल्कि उस नई मिसाल में है जो इसने कायम की। इसने दिखाया कि संतुलित, तकनीक से लैस और राजनीतिक नेतृत्व से निर्देशित सैन्य कार्रवाई दुश्मन पर भारी कीमत डाल सकती है, उसकी रणनीति बदल सकती है और फिर भी नियंत्रित दायरे में रह सकती है। यह परमाणु खतरे के बीच सीमित युद्ध के लिए भारत के उभरते मॉडल को दिखाता है- इरादों में मजबूत, कार्रवाई में सटीक और संयम में अनुशासित।

# मोदी की झालमुड़ी का कमाल, जीत लिया बंगाल !

फिरोज बख्त
अहमद

**यदि** यह कहा जाए कि दिल जीतने की कलाकारी में भारतीय प्रधानमंत्री से बड़ा कलाकार कोई दूसरा नेता विश्व में नहीं। सड़क पर झालमुड़ी खाई और बच्चों के साथ, बंगाल के लोकप्रिय खेल फुटबॉल के कोच की भांति फुटबॉल खेल कर ममता दीदी का संपूर्ण खेला कर दिया। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय ! दूसरी बात यह कि भारत के चुनाव इतिहास का भाजपा की बंगाल वाली जीत एक करिश्मा, एक अजूबा है। जहां अपने दौरों में मोदी और अमित शाह ने "मेक बंगाल ग्रेट अगेन" की भाषा से एक आम बंगाली के मन, मस्तिष्क और आत्मा को जीत लिया। इस बार बंगाल में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रांतों में भी भाजपा ने, केरल को छोड़ सबसे बढ़िया किया है। तमिलनाडु में भी स्टालिन का बोरिया-बिस्तर लपेटने में भाजपा का बड़ा रोल रहा। इस चुनाव को जीतने में जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जुगलबंदी रही, वह अटल बिहारी वाजपेयी के इसी कथन को जमीन पर लाया कि सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। वास्तव में स्वयं भाजपा को ही नहीं पता कि कितना बड़ा किला बंगाल का उसने अपनी झोली में डाल लिया है। हां, जीतने के बाद शुभेंदु सरकार ने जिस प्रकार से मुसलमानों को दोष दिया कि उन्होंने दोनों हाथों से भर-भर कर ममता को वोट दिए, ठीक नहीं था, क्योंकि जीतने के बाद सभी को ग्रेसफुल होना चाहिए। इस प्रकार के बयानों से दूरियां और वैमनस्य बढ़ते हैं।

बंगाल में मोदी-शाह की कार्पेट बॉम्बिंग ने प्रांत के विकास के लिए ममता के ड्रोन फेल कर दिए। जिस प्रकार से अमित शाह ने अपनी मेहनत और कार्य प्रणाली द्वारा एक के बाद दूसरा चुनाव जीता है उससे उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि अपने परम मित्र मोदी के वे सब से दक्ष उत्तराधिकारी हैं। हां, मोदी का यह कमाल अवश्य है कि उन्होंने पिछले बारह वर्षों में भारत के डेढ़ करोड़ निवासियों को नरेंद्र मोदी में परिवर्तित कर दिया है। इन चुनावों का सबसे अच्छा पहलू यह रहा कि कहीं भी गोला-बारूद नहीं चला, कोई मारा नहीं गया जैसे बंगाल में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की जान विशेष रूप से बंगाल और केरल में ली जाती रही हैं। बंगाल में ममता का खौफ था कि यदि उन्हें पता चल गया कि वोट तृणमूल को नहीं दिया गया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितने भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस विजय के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। जहां भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस जीत का श्रेय दे रही है, उसी प्रकार से हर बलिदानी कार्यकर्ता के परिवार को रोज़गार और मदद से मालामाल कर देना चाहिए और उनकी प्रतिमाएं स्थापित होनी चाहिए।

ममता का जबानी जमा खर्च, 'मां, माटी, मानुष' सुनने में तो बहुत अच्छा था, मगर फेल इसलिए हुआ कि उसको उन्होंने जमीन पर नहीं उतारा और न तो लोगों को रोज़गार मिला और न ही सिक्योरिटी। वास्तव में ममता दीदी ने तीसरी पारी में जनता को "टेकन फॉर ग्रांटेड" के रवैये से काफ़ी दु:खी किया। फिर जिस प्रकार धमकी भरी और घमंड से चूर भाषा प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेताओं के प्रति ममता दीदी बोलती चली आ रही हैं, आम लोगों में इसका विपरीत असर पड़ा।

हैरानी की बात है कि जिन मुसलमानों ने दोनों हाथ भर कर तृणमूल को वोट दिए, ममता ने सिवाय नारेबाज़ी के ठेंगे के उन्हें कुछ नहीं दिया। उनकी बस्तियां गंदगी और बड़बोले कुछ नहीं। उनके मकान, मदरसे आदि दयनीय स्थिति में हैं। बजाय स्कूलों क्रीड़ांगनों, उद्यानों आदि के उनकी बस्तियों में पुलिस स्टेशन अधिक हैं। भले ही भाजपा ने पूर्व में चुनाव जीते हों, मगर जो ऐतिहासिक विजय बंगाल में भाजपा को मिली है, उसे हम बंपर जीत का दर्जा नहीं तो क्या कहें। ममता राज की काफ़ी त्रुटियां सामने आई हैं। संदेशखाली, बसीरहाट और आर जी कार मेडिकल कॉलेज जैसी हज़ारों बातें ऐसी हुईं कि जो जनता में चर्चा का विषय बनीं। जिस प्रकार से भाजपा की कैंडिडेट रत्ना देव नाथ के चेहरे पर तृणमूल के गुंडों ने थूका, वह वीभत्सपूर्ण कृत्य भी दुनिया ने देखा। यह भी देखा गया कि तृणमूल के बदमाशों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी औरतों को तृणमूल के नेताओं के घर भेजो। जिस प्रकार से ममता दीदी ने बंगाल में भय का भयानक वातावरण पैदा कर दिया था। भले ही ममता ने पूर्व में चुनाव जीते, मगर लोगों को प्राय: विस्मय होता था किस प्रकार से आग और ज़हर उगलने वाली चंडी देवी जैसी ममता दीदी कैसे जीत जाती हैं।

कुछ भी हो, सलाम है, भाजपा के धुरंधर अंदाज़ से इलेक्शन लड़ने की कोशिशों को। कोई क्लोन भी नहीं कर सकता था कि बंगाल भाजपा की झोली में गिर जाएगा। अब जबकि भाजपा जीत चुकी है, उसे इस बात पर ध्यान देकर काम करना होगा कि आजादी के बाद से बंगाल को इंसाफ नहीं मिला है और इसकी दशा जर्जर है। पहले तो इस डबल इंजन सरकार को 75 साल के खड्डों को भरना होगा और साथ ही साथ मुस्लिमों का दिल भी जीतना होगा, जिनके क्षेत्रों से इस बार 45 प्रतिशत सीटें भाजपा ने जीती हैं जिससे प्रतीत होता है कि उन्होंने भी भाजपा को वोट दिए हैं।

# निगरानी, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की मजबूती के लिए 1476 करोड़ रुपए का करार

**रक्षा** क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती देते हुए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बड़ा रक्षा सौदा किया। यह रक्षा सौदा भारतीय सेना के लिए किया गया है। इस सौदे के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) हैदराबाद के साथ 1,476 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इस खरीद से भारतीय सेना का निगरानी व संचार तंत्र और मजबूत होगा। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी इससे मदद मिल सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यह अनुबंध पांच ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय की इस डील में कम से कम 72 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। यह स्वदेशी सामग्री देश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रही है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह करार 'बाय (इंडियन–इंडिजेनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड)' श्रेणी के तहत किया गया है। अनुबंध पर हस्ताक्षर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 (रक्षा मंत्रालय) में किए गए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के शामिल होने से भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। खास तौर पर यह सिस्टम सेना की निगरानी, संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इस सौदे से भारतीय सेना को तकनीकी बढ़त को मिलेगी ही, वहीं दूसरी ओर देश के स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। इससे घरेलू कंपनियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और सप्लाई चेन को नए अवसर मिलेंगे।

सरकार का मानना है कि यह करार 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल को गति देगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर लगातार जोर दिया गया है, और यह अनुबंध उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे प्रोजेक्ट्स भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बना रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही भारत के अग्रणी युद्धक टैंकों टी-72 और टी-90 टैंकों से जुड़ा एक बड़ा रक्षा सौदा भी किया गया था। इस सौदे के तहत लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से टी-72 और टी-90 टैंकों के ट्रॉल असेंबली की खरीद का निर्णय लिया गया। ट्रॉल असेंबली, युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगों (माइनफील्ड) को पार करने में सेना को और अधिक सशक्त बनाएगी।

गौरतलब है कि ट्रॉल, टैंकों के सामने आने वाली बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर देता है। यह टैंक के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनता है। यह रक्षा सौदा भी आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देते हुए किया गया था। इसके लिए लगभग 975 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद से जुड़े थे। -आईएएनएस

# एचडीएफसी बैंक के सीईओ के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला खारिज

**मुंबई,** (पंजाब केसरी): बंबई उच्च न्यायालय ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन के खिलाफ दायर रिश्वतखोरी के मामले को मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने ट्रस्ट की शिकायत को बैंक की ओर से 65 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए शुरू की गई कार्यवाही के जवाब में उठाया गया कदम करार दिया।

न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की पीठ ने कहा कि वित्तीय संस्थान ऋण राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य हैं। उसने कहा कि शिकायत ट्रस्ट के पूर्व और वर्तमान न्यासियों के बीच कड़वाहट और तनावपूर्ण संबंधों का नतीजा थी।

लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बांद्रा में लीलावती अस्पताल का संचालन करता है।

उच्च न्यायालय ने कहा, हमारी राय में यह शिकायत ट्रस्ट के खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही के जवाब में उठाए गए कदम के अलावा और कुछ नहीं है। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री शिकायतकर्ता की ओर से किए गए दावे की जांच को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराती है। अदालत ने शिकायतकर्ता के इस दावे को भी मानने से इनकार कर दिया कि ट्रस्ट के संस्थापक किशोर मेहता की मौत 2024 में बैंक की ओर से डाले गए दबाव के कारण हुई थी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

दैनिक जागरण
अनुशासन उन्नति का आधार है

## ममता का हठ

पश्चिम बंगाल में खुद अपना भी चुनाव हारने के साथ ही बुरी पराजय का सामना करने के बाद ममता बनर्जी का यह कहना राजनीतिक हठधर्मी ही है कि वे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगी। ऐसा कहकर वे अपनी अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचय देने के साथ ही अपने उस अराजक राजनीतिक व्यवहार को भी रेखांकित कर रही हैं, जिसके चलते उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। वे इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं कि उनके साथ-साथ पराजय का सामना करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी हार सहजता से स्वीकार कर ली और केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तो ऐसा करने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी एक तरह से बालहठ ही नहीं दिखा रही हैं, बल्कि राजनीतिक अपरिपक्वता का भी परिचय दे रही हैं। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि यदि वे इस्तीफा नहीं देतीं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। यदि उनके हठ के कारण इसकी नौबत आई तो इससे उनकी फजीहत ही होगी। रह-रहकर संविधान की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी जिस तरह इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, उसकी मिसाल मिलना कठिन है।

इस्तीफा न देने की जिद करके ममता बनर्जी अपने समर्थकों को यह संदेश देने की नाकाम कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस तरह से वे न तो लोगों की सहानुभूति अर्जित कर सकती हैं और न ही अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि लोग सब कुछ तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी का अहंकार आसानी से नहीं भूलते। यदि ममता बनर्जी अपनी खोए हुए जनाधार को फिर से पाना चाहती हैं तो उन्हें जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उनका तर्क है कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है। साफ है कि वे यह समझने-मानने को तैयार नहीं कि उनकी पराजय का कारण उनका कुशासन और उसके चलते जनता की उनसे गहरी नाराजगी रही। यह बताने की जरूरत नहीं कि तृणमूल कांग्रेस कोई 10-15 सीटों के अंतर से बहुमत से दूर नहीं रही। वह 294 सीटों वाली विधानसभा में सौ सीटों तक भी नहीं पहुंच सकी। ममता बनर्जी खुद को हराए जाने का आरोप उछाल कर वही लाइन ले रही हैं, जो राहुल गांधी ने एक लंबे समय से पकड़ रखी है और जिसके तहत चुनाव की चोरी का राग अलापते रहते हैं। गत दिवस उन्होंने यही राग अलापते हुए कहा कि असम और बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव की चोरी की। प्रश्न यह है कि आखिर केरलम के बारे में उनकी क्या राय है, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीत हासिल की है?

## बख्शे न जाएं दोषी

बिहार सरकार जिस प्रकार अपराध के विरुद्ध सख्त हुई है, पुल-पुलियों के रख रखाव के मामले में भी उसी शिद्दत के साथ गंभीर होने की जरूरत है। पिछले वर्ष बड़ी संख्या में विशेषकर पुलियों के ध्वस्त होने से राज्य सरकार की किरकिरी हुई थी। हालांकि ये ऐसी छोटी-छोटी पुलिया थी, जिनका निर्माण ज्यादातर स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किया गया था। पूर्व के शासनकाल में बनी पुलियों की खामी का ठीकरा वर्तमान सरकार पर फूटा। हालांकि यह जरूरी था कि पुलियों का रख रखाव वर्तमान सरकार करे। नीतीश सरकार में पुल-पुलियों के रख रखाव के लिए हेल्थ कार्ड की योजना बनाई गई थी। विशेषज्ञों की टीम पुलों की भौतिक स्थिति की जानकारी हेल्थ कार्ड में दर्ज करेगी। इसी आधार पर उनकी मरम्मत की योजना बनाकर काम होना था। इस प्रक्रिया को पूरी तरह सक्रिय कर देने के जरूरत है। भागलपुर में रविवार की रात 25 साल पुराने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा देखते-देखते गंगा में समा गया। पिछले आठ वर्षों से इसके रख रखाव में शिथिलता बरती जा रही थी। संबद्ध विभाग एक दूसरे को आरोपित कर रहे, लेकिन नुकसान तो आम जनता का हुआ। एनएच के कार्यपालक अभियंता को निलंबित किया गया है। घटना की जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पुल को तीन महीने में सुचारू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।

**पुल-पुलियों के रख रखाव के लिए हेल्थ कार्ड की योजना को क्रियान्वित करने की जरूरत है**

# आतंक के विरुद्ध और मजबूत हो मुहिम

राजा मुनीब

**जब तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक वह भारत के लिए खतरा बना रहेगा**

पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले को साल भर बीत गया है और इस हमले के जवाब में आपरेशन सिंदूर का भी एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। एनआइए की जांच में यही सामने आया था कि पहलगाम हमले की जड़ें पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी गुटों से जुड़ी थीं और इस हमले में भी वैसे ही तौर-तरीके अपनाए गए, जैसे मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा हमले के दौरान आजमाए गए थे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब छह-सात मई की रात को आपरेशन सिंदूर से दिया था। इसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था-भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों को उनकी करतूतों का सबक सिखाना और यह बताना था कि पाकिस्तान का हर एक आतंकी ढांचा भारत की मारक क्षमता के दायरे में है। आपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने उजागर करने के लिए कूटनीतिक अभियान के तहत प्रमुख देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इस एक वर्ष के बीच वैश्विक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। इसके बावजूद, स्पष्ट है कि आतंकवाद की निंदा के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खास मतभेद नहीं है।

पहलगाम हमले के बाद जारी बयानों में भी यही झलका था कि नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है, फिर भी यह वैचारिक स्पष्टता उन आतंकी ढांचों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई में तब्दील नहीं हो पाई है, जो ऐसे हमलों को बढ़ावा देते हैं। खासतौर से तब यह और अखरता है, जब ऐसे ढांचों का पूरा तंत्र पाकिस्तान में स्पष्टता से दिखाई देता हो और वे कार्रवाई से बचे रह जाएं। पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में जिन नेटवर्कों की पहचान की गई, वे उसी ढांचे का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तानी इलाकों में एक सुसंगठित सहायता तंत्र के दायरे में संचालित होते हैं। इसमें प्रशिक्षण सुविधाएं, वित्तीय सहायता, भर्ती के रास्ते और वैचारिक समर्थन जैसे पहलू शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में विभिन्न जांचों में इन तत्वों को बार-बार प्रमाणित किया गया है। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान पर इस बात के लिए निरंतर दबाव बनाने को लेकर व्यापक रूप से परहेज ही किया गया है कि वह इन नेटवर्कों को चिह्नित कर उन्हें ध्वस्त करे। ऐसे ढांचों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई के मोर्चे पर अंतर की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है और उसमें एक चिरपरिचित रुझान भी नजर आता है। प्रत्येक बड़े आतंकी हमले के बाद कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। उसके बाद साक्ष्य साझा करने के साथ एकजुटता प्रदर्शित की जाती है। हालांकि, ऐसी प्रतिक्रियाएं किसी स्थायी समाधान का निमित्त नहीं बन पातीं, जिनसे भावी आतंकी हमलों पर अंकुश लग सके। इसका यही परिणाम होता है कि किसी हमले को अंजाम देने के बाद वही आतंकी ढांचे नई पहचान के साथ नए सिरे से फिर सक्रिय हो जाते हैं।

आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया आतंकी ठिकाना। फाइल

शक्तिशाली देशों के आचरण में आतंकवाद को लेकर विसंगति उनके व्यवहार में भी झलकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी, पर अब उनका नजरिया बदला हुआ एवं अस्थिर है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सहित वहां के नेतृत्व के साथ उनकी हालिया करीबी उसी वैचारिक बदलाव को दर्शाती है, जहां आतंक से निपटने की जवाबदेही तय करने के बजाय निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। आतंकी नेटवर्कों के साथ पाकिस्तान के पुख्ता संबंधों के बावजूद उसे कूटनीतिक समर्थन देकर अमेरिका अब उन्हीं प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा है, जिसकी वह खुद निंदा करता आया है। यह रवैया भी किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। तमाम अंतरराष्ट्रीय किरदार ऐसा ही दोहरा रवैया दिखाते हैं। एक ओर तो वे आतंक को वैश्विक खतरे के रूप में मान्यता देते हुए पीड़ितों का समर्थन करते हैं तो दूसरी ओर भू-राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए पाकिस्तान पर किसी भी सीधी कार्रवाई से न केवल संकोच करते हैं, बल्कि उस पर दबाव बनाना भी उचित नहीं समझते।

आधिकारिक रुख के साथ-साथ मानवाधिकार संगठनों और नीतिगत विश्लेषकों के बीच भी एक समानांतर विमर्श जारी है। हालांकि यह मुख्यतः शासन और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे विषयों पर केंद्रित होता है, लेकिन यह अक्सर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका देता है। यह स्थिति विमर्श को न केवल जटिल बनाती है, बल्कि जवाबदेही की मूल समस्या के समाधान में कोई योगदान भी नहीं देती। इस तरह देखा जाए तो पहलगाम हमला आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में व्याप्त एक ढांचागत समस्या को दर्शाता है।

हिंसक आतंकी घटनाओं को चिह्नित करने और उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के स्तर पर तो स्पष्टता दिखाई देती है, लेकिन जब उस हिंसा के स्रोत के रूप में पाकिस्तान जैसे देश सामने आते हैं, तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। यह हिचकिचाहट पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्कों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपना संचालन जारी रखने का अवसर एवं गुंजाइश प्रदान करती है।

भारत का लंबे अर्से से यही रुख रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई केवल तात्कालिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वित्तीय स्रोतों पर अंकुश, परिचालन संबंधी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और वैचारिक समर्थन तंत्र को चुनौती देने वाले समग्र एवं निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। आपरेशन सिंदूर की संकल्पना यही थी कि इसमें केवल हमलावरों को उनकी करनी का सबक ही नहीं सिखाना, बल्कि उनकी जड़ों पर प्रहार करना था। अब जब पहलगाम हमले को साल भर बीत गया है, तब आतंक के विरुद्ध वैश्विक सैद्धांतिक रुख भले ही यथावत कायम हो, लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर वह खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि तमाम साक्ष्यों के बावजूद पाकिस्तानी आतंकी ढांचा जस का तस कायम है। जब तक ऐसे ढांचों को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक पहलगाम जैसे आतंकी हमलों का खतरा बना रहेगा। समाधान केवल समस्या को पहचानने में नहीं, बल्कि उसका निदान करने से ही संभव है।

(लेखक सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

# फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल

राजीव सचान

**अब यह फ्राड नहीं चलेगा कि मुस्लिम गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति है, मगर हिंदुओं को गोलबंद करना सांप्रदायिक**

पांच राज्यों के चुनावों में से राहुल गांधी को असम और बंगाल के चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं हैं। उनके शब्दों में, 'असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं, जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चुराया है। हम ममता बनर्जी से सहमत हैं कि बंगाल में सौ से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तरीका देखा है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी-अब और चारा ही क्या है।' आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। केरलम के बारे में तो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे ने जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने तमिलनाडु में शानदार जीत हासिल करने वाले टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय को बधाई दी तो पराजय का सामना करने वाले स्टालिन से भी बात की। ज्ञात हो स्टालिन ने चुनाव नतीजों को सहजता से स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से भी बात की और अपनी एक्स पोस्ट में कांग्रेस के उन लोगों को संभलने की सलाह दी, जो टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे। यह वही राहुल गांधी हैं, जिन्होंने बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले ममता को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर टीएमसी में कोई न कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं मिलने वाला। ममता पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों और अपनी पार्टी के लोगों के लिए करती हैं और जनता की कोई भी मदद नहीं करतीं। उन्होंने यह भी कहा था, बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है।

आखिर राहुल अपनी ही बातों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? राहुल ने बंगाल में प्रचार के दौरान ही ममता को लेकर यह भी कहा था कि बंगाल में बढ़ते ध्रुवीकरण की वजह से ही भाजपा को मौका मिला। इससे इन्कार नहीं कि बंगाल में भाजपा की जीत के कई कारणों में से एक मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी रहा। इस निष्कर्ष पर

भारी पड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। फाइल

पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता गोलबंद हुए और इसलिए भी उसे बंपर जीत मिली, पर ऐसा केवल इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल सरीखे दल कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का काम करते हैं। वास्तव में यह काम खुद को सेक्युलर बताने वाले अधिकतर दल करते हैं। कांग्रेस देश भर में यही करती है और बंगाल में ममता भी यही कर रही थीं और इतना खुलकर कर रही थीं कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण में बदल गया।

आम तौर पर मुस्लिम किसी दल के पक्ष में थोक वोट करते हैं और जबसे भाजपा का उभार हुआ है, तबसे वे खास तौर पर उस दल के पक्ष में वोट करते हैं, जो उसे हरा सकने में सक्षम दिखता है। इसके चलते कथित सेक्युलर दल उनकी गोलबंदी में अतिरिक्त परिश्रम करने लगे। वे उनके सामने भाजपा का हौवा खड़ा करते और उनका काम आसान हो जाता। मुस्लिम वोटों की इस गोलबंदी को ध्रुवीकरण के बजाय सेक्युलर राजनीति की संज्ञा दी जाने लगी। इस फर्जी सेक्युलर राजनीति के चलते एक समय ऐसा आया कि भाजपा विरोधी दलों के लिए मुस्लिम वोट एक तरह के वीटो पावर बन गए। जब भाजपा ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के जवाब में हिंदू वोटों को गोलबंदी करनी शुरू की तो उसके विरोधियों ने उस पर ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति करने ठप्पा लगाना शुरू किया। भाजपा ने इसकी परवाह न करते हुए सेक्युलरिज्म को छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा दी और वह उस पर इसलिए बुरी तरह चिपक गया, क्योंकि यही सच था।

निःसंदेह बंगाल में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के कारण भी टीएमसी को नुकसान हुआ, लेकिन यदि ममता मुस्लिम समुदाय का इतना खुला तुष्टीकरण नहीं करतीं तो हिंदू भाजपा के पक्ष में खुलकर गोलबंद नहीं होते। ममता केवल इसलिए नहीं हारीं, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और अधिसंख्य हिंदू वोट भाजपा के खाते में चले गए। वे इसलिए भी हारीं, क्योंकि उनका शासन पक्षपात और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार संग उनकी गुंडागर्दी का पर्याय बन गया था। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी राज्य में महिला असुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना। ममता को घुसपैठियों की अनदेखी और मुस्लिमपरस्ती की भी कीमत चुकानी पड़ी। यही कीमत असम में कांग्रेस ने चुकाई। इस पर गौर करें कि असम में एक समय कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने वाले बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग बता दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब यह फ्राड बंद होना चाहिए कि मुसलमानों की गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति है और उसके जवाब में हिंदुओं को एकजुट करना सांप्रदायिक राजनीति। मुस्लिम वोटों ने असम और बंगाल में भी अपना वीटो पवार खो दिया और यह मिथ्या धारणा ध्वस्त हो गई कि उनके वोट किसी दल की चुनावी नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि उनका ध्रुवीकरण रिवर्स ध्रुवीकरण करता है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

## त्रिविध ताप

संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। दुखों की भी प्रकृति होती है। दुख शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। दुखों से मुक्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपितु दुखों को पढ़ना, समझना, उनका विवेचन करना, उन्हें आत्मसात करना तथा उनके द्वारा अपने को तपाना जीवन का उद्देश्य है। अध्यात्म में दुखों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे 'त्रिविध ताप' की संज्ञा दी गई है। इन तीन तापों को आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक कहा गया है।

आध्यात्मिक ताप वह कष्ट है जो स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है। इसमें मानसिक अशांति, भ्रम, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि सम्मिलित हैं। मनुष्य का मन जब अस्थिर होता है, तब वह स्वयं अपने लिए दुख का कारण बन जाता है। यह ताप सबसे सूक्ष्म और गहरा है, क्योंकि इसका स्रोत बाहरी नहीं, अपितु आंतरिक होता है। आत्म-अज्ञान ही इसका मूल कारण माना गया है। आधिभौतिक ताप बाहरी भौतिक जगत से उत्पन्न होता है। इसमें अन्य प्राणियों, मनुष्यों, पशु-पक्षियों अथवा वस्तुओं से मिलने वाले कष्ट सम्मिलित हैं। जैसे दुर्घटनाएं, हिंसा, शत्रुता, या सामाजिक संघर्ष। यह ताप मनुष्य के पारस्परिक संबंधों और भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। आधिदैविक ताप उन कष्टों को संदर्भित करता है जो दैवीय या प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी आदि। ये वे स्थितियां हैं, जिन पर मनुष्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता और जिनका अनुभव उसे प्रकृति या दैविक व्यवस्था के अधीन होकर करना पड़ता है। त्रिविध ताप में केवल कष्टों का वर्गीकरण नहीं, बल्कि जीवन को समझने का सहज मार्ग भी निहित है। भारतीय चिंतन के अनुसार ज्ञान, साधना और आत्मबोध के माध्यम से इन तापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

द्विंकल तोमर सिंह

# 'वैश्विक जल दिवालियापन' का खतरा

सुधीर कुमार

**'जल दिवालियापन' एक ऐसी स्थिति हैं, जहां पानी का उपभोग जल धारण क्षमताओं से कहीं अधिक हो रहा हैं**

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया 'जल दिवालियापन' के कगार पर पहुंच चुकी है। यह एक ऐसी स्थिति है, जहां पानी का उपभोग जल धारण क्षमताओं से कहीं अधिक हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप न केवल जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, बल्कि 'डे-जीरो' परिघटना, प्रवासन और सामाजिक अशांति उत्पन्न होने का खतरा भी मंडराने लगा है।

पानी मानवता के हरेक दिन के गुजारे के लिए अनिवार्य तत्व है। हालांकि कभी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और निःशुल्क उपलब्ध पानी की निर्ममता से की गई बर्बादी के कारण पानी की उपलब्धता, उपभोग और उसके पुनर्भरण के बीच असंतुलन व्याप्त हो गया। वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी की पानी की आवश्यकता पर मंडराते संकट का यह एक सर्वप्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन, भूजल के दोहन, जल संचयन में शिथिलता, प्रदूषण के कारण न केवल नदियां, झीलें और अन्य जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, बल्कि उसकी जलधारण क्षमता भी घटती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक दुनिया की आधे से अधिक बड़ी झीलों का जलस्तर घट चुका है, जबकि साल 1970 के बाद से लगभग 35 प्रतिशत प्राकृतिक आर्द्रभूमियां समाप्त हो चुकी हैं। स्वच्छ पानी की कमी पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुका है। दुनियाभर में तकरीबन दो अरब लोग स्वच्छ एवं सुरक्षित जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, दुनिया की लगभग तीन-चौथाई आबादी ऐसे देशों में रहती है, जिन्हें जल-असुरक्षित या गंभीर रूप से जल-असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।

वहीं लगभग चार अरब लोग हर साल कम से कम एक महीने के लिए गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। पानी की उपलब्धता प्रभावित होने से मानव जीवन के साथ-साथ स्वास्थ्य और आजीविका पर भी संकट मंडराने लगता है। पानी की कमी और सूखे का आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है। इस संकट के कारण हर वर्ष 307 अरब डालर की आर्थिक चपत लगती है। पेयजल संकट से भारत भी अछूता नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की कमी हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में इस वर्ष के दिसंबर में प्रस्तावित है। पानी की कमी एक ऐसा संकट है, जिससे मानव के साथ-साथ वन्यजीव और वनस्पति भी प्रभावित होता है। हालांकि इससे निपटने के लिए मानव को ही प्रयत्न करने होंगे। अतः आवश्यक है कि सम्मेलनों के आयोजन के साथ-साथ पानी की बर्बादी को रोकने और वर्षा जल संचयन की आदत को परंपरा बनाया जाए।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

## मेलबाक्स

### अपेक्षित प्रभाव भी दिखाएं परिणाम

'राष्ट्रीय राजनीति को बदलने वाले नतीजे' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राहुल वर्मा ने हालिया चुनाव परिणामों को भारतीय राजनीति के नए मोड़ के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां गठबंधन की वापसी, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और मतदाता के बदले रुझान को रेखांकित किया गया है। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है, परंतु इससे आगे बढ़कर कुछ बुनियादी प्रश्नों पर भी विचार आवश्यक है। चुनाव परिणाम केवल सत्ता के समीकरण नहीं बदलते, बल्कि वे शासन की दिशा और प्राथमिकताओं का भी संकेत देते हैं। फिर भी, बहस अक्सर यहीं थम जाती है कि किसे कितनी सीटें मिलीं। असली मुद्दा यह है कि क्या इन बदलावों से आम नागरिक के जीवन में ठोस सुधार होगा? एक ओर विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर रोजगार, ट्रैफिक और बुनियादी सेवाओं की चुनौतियां कायम रहती हैं। यह अंतर बताता है कि राजनीतिक विमर्श और जमीनी सच्चाई के बीच खाई अभी भी गहरी है। एक और पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, वह है स्थानीय नेतृत्व की जवाबदेही। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन वार्ड और नगर स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना कठिन है। जब तक नीतियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा और स्थानीय निकायों को वास्तविक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। समाधान के तौर पर राजनीतिक दलों को घोषणापत्रों को केवल वादों का दस्तावेज न बनाकर, उन्हें समयबद्ध कार्ययोजना में बदलना होगा। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, डाटा-आधारित नीति निर्माण और पारदर्शिता को अनिवार्य करना होगा। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है, जब चुनाव नतीजे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता में भी बदलाव लाएं। परिणाम तभी सार्थक होंगे, जब वे अपेक्षित प्रभाव भी दिखाएं।

awanishg30@gmail.com

### बाय बाय तुष्टीकरण

भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण की नीति कोई नई नहीं है, लेकिन जब यह अपनी सीमाएं लांघ जाती है तो उसका परिणाम सत्ता के क्षरण के रूप में सामने आता है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दिया, वह मूलतः उसी ढांचे की उग्र अभिव्यक्ति थी जिसे कांग्रेस ने दशकों पहले स्थापित किया था-एक विशेष वोटबैंक को केंद्र में रखकर सत्ता की रणनीति बनाना। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस नीति को "संतुलन" के आवरण में चलाया, लेकिन तृणमूल ने इसे खुलकर अपनाया। नतीजा यह हुआ कि तुष्टीकरण एक रणनीति न रहकर पहचान बन गया। जब राजनीति पहचान पर टिक जाती है, तो प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होती है। बंगाल में यही देखने को मिला-जहां एक समय सर्वग्राही दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस धीरे-धीरे एक सीमित वर्ग तक सिमटती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में यह स्पष्ट संकेत मिला कि बहुसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अपने राजनीतिक विकल्प बदल रहा है। भाजपा का बंगाल में तेज उभार केवल संगठनात्मक विस्तार का परिणाम नहीं था, बल्कि उस असंतोष का राजनीतिक रूपांतरण था जो वर्षों से पनप रहा था। यह वही स्थिति थी, जब मतदाता केवल सरकार नहीं बदलता, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई रेखा खींच देता है। यही पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने भी लंबे समय तक एक विशेष वोटबैंक पर आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। 2012 से 2017 के बीच के शासनकाल में कानून-व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव और प्रशासनिक पक्षपात के आरोपों ने एक बड़ी आबादी के भीतर असंतोष पैदा किया। इसका परिणाम 2017 में सामने आया, जब भाजपा ने अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि संदेश था कि मतदाता तुष्टीकरण की राजनीति को अस्वीकार कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति तात्कालिक लाभ तो दे सकती है, दीर्घकाल में यह आत्मघाती सिद्ध होती है।

सुशील कुमार बतरा, मेरठ

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें:**
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

राष्ट्रीय संस्करण

बुधवार, 6 मई, 2026

दैनिक जागरण

# बिजनेस

## काफी निर्यात जनवरी-अप्रैल में 27 प्रतिशत बढ़ा

**नई दिल्ली:** देश का काफी निर्यात 2026 की जनवरी-अप्रैल अवधि में 26.6 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख टन रहा। इसकी मुख्य वजह रोबस्टा और इंस्टेंट काफी के निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। पिछले साल इसी अवधि में देश ने 1.37 लाख टन कॉफी का निर्यात किया था। भारत अरेबिका और रोबस्टा किस्मों के साथ-साथ इंस्टेंट काफी का भी निर्यात करता है। मूल्य के हिसाब से, कुल निर्यात एक साल पहले के 757.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 936.57 करोड़ रुपये हो गया। (प्रेट्र)

पश्चिम एशिया संघर्ष ने ऊर्जा संकटों के प्रति भारत की ढांचागत कमजोरी को उजागर किया है। ऐसे में आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत बढ़ गई है।

**– नागेश कुमार, एमपीसी सदस्य**

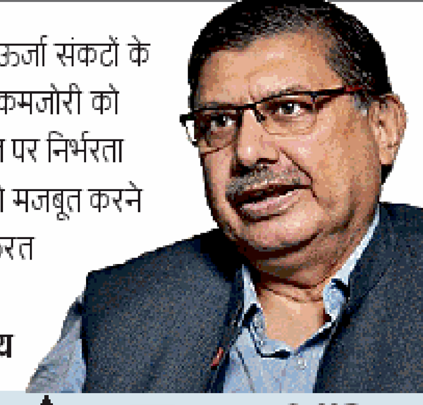

| | | | |
|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 77,017.79 | ▼ | 251.61 |
| निफ्टी | 24,032.80 | ▼ | 86.50 |
| सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 1,52,500 | ▼ | ₹ 300 |
| चांदी प्रति किलो ग्राम | ₹ 2,51,000 | ▲ | ₹ 1,500 |
| डालर | ₹ 95.18 | ▼ | ₹ 0.05 |
| क्रूड प्रति बैरल | $ 113 | | |

## एक नजर में

### प्रमोटर इकाई ने अदाणी पोर्ट का दो प्रतिशत हिस्सा बेचा

**नई दिल्ली :** प्रमोटर समूह की इकाई ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनमिक जोन की दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। यह हिस्सेदारी खुला बाजार लेनदेन के जरिये 7,486 करोड़ रुपये में बेची गई है। बीएसई पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, अदाणी पोर्ट्स के प्रमोटर समूह की इकाई वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड ने यह हिस्सेदारी अमेरिका के कैपिटल ग्रुप को बेची है। यह सौदा 1,632.45 रुपये प्रति शेयर पर हुआ है और प्रमोटर इकाई ने कुल तीन किस्तों में 4,58,58,705 शेयरों की बिक्री की है। (प्रेट्र)

### 14 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करेगा क्वाइनबेस

**नई दिल्ली :** क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइनबेस ने मंगलवार को कहा कि वह अपने 14 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इसका कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) लोगों के काम करने के तरीके को बदल रहा है। कंपनी ने कहा कि प्रभावित सभी टीम सदस्यों को उनके पर्सनल अकाउंट पर ज्यादा जानकारी के साथ एक ईमेल मिलेगा। एक्सचेंज के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक्स पोस्ट में कहा, आज मैंने क्वाइनबेस का आकार 14 प्रतिशत तक कम करने का कठिन निर्णय लिया है। (आइएएनएस)

### महिंद्रा एंड महिंद्रा का शुद्ध लाभ 48.5 प्रतिशत बढ़ा

**नई दिल्ली :** महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मंगलवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में उसका शुद्ध लाभ 48.5 प्रतिशत बढ़कर 5,259.91 करोड़ रुपये रहा है। इसमें आटो और कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। जनवरी-मार्च 2025 में कंपनी को 3,541.85 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बीती तिमाही के दौरान कंपनी का संचालन राजस्व 54,891.55 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 42,585.67 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 33 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। (प्रेट्र)

# अप्रैल में 26 लाख से ज्यादा वाहनों की खुदरा बिक्री

## जीएसटी में कटौती, रेपो रेट में नरमी और मजबूत रबी फसल ने आटोमोबाइल उद्योग को दी रफ्तार

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** देश में मोटर वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अप्रैल में 12.94 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 26,11,317 इकाई रही जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 23,12,221 यूनिट थी। उद्योग संगठन 'फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' (फाडा) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी में कटौती, आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में नरमी, मजबूत रबी फसल के बाद ग्रामीणों के हाथ में आए पैसे जैसे सकारात्मक कारकों ने उद्योग को मजबूत प्रदर्शन में मदद की।

यात्री वाहन (पीवी) की खुदरा बिक्री पिछले महीने रिकार्ड 4,07,355 इकाई रही जो अप्रैल 2025 के 3,63,028 इकाइयों की तुलना में 12.21 प्रतिशत अधिक है। दोपहिया वाहनों की बिक्री भी अप्रैल में अब तक के सर्वाधिक मासिक स्तर 19,16,258 इकाइयों पर पहुंच गई। यह पिछले वर्ष के इसी महीने की 16,95,638 इकाइयों की तुलना में 13.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। तिपहिया वाहनों की बिक्री अप्रैल 2025 की 99,741 इकाइयों के मुकाबले 7.19 प्रतिशत बढ़कर 1,06,908 इकाई पर पहुंच गई। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी अप्रैल 2025 के 86,364 इकाइयों से 15.02 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकार्ड 99,339 इकाई रही। अगले तीन महीनों के परिदृश्य पर फाडा ने कहा कि लगभग 51 प्रतिशत डीलर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

भारतीय मोटर वाहन खुदरा उद्योग ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है। छह में से पांच वाहन श्रेणियों में अप्रैल में अब तक के सर्वोच्च रिकार्ड दर्ज किए गए, जो यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में दिखी संरचनात्मक मांग नए वित्त वर्ष में भी जारी है।

**– साई गिरधर**, वाइस प्रेसिडेंट, फाडा

### बिक्री पर प्रभाव डाल सकती है पश्चिमी एशिया की स्थिति

मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कई राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी की भविष्यवाणी, पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति और ईंधन कीमतों पर संभावित प्रभाव तथा कुछ माडल की आपूर्ति में बाधाएं दोपहिया खंड के लिए जोखिम कारक हैं। पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के अलावा वाणिज्यिक वाहन खंड में नकदी भी एक महत्वपूर्ण कारक रहेगी, जिस पर नजर रखनी होगी।

### तिपहिया वाहन सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी 60.38%

**नई दिल्ली, एएनआइ :** पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के चलते ईंधन कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव का असर वाहनों की मांग पर दिखाई दिया। फाडा के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी का रुझान दिखाई दिया। तिपहिया वाहन सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी 60.38 प्रतिशत तक हो गई है। यात्री वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर 5.77 प्रतिशत हो गई जबकि दोपहिया श्रेणी में यह हिस्सेदारी 7.76 प्रतिशत रही। मार्च दोपहिया वाहनों हिस्सेदारी 9.79 प्रतिशत थी। ईवी इंसेंटिव बंद होने से पहले हुई तेज खरीदारी के चलते मार्च का आंकड़ा ज्यादा बढ़ा दिखाई दे रहा है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

## आइफोन-17 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन

- वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन बिक्री में आइफोन-17 की हिस्सेदारी छह प्रतिशत रही
- स्मार्टफोन बिक्री में शीर्ष 10 में शामिल माडल की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत रही

**नई दिल्ली, आइएएनएस:** एपल का आइफोन-17 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा। वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन बिक्री में इसकी हिस्सेदारी छह प्रतिशत रही। काउंटरप्वाइंट रिसर्च के मुताबिक, स्मार्टफोन की सूची के पहले 10 स्थानों में से तीन पर आइफोन-17 के विभिन्न माडल रहे। पांच माडल के साथ सैमसंग गैलेक्सी-ए सीरीज की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही।

जनवरी-मार्च 2026 के दौरान वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन बिक्री में शीर्ष 10 में शामिल माडल की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत रही। काउंटरप्वाइंट के वरिष्ठ विश्लेषक हर्षित रस्तोगी ने कहा कि आइफोन-17 अपने पिछले माडल से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा बेस स्टोरेज, बेहतर कैमरा रेजोल्यूशन और बेहतर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जैसे खास अपग्रेड हैं, जिससे यह प्रो वेरिएंट के करीब आ गया है। आइफोन ने चीन और अमेरिका जैसे बाजार में साल-दर-साल दो अंकों की वृद्धि दर्ज की और दक्षिण कोरिया में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे उभरते बाजार में मजबूत मांग के चलते एंड्रायड डिवाइस में सैमसंग का गैलेक्सी ए07 4जी सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बना। बेहतर साफ्टवेयर और सिक्योरिटी सपोर्ट ने वैल्यू फोकस्ड खरीदारों के बीच इसकी मांग को बढ़ाया।

उधर, साइबरमीडिया रिसर्च ने अनुमान जताया कि चिप की कीमत बढ़ने से 2026 में भारत में स्मार्टफोन बिक्री में 10-12 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

## आयातित रेंज रोवर के मूल्य में 75 लाख रुपये तक की कटौती

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** जेएलआर इंडिया ने मंगलवार को ब्रिटेन से पूरी तरह से निर्मित आयातित रेंज रोवर के मूल्य में 75 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की। टाटा समूह की इस कंपनी ने भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने से पहले ही यह कदम उठाया है। कंपनी ने कहा कि एफटीए से लाभान्वित होने वाले प्रमुख माडल रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी हैं।

कंपनी ने बताया कि इस कटौती के बाद भारत में रेंज रोवर एसवी की कीमत 4.25 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ रुपये (शुरुआती कीमत, एक्स-शोरूम) और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की कीमत 2.75 करोड़ रुपये से घटाकर 2.35 करोड़ रुपये हो गई है। इससे बाजार में इसकी स्थिति काफी मजबूत हुई है। संशोधित कीमतें एफटीए के तहत लागू नई ड्यूटी संरचना को दर्शाती हैं और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

## निफ्टी-500 में डीआइआइ ने एफआइआइ को पीछे छोड़ा

Nifty500

**मार्च, 2026 में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी रिकार्ड 21% हुई, एफआइआइ की हिस्सेदारी 17.1 प्रतिशत पर आई**

**मुंबई, आइएएनएस:** भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। मार्च, 2026 में निफ्टी500 कंपनियों में डीआइआइ की हिस्सेदारी रिकार्ड 20.9 प्रतिशत तक पहुंच गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार आठवीं तिमाही में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। साल-दर-साल आधार पर हिस्सेदारी में 170 आधार अंकों की वृद्धि हुई है जबकि तिमाही आधार पर 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की हिस्सेदारी 17.1 प्रतिशत के नए निचले स्तर पर आ गई है।

निफ्टी 500 में एफआइआइ-डीआइआइ का अनुपात अब घटकर 0.8 गुना रह गया है। यह एक ऐसा स्तर है, जो भारत के शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है, उसका संकेत देता है। एमओएफएसएल के अनुसार, डीआइआइ की मजबूती के पीछे मुख्य चालक एसआइपी के माध्यम से लगातार निवेश आना रहा है। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही में, घरेलू कंपनियों ने भारतीय इक्विटी में 27.2 अरब डालर का निवेश किया जबकि विदेशी निवेशकों ने 15.8 अरब डालर निकाले। विदेशी निवेशकों ने अकेले 14.2 अरब डालर मार्च में निकाले। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार जब पश्चिम एशिया में शांति आ जाएगी तो एफआइआइ निवेश का माहौल बेहतर होने की संभावना है।

# बैंकिंग सेक्टर पर वित्त मंत्रालय व मैकेंजी का अलग-अलग दावा

- वित्त मंत्रालय ने उद्योग के मौजूदा दौर को पिछले कई दशकों का सबसे शानदार समय बताया
- कंसल्टेंसी फर्म ने कहा- बैंकिंग सेक्टर ऐसे मोड पर पहुंचा, जहां से नीचे जाने का खतरा

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली:** भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। फंसे कर्ज (एनपीए) रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर हैं। वित्त मंत्रालय ने इस आधार पर मंगलवार को बैंकिंग उद्योग के मौजूदा दौर को पिछले कई दशकों का सबसे शानदार करार दिया। लेकिन इसी दिन वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी ने चेतावनी दी कि अब मुनाफा बढ़ाना और मार्जिन बनाए रखना भारतीय बैंकिंग के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दोनों रिपोर्टों के बीच का यह विरोधाभास भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत रही, जो पिछले साल के 10.9 प्रतिशत से 497 आधार अंक की भारी बढ़ोतरी है। कुल ऋण बकाया मार्च 2026 तक 212.9 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 29.2 लाख करोड़ रुपये अधिक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ऋण वृद्धि 15.7 प्रतिशत (पिछले साल 10.4), उद्योग क्षेत्र में 15 प्रतिशत (पिछले साल 8.2), सेवा क्षेत्र में 19 प्रतिशत (पिछले साल 12) और व्यक्तिगत ऋणों में 16.2 प्रतिशत (पिछले साल 11.7) की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंत्रालय ने इसे आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और निजी निवेश में उछाल का नतीजा बताया और कहा है कि कम ब्याज दर वातावरण, सरकारी पूंजीगत खर्चे में वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों ने निजी निवेश को बढ़ावा दिया है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है और बैंकिंग सेक्टर ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम फंसे कर्जे और पर्याप्त पूंजी के साथ अर्थव्यवस्था का इंजन बनकर उभरा है।

**बैंकों को जमा जुटाने के लिए देना पड़ रहा ज्यादा ब्याज :** मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से आगे नीचे जाने का खतरा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) के 1.4 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (निम) 3.3 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया है। ऋण-जमा अनुपात दशक के उच्चतम स्तर 80 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जिससे बैंक महंगे टर्म डिपाजिट की ओर मजबूर हो रहे हैं। यानी बैंकों को जमा जुटाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। मैकेंजी का यह भी कहना है कि असुरक्षित रिटेल लोन में कर्ज अदाएगी में गड़बड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। पर्सनल लोन में एनपीए 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 1.6 प्रतिशत और क्रेडिट कार्ड एनपीए 2.2 से 3.3 प्रतिशत हो गया है। परिचालन खर्च तेजी से बढ़ रहा है, खासकर प्राइवेट बैंकों में, लेकिन आय में उतनी वृद्धि नहीं हो रही।

**रेगुलेटरी बदलाव और टेक्नोलाजी के बीच संतुलन बनाना चुनौती:** मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटरी बदलाव, ग्राहक व्यवहार और तेज टेक्नोलाजी को अपनाने के बीच संतुलन बनाना अब चुनौती है। मैकेंजी ने पांच आयामों वित्तीय प्रदर्शन, उद्योग स्वास्थ्य, ग्राहक अनुभव, सामाजिक प्रभाव और परिचालन लचीलापन पर बैंकिंग सेक्टर का मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि बैंकों को अब केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन, लागत अनुशासन, साइबर सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान देना होगा। जाहिर है कि रिपोर्ट बैंकिंग के मौजूदा सुनहरे दौर के चुनौतीपूर्ण दौर में बदलने को लेकर सचेत कर रहा है।

## राष्ट्रीय फलक

# नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी

- सीबीआइ ने हाई कोर्ट के निर्णय को शीर्ष अदालत में दी चुनौती
- हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद करते हुए हुड्डा को दी थी राहत

**राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़**

पंचकूला स्थित नेशनल हेराल्ड प्लाट आवंटन मामले में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सीबीआइ द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद शीर्ष अदालत ने हुड्डा को नोटिस जारी किया है।

फरवरी 2026 में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि रिकार्ड पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपितों ने कोई अपराध किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई निर्णय नीति या दिशा-निर्देशों के विपरीत लिया गया हो, तो मात्र इसी आधार पर उसे भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को रद कर दिया गया और पूरे मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इसके बाद सीबीआइ की विशेष अदालत और ईडी की अदालत ने भी अपने-अपने केस बंद कर दिए थे।

सीबीआइ की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में गंभीर खामियां छोड़ी हैं। जांच एजेंसी ने दलील दी कि उपलब्ध साक्ष्यों से भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनता है।

### यह है मामला

इस मामले की जड़ें पंचकूला के सेक्टर-6 में स्थित प्लाट नंबर सी-17 से जुड़ी हैं। यह जमीन मूल रूप से एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड (एजेएल) को 1982 की दरों पर 'नो-प्राफिट, नो-लास' आधार पर दी गई थी, ताकि वहां अखबार का प्रकाशन शुरू हो सके, लेकिन निर्माण नहीं होने से 1996 में यह प्लाट वापस ले लिया गया। विवाद तब खड़ा हुआ, जब वर्ष 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी प्लाट को दोबारा पुरानी दरों पर एजेएल को आवंटित किया गया। एजेंसियों का आरोप है कि यह पुन: आवंटन नियमों के खिलाफ था और इससे राज्य सरकार को 1.75 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी ने दावा किया कि एजेएल ने इस जमीन को स्वच्छ संपत्ति दिखाकर करीब 72.57 करोड़ के ऋण हासिल किए और बाद में संपत्तियां बनाईं।

## अब यूपीएससी नतीजों में दिखेगी उप-जाति की झलक

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में अब एक बड़ा और पारदर्शी बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक महत्वपूर्ण सिफारिश भेजी है। इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अंतिम चयन परिणामों में केवल मुख्य श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी) का ही जिक्र न हो, बल्कि अभ्यर्थियों की उप-जाति का विवरण भी शामिल किया जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण और 'सकारात्मक कार्रवाई' का लाभ वास्तव में उन वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं, जो अब भी हाशिए पर हैं।

यह मामला तब सामने आया जब आरटीआइ आवेदक ने 1995 की सिविल सेवा में चयनित आइएएस की जाति-वार जानकारी मांगी थी।

## व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ करेंगे भारत और जमैका : जयशंकर

- विदेश मंत्री ने जमैका की समकक्ष के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता
- स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा और प्रसारण के क्षेत्रों में तीन समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

**किंग्स्टन, प्रेट्र:** विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जमैका व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। स्वास्थ्यकर्मियों और शिक्षकों समेत कुशल पेशेवरों की भर्ती व दोनों देशों में उनके आवागमन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर सहमत भी हुए हैं। जयशंकर इस कैरेबियाई देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। वह जमैका, सूरीनाम व त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी नौ दिवसीय यात्रा के तहत शनिवार को किंग्स्टन पहुंचे।

जयशंकर ने सोमवार को जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस से मुलाकात की और फिर विदेश व व्यापार मंत्री कामिना जानसन स्मिथ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्मिथ के साथ संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि व्यापक चर्चा हुई और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए नए रास्ते भी तलाशे गए। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

किंग्सटन में मंगलवार को यूनिवर्सिटी आफ वेस्ट इंडीज मोना कैंपस में संबोधित करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

## बैंकों के अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े नियमों का मसौदा जारी

**मुंबई, प्रेट्र:** आरबीआइ ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा कर्ज वसूली के तौर पर अचल संपत्ति के अधिग्रहण के नियम तय करने के लिए मसौदा जारी किया है। इन नियमों का उद्देश्य स्पष्टता लाना और अचल संपत्तियों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करना है।

26 मई तक आम लोग आरबीआइ के इस मसौदे पर अपनी राय दे सकते हैं। दरअसल, बैंक सामान्यतः अचल संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करते हैं। हालांकि, जब कोई कर्ज एनपीए बन जाता है और कानूनी उपाय काम नहीं आते हैं तो बैंक रिकवरी के लिए अचल संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। इन संपत्तियों को रखने की अधिकतम अवधि सात साल प्रस्तावित की गई है। जोखिम को कम करने को बैंक अधिग्रहित अचल संपत्ति को मूल उधारकर्ता या उससे संबंधित पक्ष को नहीं बेच पाएंगे।

## बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार ने भतीजी क्लेयर को बनाया उत्तराधिकारी

**नई दिल्ली, आइएएनएस:** भारत की प्रमुख बायोटेक्नोलाजी कंपनी बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार शा ने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। फार्च्यून इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में 73 वर्षीय मजूमदार ने कहा कि वह क्लेयर (37) को बायोकान की वृद्धि को अगले चरण में ले जाने के लिए सही व्यक्ति मानती हैं।

उन्होंने कहा, "मैं बायोकान की अकेली मालकिन हूं और मुझे यह पक्का करना है कि मैं इसे अच्छे हाथों में सौंपूं। मैंने अपनी भतीजी क्लेयर को अपना उत्तराधिकारी इसलिए बनाया है, क्योंकि उसने साबित किया है कि वह एक कंपनी चला सकती है।" क्लेयर अभी बिकारा थेराप्यूटिक्स की संस्थापक और सीईओ हैं। नैस्डेक सूचीबद्ध इस कंपनी की स्थापना बायोकान की मदद से की गई थी।

किरण मजूमदार शा के कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा, 'एक बड़ा फैमिली इकोसिस्टम भी कंपनी की वृद्धि में मदद कर सकता है। इसमें क्लेयर के भाई एरिक मजूमदार भी हैं।

एरिक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में प्रोफेसर और एआइ विशेषज्ञ हैं।' कंपनी में बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर बायोकान ने अपने जेनरिक और बायोलाजिक्स बिजनेस का विलय कर दिया है और कर्ज को कम किया है। किरण ने कहा कि कंपनी बायोसिमिलर पर अपना फोकस बढ़ा रही है, जिसकी कंपनी के राजस्व में बड़ी भूमिका है।

किरण मजूमदार शा व क्लेयर। फाइल

# एफडीआइ प्रस्तावों का 12 सप्ताह में होगा निपटान, जारी की गई नई एसओपी

- डीपीआइआइटी ने एफडीआइ को लेकर जारी की नई एसओपी
- 2017 की एसओपी में 10 सप्ताह का समय तय किया गया था

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। नई एसओपी के अनुसार, सरकार अब एफडीआइ से जुड़े सभी आवेदनों का 12 सप्ताह में निपटान किया जाएगा। इसमें वह समय शामिल नहीं है जो आवेदक प्रस्तावों में कमियों को दूर करने या सक्षम अधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी देने में लगाते हैं। 2017 के एसओपी में एफडीआइ आवेदन के निपटान के लिए अधिकतम 10 सप्ताह का समय तय किया गया था। नई एसओपी के मुताबिक, डीपीआइआइटी को उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, जिन्हें खारिज करने का प्रस्ताव है या जिन पर सक्षम अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्तें लगाने का प्रस्ताव है। डीपीआइआइटी ने कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एफडीआइ आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। इसलिए, आवेदक को प्रस्तावों को प्रोसेस करने के लिए जरूरी किसी भी दस्तावेज की फिजिकल कापी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। डीपीआइआइटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा है जो एफडीआइ से जुड़े मामलों को देखता है।

नई एसओपी के मुताबिक, सभी आवेदनों को विदेश मंत्रालय को उसकी टिप्पणियों और मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि किसी भी प्रस्ताव पर जिन सभी मंत्रालयों और विभागों से सलाह ली जाती है उनमें आरबीआइ, गृह और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इन सभी को तय समयसीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां देनी होंगी। तय समय में टिप्पणी नहीं मिलती है तो मान लिया जाएगा कि उनके पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।

इसके अलावा सरकार ने रेयर अर्थ-मैग्नेट और प्रिंटेड सर्किट जैसे 40 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनके लिए जमीन साझा करने वाले देशों से आने वाले एफडीआइ प्रस्तावों को 60 दिन में मंजूरी दी जाएगी। भारत से जमीन साझा करने वाले देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में निवेश प्राप्त करने वाली संस्था की अधिकांश हिस्सेदारी और नियंत्रण हर समय भारत के निवासी नागरिक या संस्था के पास हो।

## बैंकों के खाताधारक उदगम पोर्टल पर खोज सकते हैं दावारहित जमा

- आरबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, कहा-पोर्टल पर अब तक 44 लाख सर्च किए गए
- मृत खाताधारक के कानूनी वारिसों को धन दिलाने वाली याचिका पर कोर्ट कर रहा था सुनवाई

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** आरबीआइ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उदगम पोर्टल पंजीकृत खाताधारक को दावारहित जमा को खोजने की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक ने यह दलील जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय विश्नोई की उस पीठ के सामने दी, जो पत्रकार सुचेता दलाल की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुचेता दलाल ने अपनी याचिका में मृत खाताधारक के कानूनी वारिसों को बैंक खाते में पड़े दावा रहित जमा के बारे में बताने के लिए एक प्रणाली बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

आरबीआइ की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उदगम पर लगभग 44 लाख सर्च किए गए हैं और यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बड़ा मुद्दा यह है कि मृतक खाताधारक के कानूनी वारिसयों को बैंक खातों में पड़े दावा रहित जमा के बारे में कैसे पता चलेगा। केंद्र की तरफ से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उन्होंने एक नया एफिडेविट तैयार किया है, जिसे कोर्ट में फाइल किया जाएगा। पीठ ने केंद्र से एक हफ्ते के अंदर संबंधित विवरण देते हुए अपडेटेड एफिडेविट फाइल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 19 मई तय कर दी। 17 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र और आरबीआइ से पूछा था कि आखिर मृतकों के बैंक खातों का विवरण उनके वारिसों को क्यों नहीं बताया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर एक नीति बनानी चाहिए।

**कल्पमेधा**

*आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं और यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें।*

*– लालबहादुर शास्त्री*

## दावे और हकीकत

देश की सभी पार्टियां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक मत से समर्थन करती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिए तैंतीस फीसद आरक्षण का विधेयक पारित कराने में भी सभी दलों की भूमिका रही। मगर महिलाओं की नुमाइंदगी के सवाल पर संजीदा दिखने वाली लगभग सभी पार्टियां क्या तब तक इस मुद्दे पर ठोस पहल नहीं करेंगी, जब तक विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहार में लागू न हो जाए? आखिर क्या वजह है कि देश में लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए जब भी चुनाव होते हैं, तो उसमें पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने को लेकर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है? गौरतलब है कि चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की ओर से जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया और उनमें जीतने वालों की जो संख्या रही, वह महिला भागीदारी के सवाल पर राजनीतिक दलों के प्रचारित सरोकार के प्रति ईमानदारी को कठघरे में खड़ा करती है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। नतीजों के मुताबिक, इन पांचों प्रदेशों कुल पांच फीसद सीटों पर ही महिलाएं चुनी गईं। इन राज्यों में अलग-अलग पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में भी अपने घोषित सरोकारों के उलट रवैया अपनाया। मसलन, पश्चिम बंगाल में दो सौ सात सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा ने सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसने सिर्फ तैंतीस सीटों पर महिलाओं को मौका दिया था। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी के 291 सीटों में से 52 महिलाओं को टिकट दिया था। नतीजतन, राज्य की कुल सीटों में से सिर्फ दस फीसद महिलाएं जीत सकीं। दूसरी ओर, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके 234 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसने सिर्फ चौबीस महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। असम में फिर से जीतने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 126 सीटों में से केवल छह महिलाओं को टिकट दिया। केरल में जीत हासिल करने वाली यूडीएफ ने सिर्फ दस महिलाओं को मौका दिया।

जाहिर है, तकरीबन सभी पार्टियों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक पारित न होने के संदर्भ में महिला आरक्षण का सवाल चुनावी राजनीति का भी मुद्दा बना और भाजपा की ओर से इस मसले पर विपक्षी दलों पर सवाल उठाए गए। विडबंना यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के घोषित दावों के बरक्स टिकट देने के मामले में भाजपा सहित सभी पार्टियों के भीतर इच्छाशक्ति की कमी दिखती है। क्या यही सबसे बड़ी वजह नहीं है कि विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और एक न्यायपूर्ण संतुलन के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ी? महज औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी महिला को टिकट देना सरोकारों के प्रति ईमानदारी को नहीं दर्शाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि महिला आरक्षण की व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए और उसके समांतर सभी राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को अधिकार के रूप में ज्यादा से ज्यादा अवसर देने को लेकर ईमानदारी से पहल हो।

## नया अध्याय

तमिलनाडु में सिनेमा और सियासत का खासा प्रभाव रहा है, जहां कई लोकप्रिय अभिनेताओं ने फिल्मी परदे से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया है। राज्य में अभिनेता से नेता बनने की परंपरा की नींव एमजी रामचंद्रन ने रखी थी। उन्होंने वर्ष 1972 में द्रमुक से अलग होकर अन्नाद्रमुक पार्टी का गठन किया और लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभाली। अब तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय भी उनकी राह पर हैं। उनकी पार्टी टीवीके राज्य विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। टीवीके की इस जीत को इसलिए अहम माना जा रहा है कि यह उसका पहला चुनाव था और उसने राज्य के इतिहास में एक बार फिर राजनीति की दिशा बदल दी है। इससे पहले यहां की सियासत केवल दो दलों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के ईर्द-गिर्द केंद्रित रहती थी। हालांकि, विजय की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन राज्य में उनकी सरकार बननी लगभग तय है। अब देखना होगा कि सत्ता संभालने के बाद वे जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे।

गौरतलब है कि तमिलनाडु की सियासत में एमजी रामचंद्रन के बाद कई फिल्मी सितारों ने कदम रखा, जिनमें जयललिता का नाम सबसे ऊपर है। अभिनेता विजयकांत और कमल हासन ने भी नए दलों का गठन किया, लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके अलावा, रजनीकांत ने भी वर्ष 2020 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। वहीं, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को बने हुए लगभग दो साल का ही वक्त हुआ है और पहले ही चुनाव में उसने राज्य की मुख्यधारा के दोनों दलों को करारी शिकस्त देकर शानदार जीत हासिल की है। विजय को अभिनेता के रूप में जिस तरह की फिल्मों से लोकप्रियता मिली है, उनमें से ज्यादातर व्यवस्था की जटिलता एवं उसमें सुधार पर केंद्रित रही हैं। अब यह देखने की बात होगी कि इससे पहले सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली द्रमुक की राज्य में शासन और विकास की नीतियों के समांतर अब विजय और उनकी टीवीके तमिलनाडु की राजनीति को कौन-सी नई दिशा देते हैं।

# अव्यवस्था के रोग से जूझते अस्पताल

**देश के स्वास्थ्य तंत्र में पसरी अव्यवस्था की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिन स्वास्थ्य संस्थानों को जीवन रक्षक मानकर उन पर भरोसा किया जाता है, वही कई बार संसाधनों की कमी, प्रबंधन की विफलता और बढ़ती व्यावसायिकता की वजह से संकट का कारण बन जाते हैं।**

**मनीष जैसल**

अस्पताल उपचार का केंद्र होते हैं, लेकिन कई बार वे खुद ही बीमार नजर आते हैं। यह कहने और सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन देश के स्वास्थ्य तंत्र की इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। जिन स्वास्थ्य संस्थानों पर हम जीवन बचाने का भरोसा करते हैं, वही कई बार संसाधनों की कमी, प्रबंधन की विफलता और बढ़ती व्यावसायिकता की वजह से संकट का कारण बन जाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा दबाव है, या फिर इसे खुद इलाज की जरूरत है। आज के दौर में अस्पताल जाना कई बार बीमारी से बड़ा अनुभव बन जाता है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन सबसे पहले उसे भीड़ और कतार में खड़े होकर कई घंटे इंतजार करने की परेशानी से जूझना पड़ता है। इसके बाद कहीं बिस्तर नहीं मिलता, तो कहीं विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद नहीं होते। यही नहीं, कई बार सब कुछ होने के बावजूद व्यवस्था साथ नहीं देती। यह तस्वीर किसी एक शहर की नहीं, बल्कि देश भर की है।

देश के अस्पतालों में प्रति एक हजार लोगों के लिए औसतन 1.3 बिस्तर हैं, जबकि दुनिया का मानक इससे दोगुने से भी ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि मरीज ज्यादा हैं और जगह कम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या और साफ दिखती है, जहां आबादी इतनी ज्यादा है कि अस्पताल हमेशा भरे रहते हैं। समय के साथ आबादी बढ़ी, मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके अनुरूप अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एनएचपी-2022) के अनुसार, देश में प्रति दस हजार आबादी पर अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता लगभग पंद्रह है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार न्यूनतम संख्या तीस बिस्तरों की है। यानी हम बुनियादी स्तर पर अभी आधे रास्ते में हैं। राज्यों के बीच असमानता इस संकट को और गहरा करती है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। बिहार में प्रति दस हजार आबादी पर बिस्तरों की संख्या छह-सात के बीच है। इसका मतलब है कि एक ही देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता नागरिक की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस 2022-23) की रपट से पता चलता है कि देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 70 फीसद से अधिक पद खाली हैं। कई बड़े राज्यों में यह आंकड़ा 75-80 फीसद तक है। यानी ग्रामीण भारत में रहने वाले करोड़ों लोग प्राथमिक स्तर पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं। अस्पतालों में संक्रमण की स्थिति भी चिंताजनक है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, देश में 10-15 फीसद मरीज इलाज के दौरान ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। विकसित देशों में यह आंकड़ा लगभग आधा है। यानी हमारे अस्पताल कई बार रोग से मुक्ति के बजाय नई बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। कोविड-19 महामारी ने इस सच्चाई को सबके सामने रखा। आक्सीजन की कमी, गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों का अभाव और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, ये दृश्य केवल एक आपदा नहीं, बल्कि हमारी तैयारियों की कमी का परिणाम थे। निजी अस्पतालों की भूमिका भी सवालों से परे नहीं है। इलाज

की बढ़ती लागत और पारदर्शिता की कमी ने आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को महंगा एवं जटिल बना दिया है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65 फीसद और शहरी क्षेत्रों में 70 फीसद लोग निजी अस्पतालों का सहारा लेते हैं। यह

> **देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। लगभग 65 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों का बड़ा हिस्सा शहरों में केंद्रित है। इस प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ कई बार मरीज की स्थिति भी गंभीर हो जाती है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अत्यधिक भीड़ और दबाव के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह असमानता केवल सुविधा की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के अभाव को दर्शाती है।**

केवल सुविधा नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर घटते भरोसे का संकेत है। देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1400 के आसपास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। नर्सिंग स्टाफ की कमी और उपकरणों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। कैग की रपटों में पाया गया है कि कई अस्पतालों में महंगे उपकरण या तो खराब पड़े रहते हैं या उनका उपयोग नहीं हो पाता। यानी समस्या संसाधनों की कमी के साथ-साथ उनके प्रबंधन की भी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 700 टन से अधिक जैव चिकित्सीय कचरा उत्पन्न होता है, जिसका पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पाता। यह स्थिति संक्रमण के खतरे को और बढ़ाती है।

इन चुनौतियों के बीच वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था- गरीब और कमजोर वर्ग को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। यह योजना अपनी अवधारणा में बेहतर थी और इसने लाखों लोगों को पहली बार बड़े अस्पतालों तक पहुंचने का अवसर दिया। मगर जैसे-जैसे इसका विस्तार हुआ, वैसे-वैसे इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आने लगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि कई अस्पतालों ने फर्जी मरीज दिखाकर या अनावश्यक प्रक्रियाएं जोड़कर इस योजना के तहत धनराशि के दावे किए।

ऐसे मामलों में सैकड़ों निजी अस्पतालों को अनियमितताओं के कारण इस योजना से बाहर कर दिया गया। इस तरह के मामलों का मानवीय पक्ष अधिक असहज करता है। एक सीमित आय वाला परिवार आयुष्मान कार्ड के भरोसे निजी अस्पताल पहुंचता है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। सतह पर सब कुछ सामान्य दिखता है, मगर बाद में कई बार सामने आता है कि अस्पताल की ओर से मरीज के इलाज के दौरान जिन प्रक्रियाओं का दावा किया गया, वे हुई ही नहीं। यानी अस्पतालों के लिए उपचार की गुणवत्ता से इतर, खर्च के बिल का विस्तार प्राथमिकता बन जाता है।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता भी स्पष्ट दिखाई देती है। लगभग 65 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों का बड़ा हिस्सा शहरों में केंद्रित है। इस प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ कई बार मरीज की स्थिति भी गंभीर हो जाती है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अत्यधिक भीड़ और दबाव के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह असमानता केवल सुविधा की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के अभाव को दर्शाती है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित होता है, जबकि सरकारी अस्पतालों पर गरीब और निम्न आय वर्ग की निर्भरता अधिक है। अनुमानतः 60 से 70 फीसद मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर होती हैं, लेकिन खर्च अधिक होता है।

इसके विपरीत, सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता या निःशुल्क होता है, लेकिन वहां संसाधनों की कमी और अत्यधिक भीड़ के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति एक ऐसी दोहरी व्यवस्था को जन्म देती है, जहां इलाज की गुणवत्ता व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है और यह स्वास्थ्य सेवाओं की समानता और न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मानव संसाधनों की कमी को दूर करना प्राथमिक कदम होने चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

# तकनीक बनाम उद्देश्य

**प्रथमेश मणि तिवारी**

**दुनिया मेरे आगे**

मानव जीवन मूल रूप से विकल्पों का जीवन है। हम हर दिन छोटे और बड़े निर्णय लेते हुए अपनी दिशा तय करते हैं, लेकिन आज के समय में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। पहले जीवन आमतौर पर बाध्यताओं द्वारा संचालित होता था। आज जीवन का बड़ा हिस्सा विकल्पों द्वारा निर्धारित होता है। इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की है। तकनीक ने न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया है, बल्कि उसने हमें यह भी तय करने की स्वतंत्रता दी है कि हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करें। अगर हम इतिहास की ओर देखें, तो प्राचीन यूनान के दार्शनिक अरस्तू ने दासप्रथा के बारे में यह कहा था कि दास अपने स्वामियों को दैनिक श्रम से मुक्त करते हैं, जिससे वे उच्च बौद्धिक और दार्शनिक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। आज हम दासप्रथा को एक अमानवीय व्यवस्था मानते हैं और यह सही भी है।

अगर हम इस विचार को केवल एक कार्यात्मक तुलना के रूप में देखें, तो आधुनिक समाज में तकनीक कुछ हद तक वही भूमिका निभाती है। तकनीक हमें रोजमर्रा के श्रमसाध्य और दोहराव वाले कार्यों से मुक्त करती है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सृजनात्मक दिशा दे सकें। आज वाशिंग मशीन कपड़े धोती है, गैस और इंडक्शन चूल्हे खाना बनाना आसान करते हैं, डिजिटल मंच हमें पल में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। इन सबके कारण हमारे पास पहले की तुलना में अधिक समय उपलब्ध है। यह समय एक अवसर है, पर यही अवसर एक चुनौती भी है। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास समय है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उस समय का उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं।

> **आधुनिक विज्ञान के विकास ने मानव को अपार शक्ति दी, लेकिन साथ ही यह खतरा भी उत्पन्न किया कि हम प्रकृति और स्वयं अपने जीवन को केवल उपयोग और नियंत्रण के दृष्टिकोण से देखने लगें। अगर हमारे विकल्प केवल इसी सीमित सोच तक बंधे रहेंगे, तो न वे मानवता के लिए लाभकारी होंगे और न ही प्रकृति के लिए टिकाऊ।**

मानव जीवन केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर पूरा जीवन केवल खाना बनाने, सफाई करने और जीविका चलाने में ही बीत जाए, तो यह जीवन की संभावनाओं के साथ अन्याय होगा। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जीना है। तकनीक हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। वह हमारे लिए साधन का कार्य करती है, साध्य का नहीं। यहीं पर चयन की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जब हमारे पास अधिक विकल्प होते हैं, तब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हम अपने समय का उपयोग ज्ञान अर्जन में कर सकते हैं, कला में कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने में कर सकते हैं, या फिर उसे केवल मनोरंजन और निष्क्रिय उपभोग में व्यर्थ कर सकते हैं। यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आज के डिजिटल युग में यह समस्या और भी गहरी हो गई है। सोशल मीडिया, आनलाइन मनोरंजन और अनगिनत डिजिटल विकल्प हमें लगातार आकर्षित करते रहते हैं। ये मंच हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं और हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देते हैं, जहां समय का बोध ही समाप्त हो जाता है। नतीजतन, वह समय जो हमें आत्मविकास या सामाजिक योगदान के लिए मिल सकता था, वह धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में तकनीक के स्वामी हैं या हम स्वयं उसके अधीन होते जा रहे हैं। तकनीक का उद्देश्य हमें मुक्त करना था, पर यदि हम सजग नहीं रहे तो वही तकनीक हमें एक नए प्रकार की निर्भरता में बांध सकती है।

इस संदर्भ में हमें इतिहास के एक और महत्त्वपूर्ण मोड़ की ओर ध्यान देना चाहिए। पुनर्जागरण के समय एक विचार प्रमुखता से उभरा जिसे हम साधन-केंद्रित तर्क कह सकते हैं। इसमें तर्क और ज्ञान को मुख्यतः प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। आधुनिक विज्ञान का विकास इसी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ। इसने मानव को अपार शक्ति दी, लेकिन साथ ही यह खतरा भी उत्पन्न किया कि हम प्रकृति और स्वयं अपने जीवन को केवल उपयोग और नियंत्रण के दृष्टिकोण से देखने लगें। अगर हमारे विकल्प केवल इसी सीमित सोच तक बंधे रहेंगे, तो न वे मानवता के लिए लाभकारी होंगे और न ही प्रकृति के लिए टिकाऊ। हमें अपने निर्णयों में विवेक और उत्तरदायित्व को शामिल करना होगा। तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि एक व्यापक और नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। हमें अपने भीतर यह प्रश्न लगातार जीवित रखना होगा कि हम अपने समय का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। क्या हम तकनीक द्वारा मिले अवसरों का उपयोग अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में कर रहे हैं? क्या हम समाज और मानवता के लिए कुछ सार्थक कर रहे हैं? या फिर हम केवल क्षणिक सुख और मनोरंजन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं?

तकनीक स्वयं में न तो अच्छी है और न ही बुरी। उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम सजग, विवेकशील और उत्तरदायी होकर अपने चुनाव करेंगे, तो तकनीक हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगी। अन्यथा वही तकनीक हमें एक ऐसे चक्र में फंसा सकती है, जहां स्वतंत्रता केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगी। विकल्पों से भरे इस युग में, सबसे बड़ी आवश्यकता है उद्देश्य की स्पष्टता। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब हमारे निर्णय भी सार्थक होंगे। तकनीक हमें एक अवसर देती है, लेकिन उस अवसर को अर्थपूर्ण बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती और संभावना है।

## सामूहिक विफलता

ओड़ीशा के क्योंझर जिले की एक घटना ने आधुनिक भारत के विकास और डिजिटल होती बैंकिंग व्यवस्था के समांतर एक स्याह तस्वीर सामने रख दी है। एक भाई को अपनी मृत बहन के बैंक खाते से महज 19,300 रुपए निकालने के लिए उसके कंकाल को कंधे पर लाद कर बैंक पहुंचना पड़ा। यह हमारे प्रशासन, बैंक और स्थानीय शासन की सामूहिक विफलता का प्रमाण है। जीतू मुंडा को उसकी बहन के खाते का पैसा देने के मामले में बैंक अपनी जटिल प्रक्रियाओं की दुहाई देता रहा, केवाईसी और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में एक गरीब और बेसहारा इंसान को उलझाता रहा। सवाल यह है कि क्या बैंक के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह स्वयं उस घर तक जाकर वास्तविकता की जांच कर पाता? क्या एक गरीब की सच्चाई की कीमत बैंक के नियमों से कम है? क्या यह उसका नैतिक दायित्व नहीं था? तकनीक और संसाधनों से लैस संस्थाएं यदि वास्तविकता की जांच नहीं कर सकतीं, तो उनकी उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महिला की मृत्यु के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने मृत्यु प्रमाणपत्र क्यों नहीं जारी किया?

*– युगल किशोर राही, छपरा*

## चुनौतियों का जाल

'संकट के संकेत' (संपादकीय, 30 अप्रैल)। पढ़ा। इसमें औद्योगिक विकास की स्थितियों और उसकी जरूरत पर उचित टिप्पणी की गई है। वर्तमान वैश्विक अस्थिरता, विशेषकर पश्चिम एशिया संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक विकास की निरंतरता आपूर्ति शृंखला की मजबूती पर निर्भर करती है। पश्चिम एशिया में संकट के बाद तेल-गैस आपूर्ति में बाधा और निर्यात पर असर से उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि भारत ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करे, वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग विकसित करे और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन दे। आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुधार, भंडारण क्षमता बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही, वैश्विक साझेदारियों को संतुलित रखते हुए व्यापारिक जोखिम को भी कम करना जरूरी है।

*– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर*

## जोखिम की राहें

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बेहद अधिक है। हर साल लाखों लोग हादसे में घायल होते हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है। इन हादसों के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी, वाहन चालकों की लापरवाही और सड़कों की खराब स्थिति। इसके अलावा ज्यादा सामान लादने और 'ओवरटेकिंग' भी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। लोग समय बचाने या जल्द गंतव्य तक पहुंचने की होड़ में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन न करना एक आम समस्या बन गई है। जबकि जरा-सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। सड़कों की स्थिति भी कई जगहों पर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ऐसे में आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।

*– कांतिलाल मांडोत, लखनऊ*

## सबक से दूर

'सबक के बजाय' (संपादकीय, 4 मई) पढ़ा। राजधानी में निजी और सरकारी कई तरणताल बने हुए हैं जिसमें बच्चे और युवा गर्मी के मौसम में तैरने जाते हैं, लेकिन दुख की बात है कि इनमें समय-समय पर ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनसे प्रायः लापरवाही सामने आती है। पिछले दिनों तीन बच्चों की मौत ने विभिन्न प्रकार के सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले जुलाई 2023 में भी इस तरह की घटना हुई थी। तब भी लापहवाही जारी रही। विभिन्न प्रकार की खामियों का पाया जाना भी सवाल खड़े करता है। आखिरकार इस तरह की कोई घटना होती है, तो इसके पीछे कोई न कोई वजह होती ही है। प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन सभी कमियों को दूर किया जाए।

*– मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

## ‘उत्तराखंड में गंगा के मुख्य प्रवाह में कोई प्रदूषित क्षेत्र नहीं’

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि गंगा का निर्बाध व स्वच्छ प्रवाह सुनिश्चित करने का मिशन ठोस परिणाम दे रहा है। पाटिल ने ‘एक्स’ पर समीक्षा के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में गंगा के मुख्य प्रवाह में कोई प्रदूषित क्षेत्र नहीं है। गंगा नदी के निर्बाध प्रवाह, स्वच्छता और संरक्षण के लिए किए गए संकल्प ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।’ इस दिशा में उत्तराखंड में गंगा के मुख्य प्रवाह में किसी भी प्रदूषित हिस्से का न होना एक बहुत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। समीक्षा के दौरान उत्तराखंड में गंगा में बहने वाले नालों को पूरी तरह से रोकने, मलजल शोधन अवसंरचना को और मजबूत करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। *(ए)*

# बंगाल में जीत के बाद भाजपा की अब सात राज्यों पर निगाहें

जनसत्ता ब्यूरो

***गुजरात,*** गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं। इनमें से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा की सरकार नहीं है।

***वर्तमान*** में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है।

***भाजपा*** ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सोमवार को 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। असम में सत्तारूढ़ राजग दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाला है।

**चुनाव**

पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के साथ पूर्वी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निगाहें अब 2027 में होने वाले सात राज्यों के विधानसभा चुनावों पर हैं। इनमें गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं। इनमें से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा की सरकार नहीं है। हालांकि दूसरी पार्टियां अभी तैयारी करती नहीं दिख रही हैं।

भाजपा ने इन राज्यों में चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अगले वर्ष के चुनावी अभियान के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ कर दिया है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब पार्टी का ध्यान अगले वर्ष सात राज्यों में होने वाले चुनावों पर केंद्रित होगा। कुछ स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें अब और तेज किया जाएगा। नवीन गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों व नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। वह जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां अगले वर्ष गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जीतने में अधिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या पंजाब में आने वाली है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसलिए वह पंजाब पर अधिक ध्यान दे रही है। हालांकि, आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को इसका कुछ फायदा विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसको लेकर पार्टी अभी से ही सचेत है और कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव में लगने के लिए कहा गया है। गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकायों को चुनाव में भाजपा को मिली बढ़त से पार्टी को विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी वह बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि, आप यहां भाजपा का सिर दर्द बन सकती है।

हाल ही में संपन्न चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद जश्न मनाने के लिए पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवीन ने सोमवार को कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘अटूट विश्वास’ बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक राजग-भाजपा की सरकार बन रही है। यह केवल भौगोलिक विस्तार नहीं, बल्कि हमारे नेतृत्व और दृष्टि में लोगों के विश्वास का विस्तार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ आने वाले समय की तैयारियों में जुट चुके हैं।

# बढ़ने लगा पर्यावरण अनुकूल जूते-चप्पल का बाजार

राकेश शर्मा

***दुनियाभर*** में तेजी से बढ़ रही ‘बायोडिग्रेडेबल’ जूते-चप्पलों की मांग, निर्यात के मामले में भारत पीछे, कुछ स्टार्टअप आए आगे, देश में साल 2030 तक बाजार का आकार बढ़कर छह अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान।

## *देश में सालाना करीब 2.9 अरब जोड़ी जूते बनते हैं*

एक अनुमान है कि यह बाजार 2024 के 3.2 अरब डालर से बढ़कर 2030 तक छह अरब डालर तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र से 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिनमें करीब 50 फीसद महिलाएं हैं। देश में सालाना करीब 2.9 अरब जोड़ी जूते बनते हैं, लेकिन प्रति श्रमिक उत्पादकता अभी 4-5 जोड़ी प्रतिदिन है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 17-20 जोड़ी प्रतिदिन तक है। उनका दावा है कि भारत इस क्षेत्र में बड़ा कर सकता है। थ्री डी बुनाई, उन्नत निर्माण तकनीक और एआइ आधारित रचना जैसे नवाचार उत्पादन को तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं।

देश में पर्यावरण अनुकूल जूते-चप्पलों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया की मांग के अनुसार भारत उत्पादन के मामले में काफी पीछे है। देश में अभी भी बड़े स्तर पर पारंपरिक रूप से चमड़े, रबड़ व प्लास्टिक पर आधारित उद्योग चल रहे हैं। विकल्प के तौर पर ‘बायोडिग्रेडेबल’ पर्यावरण अनुकूल चीजों से जूते-चप्पल निर्माण के लिए कुछ स्वदेशी स्टार्टअप आगे आए। इन्होंने गन्ने के अपशिष्ट, चावल के भूसे, बांस, घास, कृषि अपशिष्ट सहित अन्य से जूते-चप्पल बनाने का काम शुरू किया है। लेकिन जूते-चप्पलों के बाजार में इनकी भागीदारी बेहद कम है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण पूरी दुनिया में ऐसे सामान को प्राथमिकता की दी जा रही हैं जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। इसमें जैवनिम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) आधारित जूते-चप्पल विकल्प के तौर पर उभरे हैं। यह उपयोग के बाद प्राकृतिक रूप से मिट्टी, पानी और सूक्ष्म जीवों की मदद से धीरे-धीरे टूटकर खत्म हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि सामान्य जूते (प्लास्टिक, सिंथेटिक, रबर) को खत्म होने में 50झ200 साल लग सकते हैं। भारत में यह क्षेत्र की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन यह तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। इन जूते-चप्पल की कीमतें सामान्य जूतों से थोड़ी ज्यादा होती हैं यही कारण है कि मध्यम व गरीब वर्ग में इसे लेकर एक निराशा दिखती है। वस्त्र मंत्रालय का दावा है कि भारत में जूते-चप्पल का क्षेत्र तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ‘बायोडिग्रेडेबल’ जूते-चप्पल इस बदलाव के केंद्र में आ गए हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 23.9 अरब जोड़ी जूते-चप्पल का उत्पादन होता है, जिसका बाजार आकार लगभग 500 अरब अमेरिकी डालर है। इसमें भारत की हिस्सेदारी उत्पादन में 12.5 फीसद है, लेकिन निर्यात में यह सिर्फ दो फीसद ही है। यह अंतर भारत की क्षमता और वैश्विक भागीदारी के बीच की खाई को दर्शाता है। दुनिया के लगभग 86 फीसद जूते-चप्पल गैर-चमड़ा हैं, जबकि भारत का उद्योग अभी भी पारंपरिक रूप से चमड़े पर आधारित है। ऐसे में जैवनिम्नीकरणीय फाइबर, पुनर्चक्रित पीईटी और अन्य टिकाऊ सामग्री का उपयोग भारत के लिए नई दिशा तय कर सकता है।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि देश के भीतर भी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में भारतीय जूते-चप्पल का बाजार 20.67 अरब डालर तक पहुंच गया। हालांकि, एक औसत भारतीय साल में केवल दो जोड़ी जूते खरीदता है, जबकि वैश्विक औसत सात-आठ जोड़ी है। इससे घरेलू बाजार में बड़े विस्तार की संभावना है।

# दो दिन में दो पायलटों की मौत से उठने लगे सवाल

सर्वेश कुमार

***फ्लाइट*** ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों को लागू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किए जाने पर पायलट संघों ने चिंता जताई है।

**चिंता**

तनाव और थकान से जूझ रहे पायलटों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। खासकर, अप्रैल के आखिरी दो दिनों में दो पायलटों की मौत ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पायलटों को राहत देने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों को लागू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किए जाने पर पायलट संघों ने चिंता जताई है।

हालांकि स्वास्थ्य मामलों के जानकार बताते हैं ड्यूटी के नियमों का सख्ती से पालन, कोविड के बाद सेहत पर असर सहित पायलटों की सेहत को लेकर कई और चुनौतियां हैं। विमानन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पहले भी इस तरह के मामले आए हैं, लेकिन मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सघन अध्ययन करने की जरूरत है। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के एक सांसद ने भी प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ठीक एक हफ्ते पहले दो दिन के दौरान लगातार दो पायलटों की मौत ने पायलटों की सेहत, थकान और तनाव सहित कई और पहलुओं पर ड्यूटी के दौरान सभी पायलटों के लिए एकसमान सहूलियतें देने की मांग उठाई जा रही है।

पायलटों के संगठन एअरलाइन पायलट्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने विमानन नियामक (डीजीसीए) से विमानन कंपनियों के लिए थकान से जुड़े मानकों में किसी भी तरह की ढील न देने की मांग की है। संगठन ने इससे पहले भी किसी भी तरह की छूट को सुरक्षा से सीधा समझौता बताया था। 29 अप्रैल को एअर इंडिया के एक पायलट की बाली में मौत हो गई थी। ठीक इसके एक दिन बाद 30 अप्रैल को अकासा एअर के एक पायलट की प्रशिक्षण के दौरन मौत हो गई। हालांकि, दोनों अपने निधन के समय ड्यूटी पर नहीं थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को लिखे पत्र में एअरलाइन पायलट्स एसोसिएशन-इंडिया (एएलपीए-इंडिया) ने उड़ान सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं को उठाते हुए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों में दी गई छूट को धीरे-धीरे वापस लेने और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिए समयबद्ध प्रारूप की मांग की है। विमानन नियामक ने दिसंबर में पायलटों के लिए बढ़ाए गए आराम के घंटों से संबंधित संशोधित एफडीटीएल मानदंडों में अस्थायी रूप से छूट दी थी। यह छूट इंडिगो में पायलटों की कमी के कारण पैदा हुए संकट को दूर करने और इस साल पश्चिम एशिया संकट के कारण हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के मद्देनजर पायलटों को लंबी दूरी के मार्गों पर उड़ान भरने में सक्षम बनाने के लिए दी गई थी।

एएलपीए-इंडिया के अध्यक्ष सैम थामस का कहना है कि पिछले तीन साल में अलग अलग वजहों से करीब 20 पायलटों की मौत हो चुकी है। ऐसे में संचालकों को लगातार छूट दिए जाने से एफडीटीएल नियमों का मूल उद्देश्य काफी हद तक कमजोर हो गया है। ये छूट जिन्हें मूल रूप से अस्थायी उपायों के रूप में तैयार किया गया था, अब प्रभावी रूप से मानक बन गई हैं। एफडीटीएल मानदंडों को कमजोर करने वाले किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए थकान रिपोर्टिंग प्रणाली को पारदर्शी और

## कार्यक्रम

भोपाल के रवींद्र भवन में नृत्योत्सव के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करते श्री कला समिति के कलाकार।

# 4202 किलोमीटर पूर्ण हो तो, पूरा हो भारतमाला का पहला चरण

पंकज रोहिला

**योजना**

देश में एक छोर से दूसरे छोड़ तक बेरोकटोक वाहन दौड़ सकें। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 12 साल पहले भारत माला योजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। इस लम्बे समय के बाद भी केंद्र सरकार इस योजना का पूर्ण नहीं कर पाई है।

आज भी इस योजना के तहत किए जाने वाला 4202 किलोमीटर की परियोजनाओं का काम बीच में फंसा हुआ है और करीब 79 परियोजनाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में यह रपट दी है।

नितिन गडकरी के मुताबिक भारतमाला योजना का पहला चरण 2017 में शुरू किया गया था। इस चरण में कुल 34800 किमी की मार्ग परियोजनाएं थी, जिन पर करीब 535000 करोड़ खर्च होने का अनुमान था। अब तक केंद्र सरकार ने 26425 किलोमीटर मार्ग का कार्य आवंटित किया है और 22223 किमी का कार्य फरवरी 2026 तक पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार भी पहले चरण की परियोजनाओं में से 4202 किलोमीटर की योजनाओं का काम लटका हुआ है। सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारतमाला परियोजना के तह आने वाली 85 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं ऐसी है, जो कि तीन वर्ष से भी अधिक समय से देरी से चल रही हैं।

मंत्रालय के मुताबिक सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण, संबंधित एजंसियों से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में देरी, मार्ग पर विभिन्न एजंसियां जैसे पानी- सीवर या बिजली लाइन को हटाने, अतिक्रमण हटाने, निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं होना, बाढ़, तूफान, पहाड़ सरकने जैसी घटनाएं भी शामिल रही है। इसके अतिरिक्त देश में कोरोना काल के दौरान भी इस योजना का काम प्रभावित रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अब मंत्रालय की ओर से भूमि राशि पोर्टल, पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी मदद से मंजूरी प्रक्रिया को सुधारा गया है।

# उत्तराखंड में हिमनदों-झीलों की नई तकनीक प्रणाली से होगी रक्षा

सुनील दत्त पांडेय

***आपदा*** प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वाडिया संस्थान द्वारा वसुंधरा झील को एक पायलट साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी तंत्र एवं मानिटरिंग मैकेनिज्म स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 169 सेंसर एवं 112 सायरन स्थापित किए जा चुके हैं। आइआइटी रुड़की के साथ मिलकर लगातार पूर्व चेतावनी तंत्र को मजबूत किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

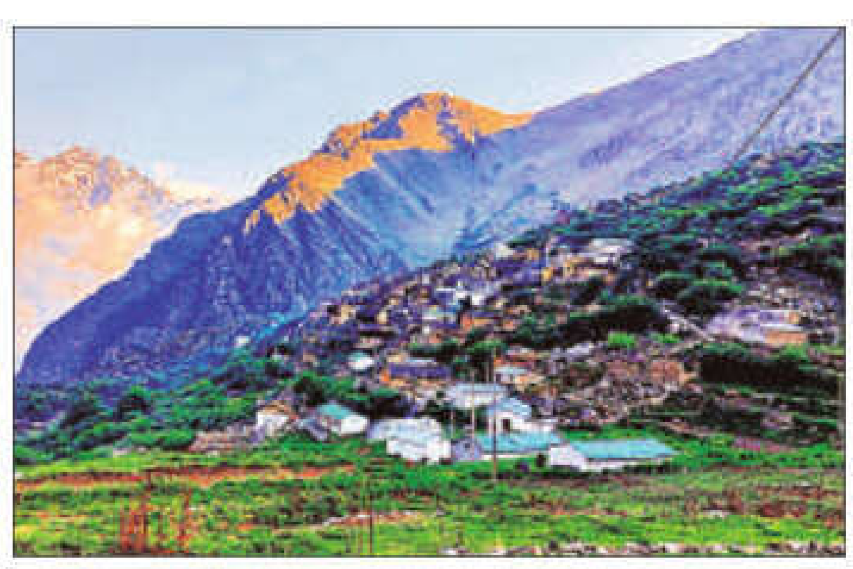

**तैयारी**

उत्तराखंड की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण यहां पर स्थित हिमनद और झील हैं। पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ते जाने से व निर्माण के दबाव के कारण यहां के हिमनदों और झीलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने हिमनदों और झीलों की रक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली का सहारा लेने की योजना बनाई है।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून में पर्यावरण एवं भूगर्भीय वैज्ञानिकों की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें उत्तराखंड की प्राकृतिक दिशा और दशा के बारे में रपट प्रस्तुत की गई और उसके आधार पर हिमनदों और झीलों की सुरक्षा का एक खाका तैयार किया गया।

देवभूमि उत्तराखंड में करीब में 1,439 हिमनद हैं, जो इस पर्वतीय राज्य के 4,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह हिमनद गंगोत्री, यमुनोत्री, और मिलम, राज्य की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा ,मंदाकिनी आदि के जल स्रोत हैं। प्रमुख हिमनद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों में फैले हुए हैं। गंगोत्री हिमनद राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध हिमनद है, जहां से भागीरथी (गंगा) नदी निकलती है। पिंडारी हिमनद कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है जो बर्फ में दौड़ भाग करने वालों के लिए यानी ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में मिलम हिमनद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। गढ़वाल मंडल के टिहरी जिले में खतलिंग हिमनद भिलंगना नदी का प्रमुख स्रोत है। चमोली जिले में सतोपंथ और भागीरथी अलकनंदा नदी का जल का प्रमुख स्रोत है। उत्तराखंड के अन्य हिमनदों में केदारनाथ और अन्य क्षेत्रों में बंदरपूंछ, कफनी, नामिक, बागिनी,चोराबाड़ी व दूनागिरी हिमनद पाए जाते हैं। वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान देहरादून के जाने-माने वैज्ञानिकों के अध्ययनों के मुताबिक, उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 5.3% भाग को प्रभावित करते हैं। यह हिमनद मुख्य रूप से गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में स्थित हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी रपट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य भूकंप को लेकर अब जोन-6 के तहत आता है, जो भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से सबसे खतरनाक और उच्च श्रेणी है। सबसे चिंताजनक और चौंकाने वाली बात यह है कि पहले उत्तराखंड पर्वतीय राज्य का कुछ हिस्सा जोन-4 और कुछ जोन-5 में आता था, लेकिन अब पूरा राज्य जोन-6 में शामिल हो गया है।

उत्तराखंड अब उच्चतम भूकंपीय खतरा वाला क्षेत्र बन गया है। गुरुकुल कांगड़ी विवि के पर्यावरण विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर बीडी जोशी ने कहा कि उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में होने के कारण, यहां निर्मित सभी इमारतों और बुनियादी ढांचे को उच्च तीव्रता वाले भूकंपों का सामना करने के लिए अत्यंत सख्त मानकों की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

# अब सिंहासन की बारी

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ होने के साथ ही वहां मुख्यमंत्री के चयन की कवायद तेज हो गई है। तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के विधायक दल ने मंगलवार को पार्टी के मुखिया जोसेफ सी विजय को अपना नेता चुन लिया, तो यह स्वाभाविक ही था। वहां किसी ऊहापोह की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। हालांकि, टीवीके पार्टी स्पष्ट बहुमत से दस सीट पीछे रह गई है, मगर उसे सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का अंकगणित बहुत कमजोर है और छोटे दलों के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, जो विजय के साथ खड़े हो सकते हैं। विजय के लिए असली चुनौती मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि वह पहली बार विधायक बने हैं और उनके पास संसदीय राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ, राज्य के लोगों की उनसे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। रुपहले परदे पर तंत्र की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले विजय के नायकत्व की असली परीक्षा उनमें जननायक तलाशते लोग अब लेंगे। अपने चुनावी वायदे को वह कितनी ईमानदारी से लागू कर पाते हैं, इस पर तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश की नजर होगी। यहां अरविंद केजरीवाल की नजीर उनके सामने है, जो दिल्ली में अपने ही बनाए मानदंड पर कैसे कसे गए और खारिज किए गए।

**पांचों राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, तो यह उचित भी है, क्योंकि देरी से प्रशासनिक ऊहापोह बनी रहती है, जिससे असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है।**

इसी तरह, पश्चिम बंगाल और असम में शानदार विजय हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दोनों प्रदेशों में विधायक दल के नेता के चयन के लिए जिस तत्परता से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा की है, वह भी सराहनीय है। पिछले कई चुनावों से यह एक परिपाटी सी बनती जा रही थी कि भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव में काफी समय लग जाता था और संबंधित राज्य को लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में, बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह व असम में स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा की नियुक्ति आश्वस्तकारी है कि वहां विधायक दल के नेता के चुनाव में अड़चनें नहीं आएंगी और जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी में राज्य सरकारें नियमित कामकाज में जुट सकेंगी। इन दोनों प्रदेशों में गहरे सामाजिक ध्रुवीकरण और चुनाव बाद ही हिंसा के इतिहास को देखते हुए जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार का गठन उचित है। खासकर पश्चिम बंगाल में आगजनी और हिंसा की कई घटनाओं को देखते हुए इस बात की अनिवार्यता और स्पष्ट हो जाती है। तमाम पार्टियों को इस समय परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए उद्दंड समर्थकों को नियंत्रित करना चाहिए।

केरलम और तमिलनाडु में भी सरकारें बदली हैं, मगर वहां जिस शालीनता से पराजित दलों ने जनादेश को स्वीकार किया है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाटकीय रुख को देखते हुए। उनकी कई शिकायतों को राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा मानते हुए भी इस बात की प्रशंसा नहीं की जा सकती कि वह स्थापित मूल्यों के खिलाफ आचरण करें। राजनीति में शिकवे-शिकायतें अपनी जगह हैं, मगर राजनेताओं का यह पहला दायित्व है कि वे परिणाम आने के बाद अपने समर्थकों-कार्यकर्ताओं के हितों को पहली प्राथमिकता दें। उन्हें किसी टकराव और भड़काऊ परिस्थिति के हवाले करना खुदगर्जी की राजनीति है। एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश अंतिम होता है और उसे शिरोधार्य करने में ही सबकी भलाई है।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 06 मई, 1951

### लोकतंत्री मोर्चे का भंग होना

अहमदाबाद में कांग्रेस महासमिति ने एकता का जो प्रस्ताव पास किया था, वह रंग लाने लगा है। नेहरूजी व मौलाना आजाद के प्रयत्नों से आचार्य कृपलानी तथा उनके साथियों ने लोकतंत्री मोर्चे को भंग करना स्वीकार कर लिया है।

हम इस बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय का स्वागत किये बिना नहीं रह सकते। इसके लिए न केवल नेहरूजी व मौलाना आजाद, वरन् आचार्य कृपलानी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सूझ से काम लेकर एकता की ओर ठोस कदम उठाया।

इस बात को तो सब स्वीकार करेंगे ही कि देश की वर्तमान डांवाडोल आर्थिक परिस्थितियों के समय हमें संगठित होकर उनका सामना करना है। यह समय राजनीतिक अखाड़ेबाजी का नहीं, समवेत प्रयत्नों से अपनी कमियों को दूर करने, वर्तमान का सामना करने और भविष्य को सुरक्षित बनाने का है। हमें आशा है कि कांग्रेस तथा लोकतंत्री मोर्चे ने एकता की ओर जो कदम उठाया है, उससे न केवल राजनीतिक विश्रृंखलता ही रुकेगी वरन् देश की आर्थिक भित्ति भी सुदृढ़ होगी।

काश्मीर की समस्या : भारत के विरोध के बावजूद अमरीका और उसके साथी काश्मीर में अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। गत सोमवार को सुरक्षा परिषद ने रूस की आपत्ति की पर्वाह न करते हुए एक अमरीकी नागरिक श्री फ्रांक ग्राहम को काश्मीर में नया संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया।

दूसरी ओर काश्मीर की जनता भी अपने अधिकारों के लिए उतनी ही दृढ़ है। जिस दिन सुरक्षा परिषद ने नये प्रतिनिधि की नियुक्ति की, उसी दिन काश्मीर में युवराज कर्णसिह ने एक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। जनता के मतों से निर्वाचित यह संविधान सभा ही काश्मीर के भविष्य का निर्णय करेगी। काश्मीर सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को भारतीय काश्मीर में न घुसने दे और इस प्रकार आंग्ल-अमरीकी गुट की चाल विफल कर दे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों ब्रिटेन व अमरीका में पाकिस्तान के प्रति अगाध स्नेह उमड़ पड़ा है। हाल में ही ब्रिटिश पत्रों ने नेहरूजी को उनकी काश्मीर-नीति के लिए जीभरकर कोसा है और उनकी तुलना चेम्बरलेन से की है, यही नहीं, उन्हें चेम्बरलेन से भी अधिक खतरनाक बताया है।

# क्या एसआईआर से सचमुच असर पड़ा

यहां स्कैन करें

रोशन किशोर | राजनीतिक आर्थिक संपादक, एचटी

**सांविधानिक व राजनीतिक नैतिकता को एक किनारे रख दें और ठोस चुनावी आंकड़ों पर गौर करें, तो भाजपा की इस जीत का मूल कारक एसआईआर नहीं दिखता है।**

भाजपा को जीत क्या एसआईआर की वजह से मिली है? पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह एक विवादास्पद सवाल बनता जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल से निर्वाचन आयोग ने जिन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया है, उनमें से छह राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, पर बंगाल इस मामले में सबसे विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि यहां 27 लाख मतदाता 'विचाराधीन' (अंडर एडजुडिकेशन) होने के कारण अयोग्य साबित कर दिए गए, यहां तक कि चुनाव के दिन भी वे अपने मताधिकार की बाट जोहते रह गए, जबकि करीब 62 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर में कटे हैं।

एसआईआर से जुड़ी सांविधानिक व राजनीतिक नैतिकता को एक किनारे रख दें और ठोस चुनावी आंकड़ों पर गौर करें, तो भाजपा की इस जीत का मूल कारक एसआईआर नहीं दिखता। इसे समझने के लिए तीन सवालों के जवाब तलाशते हैं। पहला सवाल है- पार्टियों के पारंपरिक गढ़ से बाहर एसआईआर का क्या असर रहा? दूसरा, मुस्लिम मतदाता इस प्रक्रिया से कितने प्रभावित हुए? और तीसरा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की असली वजह क्या रही?

शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। साल 2011, 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल और उसके सहयोगियों को क्रमशः 226, 211 और 215 सीटें मिली थीं। उन्होंने इन तीनों चुनावों में 124 सीटों पर हर बार जीत दर्ज की। मैं यहां 2011 से पहले के चुनावों को शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि 2008 के परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल गईं थीं।

बहरहाल, तृणमूल और उसके सहयोगियों को इस बार अपने गढ़ वाले 124 विधानसभा क्षेत्रों में से 78 में हार का सामना करना पड़ा है (इनमें से एक में चुनाव स्थगित है) और इन सभी क्षेत्रों से बाहर केवल 34 सीटें जीतने में उनको सफलता मिली है।

इसके बरअक्स, भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में क्रमशः 121, 77 व 90 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की (यहां 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को विधानसभावार बांटा गया है)। उसे इन सभी चुनावों में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में हर बार जीत मिली। इस बार भाजपा ने इन 54 विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ गुजरे तीनों चुनावों में कभी-न-कभी जीती गई सभी 142 सीटों पर भी विजय का परचम लहराया है। इसके अलावा, उसके खाते में 65 ऐसी सीटें भी आई हैं, जिन पर वह पहले कभी नहीं जीत सकी थी।

अगर किसी को बंगाल के इस नए घटनाक्रम को समझना है, तो उसे राज्य के चुनावी नतीजों पर एसआईआर के असर की जांच करनी चाहिए, पर उन 100 मजबूत विधानसभा सीटों को छोड़कर, जो 2026 में भी तृणमूल और कांग्रेस के पास ही रहीं। सवाल है कि इनमें से कितने क्षेत्रों में 2024 और 2026 के बीच मतदान में गिरावट देखी गई? जवाब है- 20, जिनमें से 2019, 2021, 2024 व 2026 में भाजपा 13 सीटों पर हर बार आगे रही, जबकि तृणमूल 2011, 2016, 2021 और 2026 में सात सीटें जीतीं (यह मंगलवार रात 10 बजे तक का आंकड़ा है)। बेशक, इन निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के कारण 2.1 प्रतिशत से लेकर 38.6 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटे हैं। किंतु, जब तृणमूल या भाजपा के वोट प्रतिशत में बदलाव और एसआईआर के कारण मतदाता-संख्या में आई कमी के बीच तुलना की जाती है, तो दोनों में दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिखता।

दूसरा सवाल। एसआईआर के तहत धर्म-विशेष के मतदाताओं के नाम को 'पक्षपातपूर्ण तरीके' से हटाने का आखिर क्या असर पड़ा? एसआईआर को लेकर यह आरोप जोर-शोर से उछला है कि इसके तहत उन जिलों में मतदाताओं के नाम ज्यादा हटाए गए, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। पश्चिम बंगाल में 39 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, जहां से 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इन 39 सीटों में से 18 सीटें उन जिलों में थीं, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी का अनुपात 50 फीसदी या उससे अधिक था। इस बार भी इनमें से 34 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जिनमें से महज पांच वास्तव में गैर-तृणमूल उम्मीदवार हैं। शेष पांच सीटें भाजपा के खाते में गई हैं।

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की कुल संख्या 40 है। साल 2021 में भी उनकी संख्या कमोबेश इतनी ही थी। अलबत्ता तृणमूल विधायकों में मुस्लिम विधायकों की हिस्सेदारी बढ़कर 42.5 प्रतिशत हो गई है। साफ है, यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उदाहरण है, न कि मतदाता-सूची में कथित हेर-फेर का नतीजा। असम में कांग्रेस भी इसी गफलत का शिकार हुई है।

ऐसे में, तीसरा सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का असली कारण क्या था? इसका जवाब है, सत्ता विरोधी लहर। लोगों पर इसका भारी असर दिखा है, शेष कसर ध्रुवीकरण ने पूरी कर दी। 2021 से 2026 के बीच तृणमूल ने 293 विधानसभा क्षेत्रों में से 268 में अपना मत-प्रतिशत गंवाया है। इनमें से 69 सीटों पर उसे 10 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके उल्ट, भाजपा ने 293 विधानसभा सीटों में से 270 में अपना मत-प्रतिशत बढ़ाया है और 95 सीटों पर उसे 10 प्रतिशत से अधिक का लाभ मिला है।

जन-समर्थन में आए इस बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से इसे समझना आसान होगा। दरअसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाममोर्चा ने 2006 की अपनी शानदार जीत और 2011 की करारी हार के बीच 11 प्रतिशत मत गंवाए थे। परिसीमन के कारण किए गए बदलावों के कारण इस परिवर्तन का क्षेत्रवार सटीक विश्लेषण संभव नहीं है, पर 2026 में तृणमूल के मत-प्रतिशत में लगभग 4.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है, जो वाममोर्चा की तुलना में कम है। यही कारण है कि ममता बनर्जी 2011 के वाममोर्चे की तुलना में अपनी सीटों की संख्या को कहीं अधिक बचाए रखने में सफल रही हैं।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती शेष है। अगर बचे हुए हिंदू मतदाता भाजपा या राज्य की अन्य विपक्षी पार्टियों का रुख कर लें, तब क्या होगा? ये मतदाता अब तृणमूल के खिलाफ मुखर हो सकते हैं, क्योंकि वह भाजपा से हार चुकी है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है।

(साथ में अभिषेक झा)

# वैश्विक पहचान मिलने से और संवरेगी शेखा झील

यहां स्कैन करें

संगीता सिंह | आयुक्त, अलीगढ़ मंडल

सुबह की हल्की धुंध में जब पक्षियों का मधुर कलरव रात्रि की नीरवता को तोड़ता है, तब शेखा झील का विस्तार एक जीता-जागता संसार बनकर उभरता है। यह संसार कोमल है, पक्षियों के मखमली पंखों-सा। प्रवासी पक्षी इस आर्द्रभूमि में आते हैं, अघोषित मेहमानों की तरह, कुछ दिन ठहरते हैं और उड़ चलते हैं किसी दूसरी दुनिया की ओर। पीछे रह जाती है, उनकी मीठी यादें और फिर से उनको देखने की कसक। अब जब शेखा झील को रामसर कन्वेंशन (अभिसमय) के तहत 'रामसर आर्द्रभूमि स्थल' का दर्जा प्राप्त हुआ है, तब इस शांत स्थल को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा साल 2018-19 के दौरान कराई गई गणना और 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में 22,361 झीलें हैं, हालांकि इनमें से बहुत सी झीलों की स्थिति अच्छी नहीं है। गाद जमने या सूख जाने के कारण इनमें से ज्यादातर उपयोग लायक नहीं रह गई हैं। इस समय देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें तालाब, टैंक, झील, जलाशय आदि शामिल हैं। इनके संरक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनमें से कई न सिर्फ हमारे शहरों की जीवनधारा हैं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिहाज से एक अनमोल संसाधन हैं।

**शेखा झील को रामसर कन्वेंशन के तहत 'रामसर आर्द्रभूमि' का दर्जा मिला है। इससे इस शांत स्थल को एक वैश्विक पहचान मिली है।**

इस पृष्ठभूमि में शेखा रामसर झील की अहमियत स्पष्ट हो जाती है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 1975 में प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ और वर्तमान में यहां 99 रामसर स्थल हैं। बिहार में बक्सर की गोकुल झील, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील और कटिहार में गोगाबिल झील के 'रामसर स्थल' बनने के बाद वहां रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

जो लोग शेखा झील को जानते हैं, वे इससे अभिभूत रहे हैं। उनके लिए यह शुरुआत नहीं, बल्कि इस स्थल की विशिष्टता की पुष्टि है। शेखा झील पर कभी शांत बैठे बगुले के रूप में, कभी अबाबील जैसे शिकारी के रूप में और कभी दूर देश से आए प्रवासी पक्षियों की विभिन्न सुर लहरियों में जीवन के विविध आयाम सहज ही परिलक्षित होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय महत्व हमेशा जोर-शोर से अपने को प्रकट नहीं करते, बल्कि निश्छल जल की तरह धीरे से अपनी चमक बिखेर देते हैं। अभी पिछले वर्ष ही प्रशासन व नागरिक समाज के लोग झील पर जमी सूखी जलकुंभी साफ करने आए थे। बारिश आते-आते वह प्रयास झील में दिख रहे स्वच्छ जल और पक्षियों की बढ़ी हुई संख्या के रूप में सामने आया।

रामसर कन्वेंशन अपने साथ मात्र वैश्विक पहचान नहीं लाया है, वरन पर्यावरणीय संरक्षण व इसके सतत उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता लेकर आया है। करीब 40 हेक्टेयर में फैली यह आर्द्रभूमि अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर है। प्रतिवर्ष 'बार हेडेड गूज, ग्रे लैग गूज' व 'नॉर्दर्न पिनटेल' जैसे प्रवासी पक्षी इसके शांत जल में जीवन की किलकारियां भरते हैं। यहां अब तक पक्षियों की 166 प्रजातियों की आमद दर्ज की गई है। मंडल के दूसरे जिले- एटा की जलेसर तहसील में 'पटना पक्षी विहार' को हाल में ही रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे यहां भी इको-टूरिज्म की संभावना बनी है।

इन स्थलों के विकास का उद्देश्य यह है कि सैलानी इन आर्द्रभूमियों का भ्रमण करें और प्राकृतिक परिवेश में विश्राम केंद्रों का सहज आनंद प्राप्त करें। अगर सावधानी से कार्य किया जाए, तो इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इस क्षेत्र की सूक्ष्म प्राकृतिक संरचना भी बची रहेगी। हालांकि, इन सबके बीच मुख्य चुनौती इस बात की है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या कहीं पक्षियों के सहज जीवन में व्यवधान न उत्पन्न करे। इसी तरह, समय-समय पर इन जल क्षेत्रों की सफाई और इनमें जलकुंभी के विस्तार को रोकना सतत चुनौती होगी। यहां निर्बाध जलापूर्ति भी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। शेखा झील आज एक सितारा बनकर उभरा है। अब इसकी चमक को और निखारने व आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)

## मनसा वाचा कर्मणा

# ओंकार का महत्व

एक साधक ने प्रश्न किया- 'बाबा, सत्य का सबसे बड़ा माध्यम क्या है?'

*सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति*- यह वैदिक उद्घोष भारतीय दर्शन की उस गहराई को स्पर्श करता है, जहां शब्द अपनी सीमा स्वीकार करते हैं और अनुभव ही सत्य का एकमात्र माध्यम बन जाता है। वेद, उपनिषद और समस्त आध्यात्मिक परंपराएं जिस परम तत्व की ओर संकेत करती हैं, उसे पाने के लिए तपस्वी तप करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साधक जीवन भर साधना में निमग्न रहते हैं। उसी परम सत्य को संक्षेप में ॐ या ओंकार के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

ओंकार सृष्टि का मूल स्पंदन है। यह वह आद्य कंपन है, जिससे सृजन, पालन और संहार की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। अ+उ+म, इन तीन ध्वनियों का सम्मिलित रूप ओंकार है, जो ब्रह्म के त्रिविध आयामों का प्रतीक है। अ सृष्टि का आरंभ, उ उसका विस्तार और म उसका लय दर्शाता है। इस तरह ओंकार में संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और प्रक्रिया समाहित है। यह 'सगुण ब्रह्म' की अभिव्यक्ति है, जबकि निर्गुण ब्रह्म उस परम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी गुणों, रूपों और शब्दों से परे है। यही कारण है कि ओंकार को निर्गुण और सगुण के बीच एक अद्भुत सेतु माना गया है।

वास्तव में ब्रह्म का अनुभव बौद्धिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। इसे तर्क या भाषा से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम केवल प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से उसके निकट पहुंचने का प्रयास करते हैं। ओंकार ऐसा ही एक दिव्य प्रतीक है, जो उस अनंत सत्ता की झलक प्रदान करता है। यह केवल उच्चारण का विषय नहीं, बल्कि श्रवण का विषय है। उस सूक्ष्म नाद को सुनना, जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड के विस्तार में निरंतर गूंजता रहता है। जब साधक बाहरी कोलाहल से हटकर अपने अंतर्मन में उतरता है, तब इस अनाहत नाद को अनुभव करता है। यही उसे मूल स्रोत से जोड़ देता है।

आध्यात्मिक साधना का सार इसी अनुभव में निहित है। साधक जब इस ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है और चेतना विस्तार होने लगता है। यह प्रक्रिया आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। इस गूढ़ सत्य को सरल भाषा में समझाने के लिए रामायण का एक प्रसंग है। जब भगवान राम के चरणों के स्पर्श से नाव सोने की बन गई, तो नाविक की पत्नी हर वस्तु को सोना बनाने लगी। तब नाविक ने उसे समझाया कि वस्तुओं की अपेक्षा उन चरणों की शरण में जाना अधिक बुद्धिमानी है।

**आध्यात्मिक साधना का सार इसी अनुभव में निहित है। साधक जब इस ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है और चेतना का विस्तार होने लगता है।**

यह कथा सिखाती है कि बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय मूल स्रोत से जुड़ना ही सच्चा ज्ञान है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

पोप लिओ XIV | ईसाई धर्मगुरु

**शिक्षण का अर्थ है, आंतरिक आजादी हासिल करने और आलोचनात्मक सोच के लिए खुद को तैयार करना। इस प्रक्रिया में, आस्था और तर्क न एक-दूसरे की उपेक्षा करते हैं और न विरोध। सत्य की खोज में दोनों को हमसफर होना चाहिए।**

## अनुलोम-विलोम
### जनादेश 2026

# भाजपा नब्ज पकड़ने में सफल रही

हालिया विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, रणनीतियों, नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों का जटिल मिश्रण है। इस बार के नतीजों ने कई स्थापित धारणाओं को तोड़ा और नई राजनीतिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वजहों से सत्ता-परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर गहराई से देखें, तो कुछ साझा कारक ऐसे रहे, जिन्होंने इन नतीजों को आकार दिया।

इनमें भाजपा द्वारा जनता की नब्ज पकड़ना उल्लेखनीय है। चुनाव अब केवल विकास या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पहचान संस्कृति और भावनात्मक अपील तक व्यापक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ माहौल बना, लेकिन यह केवल सत्ता-विरोधी रुझान नहीं था। यहां एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया। माछ-भात, झालमुड़ी और मां काली जैसे प्रतीकों के जरिये यह संदेश दिया गया कि स्थानीय परंपराओं का सम्मान केवल एक खास राजनीतिक विचारधारा ही कर सकती है। इसी तरह, ध्रुवीकरण भी इन चुनावों में बड़ा कारक रहा। यह केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के स्तर पर भी हुआ। असम में इसका एक अलग रूप देखने को मिला और इसे कहीं अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया।

इन चुनावी नतीजों का एक बड़ा कारक प्रशासनिक और संरचनात्मक बदलाव भी है। मतदाता सूचियों में संशोधन और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं का असर नतीजों पर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने का मुद्दा चर्चा में रहा, वहीं असम में परिसीमन के बाद सीटों का स्वरूप बदल गया, जिससे कई क्षेत्रों का राजनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ। ये बदलाव तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका असर जमीन पर बहुत गहरा होता है। हालांकि, तमिलनाडु में जो हुआ, वह भारतीय राजनीति के लिए एक दिलचस्प मोड़ है।

यहां एक फिल्मी सितारे ने अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। यह बदलाव जिस तेजी और पैमाने पर हुआ, उसने सबको चौंका दिया। इसका मतलब यही है कि आज का मतदाता पारंपरिक दलों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार है। खासकर युवा ऐसे चेहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो उन्हें अलग लगता है। यह बदलाव आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है।

**कांतिलाल मांडोत**, टिप्पणीकार

# जनता के मुद्दे पर मुखर हो विपक्ष

राजनीतिक विचारधारा की लोकप्रियता और अलोकप्रियता उनकी ग्राह्यता और उदारता से सर्वाधिक प्रभावित होती है। हठधर्मिता और आत्ममुग्धता अलोकप्रिय होने के बड़े कारण हैं। खासकर, जब नेतृत्व हठधर्मिता की जद में आ जाए, तो संभालना मुश्किल होता है। वह न तो अपनी गलतियां सुधारता है, न प्रतिद्वंद्वी की कुशलता को स्वीकार करता है। नतीजतन, न आगे की तैयारी हो पाती है, न पीछे का विश्लेषण।

पिछले कुछ वर्षों से भारत के तमाम राजनीतिक दलों, विशेषकर विपक्ष की स्थिति लगभग ऐसी ही रही है। कांग्रेस, वाम दल, सपा, राजद, टीएमसी- सबके लगभग एक जैसे राग हैं। चुनाव जीतने या हारने के बाद ये पार्टियां किसी भी मुद्दे पर बहुत अधिक दिनों तक मुखर नहीं दिखतीं और न ही किसी मुद्दे को निर्णायक बनाकर जनता से जुड़ पा रही हैं। बार-बार हारने के बाद भी उनको जनता से दूरी का एहसास नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि वे पराजय को स्वीकार नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि संघ और आनुषंगिक संगठन के साथ लंबे समय से सत्ता में बने रहने की विशेष सुविधा है, इसलिए वह इससे उबर जाती है। यही कारण है कि आज राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा बन गया है कि कोई भी चुनाव हो, परिणाम आने के बाद जिम्मेदारियों से भागना राजनीतिक कौशल गिना जाने लगा है। यह दलों और नेताओं को महंगा पड़ रहा है।

वे चुनाव से पहले शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं और फिर परिणाम विपरीत आने पर फिर से नए शॉर्टकट से निकल भागना चाहते हैं। किसी भी चुनाव के बाद एक ही आलाप! जीते तो खुद की पीठ थपथपाई और हारे तो धांधली का आरोप लगाकर जिम्मेदारी मुक्त हो गए।

देश में कोई संस्था नहीं बची है, जिस पर आरोप नहीं लगा है। किंतु इसका फायदा कब और क्या मिला? क्या जनांदोलन हो गया? दरअसल, ईवीएम, वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता से नहीं जुड़ रहे। कार्यकर्ता भी नेता की 'हां' में 'हां' तो मिलाते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। आशाहीन और ऊर्जाहीन कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ बन रहे हैं। उन्हें नेतृत्व से उम्मीद है, पर उनमें विश्वास नहीं। जबकि, पर्याप्त अवसर और बहुतेरे विकल्प बचे हैं। जहां कहीं थोड़ी मेहनत हुई, मुद्दे की राजनीति हुई, वहां दलों, क्षत्रपों ने पूर्णरूपेण अथवा आंशिक वापसी की है। यही कारण है कि आज राजनीतिक हितों के आरोप मुखर हैं और जनता के मुद्दे गौण। इसलिए फिलहाल देश में किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं दिख रही। जनता इसी अनुरूप जनादेश सुना रही है।

**ओंकार कश्यप**, टिप्पणीकार

## चिंतन

# ममता इस्तीफा दे देतीं तो गरिमा बनी रहती

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यह उनकी हताशा को दर्शाता है। ऐसा करके उन्होंने अपनी गरिमा को ही कम किया है। हालांकि तकनीकी रूप से उनके इस्तीफा देने या न देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ममता केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही यह सारा नाटक कर रही हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता। वास्तविकता यह है कि अगर उन्होंने अपने शासनकाल में जनता की समस्याओं के हल करने और सुविधाएं देने में दिलचस्पी दिखाई होती तो आज उन्हें इस तरह से हार का सामना न करना पड़ता। लोकतंत्र में हार-जीत होती रहती है। विजय को नम्रता और हार को बड़प्पन के साथ स्वीकार करने से व्यक्ति की गरिमा और विश्वास बना रहता है और यही भारतीय राजनीति की पहचान रही है। ममता पहले भी विपक्ष में रहते हुए आक्रामकता के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन चुनाव में हार पर उनकी आक्रामता राज्य के लोगों का अपमान है। हार के लिए केंद्र सरकार, एसआईआर, चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों को दोषी ठहराया जाना सरासर गलत है। ममता ने ऐसा करने के बजाय उन लोगों पर अंकुश लगाया होता जो प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ रहे थे, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और तमाम सरकारी योजनाओं के लिए कमीशन (कट मनी) वसूल रहे थे तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। इस बार चुनाव के दौरान हिंसा न के बराबर रही। इसलिए यह कहना कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, नितांत हास्यास्पद है। जहां तक एसआईआर का सवाल है तो यह बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हुई है। ममता ने खुद एसआईआर को लेकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वह किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर पूरा करवाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। बता दें कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ चुके हैं। बंगाल में भाजपा ने 293 में से 207 सीटें जीत ली हैं। पार्टी 9 मई को राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। ममता की टीएमसी सिर्फ 80 सीटें जीत सकी। 15 साल बाद ममता के हाथ से सत्ता चली गई है। मंगलवार को कोलकाता में ममता ने आरोप लगाए कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। चुनाव आयोग असली विलेन है। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटीं। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूं। कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं। हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। अब ममता विपक्ष को एकजुट करके अपनी राजनीति चला सकती हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पश्चिम बंगाल से विदाई हो चुकी है और ममता इसे बड़प्पन के साथ स्वीकार करें और गरिमामय तरीके से कार्यालय छोड़ दें। कुल मिलाकर लोकतंत्र में हार-जीत स्वाभाविक है, लेकिन उसे स्वीकार करने का तरीका ही किसी नेता की असली पहचान तय करता है। नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक परिपक्वता अधिक महत्वपूर्ण होती है। गरिमा बनाए रखने के लिए संतुलित प्रतिक्रिया और आत्ममंथन जरूरी है। आरोप-प्रत्यारोप से स्थिति सुधरती नहीं, बल्कि जनविश्वास कमजोर होता है। ऐसे समय में शांत, जिम्मेदार और सकारात्मक रुख अपनाना ही बेहतर नेतृत्व का संकेत होता है, जो भविष्य की राजनीति के लिए भी मजबूत आधार तैयार करता है।

चुनाव परिणाम

विकेश कुमार बडोला

# तुष्टिकरण की विदाई, राष्ट्रवाद का उदय

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों ने लोकतांत्रिक सत्ता की नैतिकता व लोकनिष्ठा की नूतन स्थापना कर दी है। भारत की लोकतांत्रिक, धार्मिक, हिन्दू जन-मन की आस्थागत दशा के अनुरूप बंगाल के चुनाव परिणाम अति उत्साहजनक हैं। गत पंद्रह वर्षों के शासन में तृणमूल एवं इसकी मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान, लोकतंत्र, हिंदू धर्मदर्शन, गरीब हिंदुओं के दमन तथा अवैध घुसपैठिए मुस्लिमों को वोटबैंक बनाने के लक्ष्य के साथ जो भी राजनीतिक खटकर्म किए, उनसे न केवल पश्चिम बंगाल अपितु समग्र हिंदुस्तान अत्यंत व्यथित था। आज राज्य में जो निष्पक्ष मतदान और मतगणना संभव हुई, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सत्तारूढ़ होने का प्रथम अवसर प्राप्त कर पाई है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों ने लोकतांत्रिक सत्ता की नैतिकता व लोकनिष्ठा की नूतन स्थापना कर दी है। बंगाल में कुल 293 में से 206 निर्वाचन-क्षेत्रों में भाजपा, 81 में तृणमूल, 2 में कांग्रेस, 2 में वामदल, 2 में अन्य विजयी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा बहुमत के लिए आवश्यक 147 से कहीं अधिक निर्वाचन-क्षेत्र जीतकर सत्तारूढ़ होने जा रही है। मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन-क्षेत्र में पराजित हुईं। उनके पूर्व सहयोगी एवं अब भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 15,105 मतों के अंतर से पराजित किया। भारत की लोकतांत्रिक, धार्मिक, हिन्दू जन-मन की आस्थागत दशा के अनुरूप बंगाल के चुनाव परिणाम अति उत्साहजनक हैं। गत पंद्रह वर्षों के शासन में तृणमूल एवं इसकी मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान, लोकतंत्र, हिंदू धर्मदर्शन, गरीब हिंदुओं के दमन तथा अवैध घुसपैठिए मुस्लिमों को वोटबैंक बनाने के लक्ष्य के साथ जो भी राजनीतिक खटकर्म किए, उनसे न केवल पश्चिम बंगाल अपितु समग्र हिंदुस्तान अत्यंत व्यथित था। आज चुनाव आयोग व केंद्रीय शासन के प्रयासों द्वारा राज्य में जो निष्पक्ष मतदान और मतगणना संभव हुई, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सत्तारूढ़ होने का प्रथम अवसर प्राप्त कर पाई है। भाजपा की ही राजनीतिक दृष्टि के साथ असम के चुनावी परिणाम देखें तो असम के कुल 126 निर्वाचन-क्षेत्रों में से भाजपा 102 पर, कांग्रेस 21 पर एवं अन्य 3 पर विजयी हुए। यहां भी भाजपा ने बहुमत की संख्या 64 से कहीं अधिक क्षेत्रों में विजय प्राप्त की है। पुडुचेरी के कुल 30 निर्वाचन-क्षेत्रों में से भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 18 पर, कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 6 पर तथा अन्य 6 पर विजयी हुए। यहां भी भाजपा के बहुमत की संख्या 16 से दो क्षेत्रों में आगे रही। भगवा रंग में रंगे पश्चिम बंगाल, असम व पुडुचेरी में भाजपा के मत प्रतिशत को देखें तो यह क्रमशः 45.84, 37.81 व 12.19 प्रतिशत रहा।

यद्यपि असम में भाजपा को अकेले ही बहुमत के आंकड़े से अधिक क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई, तथापि वह राजनीतिक गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए अपने सहयोगियों के साथ निरंतर तीसरी बार शासन की स्थापना करेगी। यह अत्यंत विचारणीय एवं प्रशंसनीय तथ्य है। जहां पश्चिम बंगाल, असम व पुडुचेरी में भाजपा शासन पर विराजमान होगी, वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु एवं केरल में से अभी केवल केरल में ही सत्तारूढ़ होने वाले दलों की स्थिति स्पष्ट है। यहां कांग्रेस अपने सहयोगी गठबंधन यूडीएफ के साथ सत्तासीन होने जा रही है। राज्य के कुल 140 निर्वाचन-क्षेत्रों में से कांग्रेस व यूडीएफ गठबंधन को 99 पर, सत्तारूढ़ एलडीएफ को 35 पर, भाजपा एवं अन्य दलों को 3-3 निर्वाचन-क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई है। यहां बहुमत के लिए आवश्यक 71 अंकों के आधार पर कांग्रेस व यूडीएफ गठबंधन सत्ताधारण करेगा। तमिलनाडु के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे। सत्तारूढ़ डीएमके को कुल 234 निर्वाचन-क्षेत्रों में से मात्र 65 पर विजय प्राप्त हुई, जबकि दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय का नवगठित राजनीतिक दल तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) 107 निर्वाचन-क्षेत्रों में विजयी हुआ है, जो बहुमत के 118 अंकों से 11 कम है।

एआईएडीएमके, जो भाजपा का सहयोगी राजनीतिक गठबंधन है, वह 51 निर्वाचन-क्षेत्रों में विजयी हुआ है। अन्य दलों को 11 क्षेत्रों में जीत मिली है।

तमिलनाडु के संदर्भ में विचारणीय यह होगा कि टीवीके किसके समर्थन द्वारा सत्तारूढ़ होगा अथवा यह किसका समर्थन लेकर शासन स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेगा। तमिलनाडु में 234 में से केवल 1 निर्वाचन-क्षेत्र में ही भाजपा विजय प्राप्त कर सकी है, जबकि 2021 में भाजपा यहां 4 क्षेत्रों में विजयी हुई थी। यहां भाजपा का मत प्रतिशत लगभग 2.1 से 3 प्रतिशत के बीच रहा। इसके विपरीत, केरल में कुल 140 में से 3 निर्वाचन-क्षेत्रों में भाजपा विजयी हुई। यहां भाजपा का मत प्रतिशत 11.42 प्रतिशत रहा। तमिलनाडु की तुलना में केरल में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कई अर्थों में अभूतपूर्व रहे। प्रथम तो यही है कि बड़े राज्यों, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु की जनता ने वर्षों से सत्तारूढ़ रहे राजनीतिक दलों व इनके नेतृत्वकर्ताओं पर अविश्वास प्रदर्शित करते हुए उन्हें सत्ताच्युत कर दिया। इन दोनों ही राज्यों में हिंदू कारक महत्वपूर्ण रहा। जहां बंगाल में तृणमूल की ममता ने हिंदुओं की कीमत पर मुस्लिमों के तुष्टिकरण को प्राथमिकता दी थी, वहीं तमिलनाडु में स्टालिन ने हिंदुओं व हिंदू धर्म के अपमान का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा था। इसकी परिणति यह रही कि आज जनता ने न केवल इन मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक दलों, अपितु दोनों मुख्यमंत्रियों को भी पराजित करने के लिए मतदान किया है। यदि समग्रता में देखें तो लोकतांत्रिक चुनाव की इस प्रक्रिया में हिंदुओं के भीतर सुलगती रही अपमान की लहर ने दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक स्थापित राजनीतिक शक्तियों को बुरी तरह धराशायी कर दिया है। विजयी राजनीतिक दल, उनके नेता तथा केंद्र में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री एवं अन्य नेता तक, यह कदापि न भूलें कि चुनाव आयोग को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ कार्य करने देने के परिणामस्वरूप ही आज बंगाल में वामपंथ व तृणमूल के कुशासन तथा तमिलनाडु, असम व पुडुचेरी में द्रविड़ों एवं कांग्रेसियों की बहुविध तुष्टिकरण की राष्ट्रघाती राजनीति का पतन हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व एसआईआर अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण का जो अस्त्र चुनाव आयोग ने प्रयोग किया था, वह इस बार पश्चिम बंगाल में भी अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सफल रहा। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में सत्तारूढ़ होने जा रही भाजपा को शासन चलाते समय इस बिंदु को अवश्य ध्यान में रखना होगा कि उनकी सत्ताप्राप्ति का माध्यम घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई का उनका वचन था, जिसका राजनीतिक व शासकीय पालन अब हर हाल में भाजपा को करना ही होगा। पश्चिम बंगाल, असम व पुडुचेरी में सर्वथा क्रांतिकारी ढंग से तथा बहुसंख्यक हिंदुओं के हित में शासकीय निर्णय लिए जाने की अति आवश्यकता है, यह बात भाजपा के शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक कार्यरत नेताओं व कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलनी है। यह जनादेश केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि उस छद्म धर्मनिरपेक्षता की पराजय है, जिसने सदैव बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक संवेदनाओं को हाशिए पर रखा।

यह राजनीतिक उथल-पुथल प्रमाणित करती है कि लोकनिष्ठा को खंडित कर सत्ता का संचालन अब संभव नहीं। भारतीय मतदाता अब तुष्टिकरण की राष्ट्रघाती नीतियों और हिंदू धर्मदर्शन के अपमान को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। विजयी दलों के लिए यह अवसर आत्ममुग्धता का नहीं, बल्कि उन संकल्पों को सिद्ध करने का है जो उन्होंने घुसपैठ और सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के लिए किए हैं। अंततः, यह लोकतंत्र की वह नूतन स्थापना है जहां राष्ट्र प्रथम का विचार ही सर्वोपरि है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

## मंथन

डॉ. नीलू तिवारी

# पैरानॉयड डिसऑर्डर : खामोश संकेत और बड़ा खतरा

कभी-कभी एक खबर सिर्फ सूचना नहीं होती, बल्कि समाज के भीतर छिपी किसी गहरी दरार को उजागर कर देती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटी वह घटना जहां एक पिता ने अपनी ही जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी, ऐसी ही एक सच्चाई को सामने लाती है। जानकारी के अनुसार वह अपनी पत्नी पर शक करता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल "शक" था या फिर एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसे हमने समय रहते पहचाना ही नहीं? हम आज भी भावनात्मक असुरक्षा और मानसिक बीमारी के बीच के अंतर को समझने में चूक रहे हैं। पैरानॉयड डिसऑर्डर केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है, जहां व्यक्ति का मन धीरे-धीरे अपने ही बनाए संदेहों की कैद में बंद हो जाता है। उसे हर चेहरा संदिग्ध लगता है, हर व्यवहार में धोखा दिखाई देता है और हर रिश्ता असुरक्षित प्रतीत होता है। यह केवल सोच नहीं बल्कि एक विकृत यथार्थ है, जिसमें व्यक्ति जीने लगता है। ऐसे में उसके निर्णय तर्क से नहीं, बल्कि डर और भ्रम से संचालित होते हैं और यही स्थिति कभी-कभी त्रासदी का रूप ले लेती है। पैरानॉयड डिसऑर्डर की एक बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति खुद को बीमार नहीं मानता। उसे लगता है कि उसकी सोच सही है और बाकी लोग गलत हैं। यही कारण है कि वह इलाज से बचता है और परिवार भी कई बार इसे "जिद" या "स्वभाव" समझकर नजरअंदाज कर देता है। धीरे-धीरे यह स्थिति और गंभीर हो जाती है। पुरुषों में यह विकार अक्सर अधिकार और नियंत्रण के रूप में सामने आता है। पत्नी की स्वतंत्रता, उसकी बातचीत, उसके संबंध हर चीज पर संदेह करना, धीरे-धीरे एक आदत नहीं बल्कि मानसिक जकड़न बन जाता है। समस्या तब और गहरी हो जाती है जब समाज इस व्यवहार को "सामान्य" या "पुरुष स्वभाव" कहकर स्वीकार कर लेता है। यही सामाजिक स्वीकृति इस विकार को पहचानने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उत्तर प्रदेश की घटना इसी अनदेखी का चरम परिणाम है, जहां शक ने संवेदना को निगल लिया।

महिलाओं के संदर्भ में भी यह समस्या कम गंभीर नहीं है। कई बार महिलाएं भी पैरानॉयड सोच का शिकार हो जाती हैं, जहां वे अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर बिना कारण संदेह करने लगती हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस जैसी अवस्था में कुछ महिलाओं में पैरानॉयड विचार विकसित हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि कोई उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा या परिवार उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस मानसिक भ्रम के कारण वे असामान्य और कभी-कभी खतरनाक व्यवहार कर सकती हैं। देश और दुनिया में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां मानसिक असंतुलन के कारण मां ने अपने ही बच्चे को नुकसान पहुँचाया। हालिया रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत में पुरुषों द्वारा मानसिक हेल्पलाइन पर कॉल करने की संख्या में 126% की वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी कुल मदद लेने वालों में उनकी हिस्सेदारी कम है। यानी समस्या मौजूद है पर उसे स्वीकार करने में झिझक अब भी बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति भी अलग नहीं है, बल्कि कई मामलों में और जटिल है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक विकारों विशेषकर डिप्रेशन और एंग्जायटी की दर महिलाओं में पुरुषों से अधिक पाई जाती है। यहां इस लेख की सबसे बड़ी प्रासंगिकता सामने आती है। हम आज भी शक और मानसिक बीमारी के बीच का फर्क समझने में चूक रहे हैं। हम "शक" को एक सामान्य भावना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं जबकि कई बार यह एक गंभीर मानसिक विकार का संकेत होता है। यही अनदेखी धीरे-धीरे समस्या को गहरा करती है और अंततः किसी बड़ी त्रासदी का कारण बनती है। लोग आज भी मनोचिकित्सक के पास जाने से डरते हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तो मानसिक बीमारी को कई बार अंधविश्वास या "किस्मत" से जोड़ दिया जाता है। यही सोच लोगों को सही इलाज से दूर रखती है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक चुनौती है। अगर हम समय रहते मानसिक समस्याओं को नहीं समझेंगे तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अंततः यह समझना जरूरी है कि जब मन बीमार होता है, तो उसका असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समाज को प्रभावित करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आसपास के लोगों के मन को समझने की कोशिश करें। उनके व्यवहार के पीछे छिपे संकेतों को पहचानें और सबसे बढ़कर एक ऐसा समाज बनाएं, जहां विश्वास, संवाद और मानसिक स्वास्थ्य को बराबर महत्व मिले। दरअसल, जब मन संतुलित होता है, तो रिश्ते सुरक्षित रहते हैं और जब मन संदेह में डूब जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

# क्या आप पूर्ण रूप से सुखी है

संकलित

दर्शन

वर्ष 1920 में योगानंद जी जब अमेरिका गए थे, तो उस समय अमेरिका पूरे उत्साह में था। उस समय वह पूंजीवाद के अपने दर्शन को लेकर तेजी से प्रगति कर रहा था। योगानंद जी अनेक सफल व्यवसायियों और औद्योगिक संस्थानों के प्रमुखों इत्यादि से मिले और उन सबने यह स्वीकार किया कि योगानंद जी उनके मध्य उस वस्तु को लेकर आए थे, जिसकी उनके जीवन में कमी थी। मैं आपको एक छोटा-सा मनोरंजक वृत्तांत सुनाता हूं : जब वे न्यू यार्क नगर में व्याख्यान दे रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे भेंट करने की अनुमति मांगी। वह व्यक्ति उनके होटल के कमरे में आया और इससे पूर्व कि योगानंद जी कुछ कहते, उसने एक चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा, 'मैं अत्यधिक धनवान हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं,' जिसका अर्थ यह था कि 'आप यहां किसलिए आए हैं?' योगानंद जी ने उसे तुरंत उत्तर दिया, 'हां, किंतु क्या आप पूर्ण रूप से सुखी हैं?' बाद में उस व्यक्ति ने कहा, 'मैं निरुत्तर हो गया था!' उस व्यक्ति ने अपना शेष जीवन एक क्रियायोगी के रूप में व्यतीत किया। बाह्य रूप से वह करोड़पति उद्योगपति था, परंतु अंदर से वह एक प्रबुद्ध योगी था। यह कह पाना और एक अद्भुत अनुभूति है कि ईश्वर की इच्छाशक्ति से सशक्त हुई मेरी इच्छाशक्ति मेरे लक्ष्य को पूरा करेगी। यदि आप आलसवश सब कुछ दिव्य शक्ति पर छोड़ देते हैं और ईश्वर द्वारा आपको दी गई अपनी इच्छाशक्ति की अवहेलना करते हैं तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

# दूसरों की जरूरतें पूरी करना ही दान है

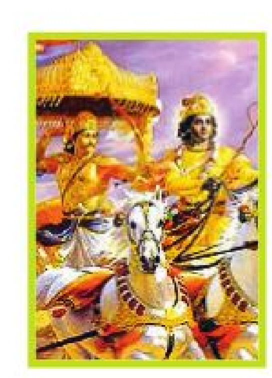

संकलित

प्रेरणा

महाभारत का एक प्रसंग है। एक दिन युधिष्ठिर ने वेद व्यास से पूछा कि दान बड़ा है या पूजा-पाठ और तपस्या? व्यास जी ने युधिष्ठिर को अपनी बात समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के महर्षि थे, वे भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे। भिक्षा में उन्हें आटा, खाने-पीने की चीजें, हवन सामग्री मिल जाती थीं। दान में मिली चीजों से ही वे खाना बनाते और पूजा-पाठ करते थे। कभी-कभी ऐसे दिन भी आते थे, जब उन्हें भिक्षा नहीं मिल पाती थी। अधिकतर अमावस्या और पूर्णिमा पर ऐसा हुआ करता था। इन दोनों तिथियों पर ऋषि मुद्गल से मिलने दुर्वासा ऋषि आया करते थे। दुर्वासा मुनि को खाना खिलाने के बाद उनके लिए कुछ बचता नहीं था तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ तो दुर्वासा मुनि ने मुद्गल ऋषि से पूछा कि आप मुझे खाना देकर खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके चेहरे पर भूख के लक्षण नहीं देखे हैं, क्या आपको भूख नहीं लगती है? मुद्गलजी ने कहा कि मेरे लिए दान का महत्व सबसे ज्यादा है। अन्न दान तो सर्वश्रेष्ठ होता है, जब आपकी भूख शांति होती है, तब मैं भी तृप्त हो जाता हूं। मैं दान पुण्य कमाने के लिए नहीं करता हैं, मैं सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता हूं। व्यास जी ने युधिष्ठिर को आगे समझाया कि तपस्या स्वयं के लिए की जाती है, लेकिन दान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। इसलिए दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना ही दान है। इसलिए दान तप से भी श्रेष्ठ है।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### खतरनाक गर्मी का बढ़ता संकट

दुनिया के शहरों पर एक ऐसा संकट तेजी से गहराता जा रहा है, जो दिखाई कम देता है, लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है- खतरनाक गर्मी। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक शहरी इलाकों में अत्यधिक गर्मी से प्रभावित गरीबों की संख्या में लगभग 700 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले शहरी भविष्य की भयावह तस्वीर है, खासकर ग्लोबल साउथ, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए। गर्मी का यह संकट सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज और अनियोजित शहरीकरण से जुड़ा है। शहरों में कंक्रीट, डामर और धातु की अधिकता प्राकृतिक हरियाली को खत्म कर देती है। इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

- प्रदीप चन्द्राकर, जगदलपुर

## ट्रेंड

### हम यूएई के साथ

यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए है। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। भारत यूएई के साथ पूरी तरह एकजुट है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

### जनादेश की चोरी

कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हे यह बात समझनी चाहिए - असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

### नारी शक्ति का अपमान

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले नेताओं, विरोध करने वाली पार्टियों को आज उनकी औकात दिखा दी गई है। डीएमके के स्टालिन हों, ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल। नारी शक्ति का अपमान करने वाला हर व्यक्ति आज जवाब देने में असमर्थ है।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

### लोकतंत्र विरोधी ताकतें

आज मैंने पंजाब के विधायकों से बातचीत की। आम आदमी पार्टी राष्ट्रहित में लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब की जनता आगामी चुनावों में भाजपा के अश्वमेध घोड़े को रोकेगी और लोकतंत्र की विजय सुनिश्चित करेगी।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

## करंट अफेयर

# महिला संरा प्रमुख चुनी जाती है तो 'बेहद खुशी' होगी : चीन

चीन ने संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के लिए किसी महिला की नियुक्ति का यह कहते हुए खुलकर समर्थन किया कि अगर इस बार कोई महिला इस शीर्ष पद पर आसीन होती है तो उसे 'बेहद खुशी' होगी। संयुक्त राष्ट्र के 80 साल के इतिहास में अभी तक कोई महिला इस पद पर नहीं पहुंच सकी है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत फू कोंग ने सोमवार को कहा, 'हम किसी महिला को महासचिव के रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। 80 साल हो गए हैं-अगर इस बार कोई महिला महासचिव बन सकती है तो चीन इसका स्वागत करेगा।' संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पद की दौड़ में दो महिलाओं समेत अभी चार उम्मीदवार हैं। पहली महिला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशेलेट और दूसरी महिला संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की महासचिव रेबेका ग्रिन्सपान हैं। पुरुष उम्मीदवारों में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख राफेल ग्रोसी और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी सॉल शामिल हैं। पिछले महीने चारों उम्मीदवारों ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और नागरिक संगठनों के सामने अपना-अपना दृष्टिकोण रखा और यह भी बताया कि वे इस शीर्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त क्यों हैं।

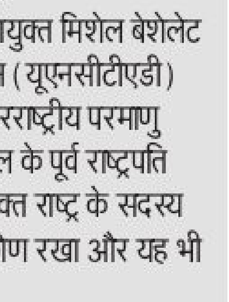

## ऑफ बीट

# क्या परीक्षा प्रणाली बच्चों को कौशल सीखने से रोक रही ?

दुनिया भर में, खासकर अफ्रीका में, शिक्षा प्रणालियां ऐसे पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ रही हैं जो रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान जैसे कौशल विकसित करने पर जोर देते हैं। योग्यता-आधारित यानी कॉम्पीटेन्सी बेस्ड पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र में रखना है। इनका लक्ष्य छात्रों को एक तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करना है, जहां सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितनी जल्दी खुद को ढाल सकता है, सोच सकता है और जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। पारंपरिक पाठ्यक्रमों के विपरीत, जो अक्सर तथ्यों को याद करने और विषयवस्तु को पूरा करने पर जोर देते हैं, ये नए पाठ्यक्रम इस बात पर केंद्रित हैं कि छात्र जो सीखते हैं उसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, केवल वैज्ञानिक परिभाषा याद करने के बजाय छात्रों से यह पूछा जा सकता है कि वे किसी अवधारणा का उपयोग करके यह समझाएं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। हालांकि इस बदलाव पर चर्चा में अक्सर शिक्षकों की तैयारी, संसाधनों की कमी और पाठ्यक्रम के सही क्रियान्वयन जैसी चुनौतियों पर ध्यान दिया जाता है लेकिन ये सभी कारण पूरी तस्वीर नहीं बताते।

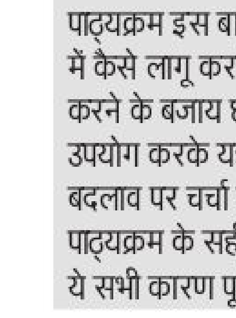

## अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

# प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ● आगरा

अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मामला बेहद सूक्ष्म और नाजुक होता है। -व्लादिमीर जिरिनोव्स्की

**लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को लेकर नेपाल पहले भी आवाज उठाता रहा है, लेकिन इस बार उसका स्वर अधिक औपचारिक और दृढ़ है। काठमांडो ने कूटनीतिक संवाद की इच्छा जताई जरूर है, पर अगर वह वाकई समाधान चाहता है, तो उसे व्यावहारिक ढंग से पेश आना होगा।**

## दर्रे पर दरार

हाल ही में लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोबारा खोलने की भारत की घोषणा और उस पर नेपाल की नई बालेन सरकार द्वारा आपत्ति जताना, भारत और नेपाल के बीच समय-समय पर उभरते तनाव की उसी कड़ी का हिस्सा है, जो पहले भी दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में कूटनीतिक खटास पैदा करती रही है। दरअसल, नेपाल का तर्क पुराना है, पर इस बार उसका स्वर अधिक औपचारिक व दृढ़ है। काठमांडो का कहना है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी महाकाली नदी के पूर्व स्थित वे क्षेत्र हैं, जो 1816 की सुगौली संधि के अनुसार नेपाल का हिस्सा हैं, और भारत व चीन बगैर उसकी सहमति के इस क्षेत्र को तीर्थ व व्यापार मार्ग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए, तब भी नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कालापानी को अपना क्षेत्र बताया था। भारत का पक्ष भी उतना ही स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश-मानसरोवर यात्रा कोई नई व्यवस्था नहीं, बल्कि 1954 से प्रचलित परंपरागत मार्ग है। भारत के लिए यह केवल धार्मिक यात्रा का प्रश्न नहीं, बल्कि उत्तराखंड से तिब्बत तक जुड़ा एक पुराना संपर्क बिंदु भी है, जिसे वह प्रशासनिक व ऐतिहासिक रूप से अपना मानता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी की काठमांडो यात्रा प्रस्तावित है। ऐसे में, यह विवाद केवल एक सीमा-रेखा का नहीं, बल्कि भारत-नेपाल संबंधों की संवेदनशीलता, पड़ोस नीति की परिपक्वता और हिमालयी भू-राजनीति की जटिलताओं से जुड़ा प्रश्न भी बन गया है। समस्या केवल दावों और प्रतिदावों की नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे विवादों का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। भारत-नेपाल संबंधों की प्रकृति किसी सामान्य पड़ोसी देशों जैसी नहीं है। खुली सीमा, रोटी-बेटी का रिश्ता, गहरी सांस्कृतिक निकटता और सामरिक परस्परता, ये सभी दोनों देशों को अनिवार्य साझेदार बनाते हैं।

यही वजह है कि दोनों के बीच सीमा विवाद, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, राजनीतिक रूप से बहुत जल्दी भावनात्मक रूप ले लेता है। नहीं भूलना चाहिए कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही भारत ने कालापानी में चौकियां स्थापित कीं और वहां से कभी हटा भी नहीं। नेपाल ने भी पूर्ववर्ती ओली सरकार से पहले दशकों तक इस मामले में चुप्पी साधे रखी। अब बालेन सरकार ने भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता जारी रखने की मंशा जताई है, लेकिन अगर काठमांडो वास्तव में समाधान चाहता है, तो उसे घरेलू राजनीति से ऊपर उठकर व्यावहारिक ढंग से संवाद की दिशा में बढ़ना होगा।

## तलाक के कगार पर

**ट्रंप का नाटो को 'कागजी शेर' कहना और यूरोपीय नेताओं की ईरान युद्ध पर असहमति के चलते अमेरिका व यूरोप के बीच दशकों पुराने रिश्ते अब दरकते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि यदि यह दोस्ती टूटती है, तो दोनों में से किसका नुकसान अधिक होगा?**

बीते कुछ समय से अमेरिका व यूरोप के बीच घट रही घटनाओं तथा इस माहौल में निर्मित वैचारिकी में निहित असहमतियां अब टकराव तक पहुंचती हुई दिख रही हैं। पश्चिम के इस 'लव और हेट' के बीच एक प्रश्न उभरने लगा है कि क्या दोनों के बीच तलाक का वक्त नजदीक आ चुका है? एक सवाल और कि यदि ऐसा हुआ, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा?

थोड़ा अतीत की ओर देखें, फिर वर्तमान में आएं तो पता चलेगा कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को अपना सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया था। इस दिशा में पहला कदम था-1948 में अमेरिकी वायुसेना का लाकेनहीथ (ब्रिटेन) पहुंचना और दूसरा था 1950 के दशक के आरंभ में जर्मनी के रामस्टीन एयर बेस का निर्माण। इसके बाद सिलसिला बढ़ता गया और यूरोप अमेरिकी सामरिक रणनीतिक का महत्वपूर्ण घटक बन गया। इसी का परिणाम है कि आज यूरोप में 40 से अधिक अमेरिकी सैन्य बेस हैं, जहां लगभग 85,000 सैनिक तैनात हैं। यहां एक बात समझने वाली है कि जब अमेरिकी नेतृत्व में पूंजीवादी शक्तियां सोवियत संघ के विरुद्ध शीतयुद्ध से गुजर रही थीं, तब नाटो के तहत इस तरह की सैन्य तैयारियां तर्कसंगत हो सकती थीं और अपेक्षित भी, पर 1991 में सोवियत संघ के बिखरते ही पूर्वी (साम्यवादी) संगठन, यानी वारसा पैक्ट खत्म हो गया, फिर भी नाटो को बनाए रखा गया, क्यों?

**रहीस सिंह**

*अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार*

जब फ्रांसिस फुकुयामा से *द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन* नाम की पुस्तक लिखवाकर 'इतिहास के अंत' का जोर-शोर से प्रचार कर दिया गया, तो डर किस बात का था, जिस कारण नाटो आवश्यक बना रहा? क्या नाटो वास्तव में उनकी रक्षा के लिए अस्तित्व में रहा या फिर वैश्वीकरण की आड़ में नवउपनिवेशवाद को स्थापित करने का एक माध्यम? अब राष्ट्रपति ट्रंप इसे 'कागजी शेर' बता रहे हैं, क्यों? इसलिए

कि यह शेर अब बूढ़ा हो गया है या फिर यह शेर अब अपने सनकी मास्टर के अनुसार हमला नहीं कर रहा है? यहां ध्यान देना जरूरी है कि जब अर्थव्यवस्थाएं युद्धजनित हो जाएं और युद्ध ही उन्हें निर्देशित करने लगें, तो यूरोप के देश पहले अपने लोगों की जिंदगियों की चिंता करें अथवा बूढ़े शेर के भोजन की? ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा और उनका 'मागा' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) का सपना उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा। ईरान युद्ध ने इसे बेनकाब कर दिया और ट्रंप बे-आबरू होकर वहां से निकलना नहीं चाहते। चूंकि, अमेरिका के अंदर ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, इसलिए उनकी सनक का गुब्बारा कहीं तो फूटना चाहिए, जो शायद यूरोप पर फूटे और यही तलाक का कारण भी बने।

अमेरिका व यूरोप ने जिन संबंधों की ठोस बुनियाद 1930 और 1940 के दशक में रखी थी, शीतयुद्ध के दौर में उसे मजबूती मिली तथा उसके खत्म होने के बाद भी, विशेषकर वार इंड्यूरिंग फ्रीडम के असफल होने से पहले तक। पर राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सब कुछ अवसरों के अर्थशास्त्र (इकनॉमिक्स ऑफ अपार्चुनिटी) के समीकरणों पर निर्भर होता है। शायद यूरोप ट्रंप के इस अर्थशास्त्र पर खरा नहीं उतर पा रहा। ट्रंप अभी तक जिसे अपनी ही बिल्ली समझ रहे थे, वही अब उनके सामने म्याऊं बोले, यह कैसे हो सकता है। इसलिए, ट्रंप ने अपने यूरोपीय साझेदारों को 'कायर' करार दिया और नाटो को 'कागजी शेर'। एक यूरोपीय अखबार तो यहां तक लिखता है कि ट्रंप प्रशासन इस पर भी विचार कर रहा है कि ईरान युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोपीय सहयोगियों को दंडित किया जाए और स्पेन को नाटो से बाहर कर दिया जाए और फॉकलैंड द्वीपों पर ब्रिटिश संप्रभुता की मान्यता वापस ले ली जाए। पर ट्रंप प्रशासन भूल रहा है कि तनाव में केवल वही नहीं, यूरोप भी है।

वैसे, यूरोपीय नेता सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए देखे गए हैं कि ईरान युद्ध उनकी सहमति के बिना और गलत ढंग शुरू किया गया है। और इसे अवैध भी माना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी कमांडर इन चीफ खुद की मसीहा जैसी तस्वीरें पोस्ट करते हुए पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, जो अमेरिकी नेतृत्व में यूरोपीय भरोसे को और कम करता है या यूं कहें कि ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंचा देता है। क्यों न हो? अमेरिका द्वारा यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाना और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देना, क्या वास्तव में अजीब संभावनाएं पैदा नहीं करता? क्या ट्रंप की सनक यूरोपीय सैनिकों को अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं उकसा रही। इसी वजह से स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में अधिक लोग अमेरिका को 'करीबी सहयोगी' बजाय खतरा मानने लगे हैं। दरअसल, ट्रंप का 'मागा' एक यूटोपियाई परिकल्पना है, जिसकी पृष्ठभूमि में युद्ध एक हथियार की तरह है। ऐसी स्थिति में यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में वह शक्ति प्रदर्शन जारी रखना चाहेगा। इसलिए उसे यूरोप का सहयोग अपेक्षित रहेगा। अमेरिका वर्तमान युद्ध के दौरान राजनीतिक दिखावे के बावजूद यूरोपीय अड्डों का उपयोग भी कर रहा था। जिस दिन अमेरिका आश्वस्त हो जाएगा कि उसे अब इनकी जरूरत नहीं है, तो वह उन्हें बंद कर देगा। हाल के दशकों में अमेरिका के पश्चिम एशिया (और बाल्कन) में लगातार सैन्य हस्तक्षेपों को देखते हुए, यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि ईरान युद्ध उसकी सैन्य संलिप्तता का अंतिम उदाहरण है। फिर तो उसे यूरोप की जरूरत पड़ती रहेगी।

वैसे अमेरिका को अलविदा कहना यूरोप के लिए भी जोखिम भरा होगा। कारण यह कि रूस अब भी यूक्रेन में युद्ध कर रहा है। अगर इसके अंतिम परिणाम रूस के पक्ष में रहे, तो संभव है कि वह नाटो क्षेत्र पर भी हमला करे। यूरोप की असल चिंता यह भी है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका नाटो के सामूहिक रक्षा संबंधी सिद्धांत का अनुपालन करेगा या नहीं। नाटो महासचिव मार्क रुटे भी चेतावनी दे रहे हैं कि यूरोप अमेरिकी सहायता के बिना रूस के खिलाफ अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए वह चाहते हैं कि यूरोप ट्रंप को हर हाल में संतुष्ट रखे। यूरोप रक्षा की दृष्टि से कई मामलों में अमेरिका पर निर्भर है, इसलिए, अधिकांश यूरोपीय नेता 'एक्चुअली लव' जैसे सपने देखने में तो सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप को नाराज करने से भी बच रहे हैं।

कुल मिलाकर, अटलांटिक के दोनों पक्ष यह जान रहे हैं कि फिलहाल वे एक असंतुष्ट विवाह में बंधे हुए हैं, पर दोनों के बीच औपचारिक तलाक बेहद जोखिम युक्त कदम होगा। सच भी यही है।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

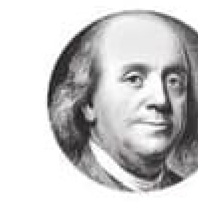

**बेंजामिन फ्रैंकलिन**

लोग जीवन में इसलिए असफल होते हैं, क्योंकि वे अपने दिन को बिना स्पष्ट उद्देश्य के व्यतीत करते हैं। यदि व्यक्ति हर दिन खुद से पूछे कि 'मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूं', तो वह अधिक रचनात्मक व अनुशासित बन सकता है।

### हर दिन एक नया अवसर होता है

*__जीवन__ में हमें रोज सुबह खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आज मैं क्या अच्छा काम करूंगा? यह सवाल हमारे पूरे जीवन-प्रबंधन, आत्म-सुधार और नैतिक अनुशासन का केंद्रीय सूत्र है। इसलिए, इसे हमें दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। मैं सुबह उठते ही खुद से सवाल करता था कि आज मुझे कौन-सा अच्छा और उपयोगी काम करना है। मेरे लिए यह सवाल सिर्फ सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि नैतिकता व आत्म-विकास का आधार था। साथ ही, समाज के लिए उपयोगी भी।*

*मेरा मानना है कि हर एक दिन हमें एक नए अवसर की तरह मिलता है। यदि वह दिन उद्देश्यपूर्ण ढंग से जिया जाए, तो हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। यही उत्कृष्टता हमारे जीवन की सफलता की नींव तैयार करती है। अच्छा जीवन बड़े आदर्शों की घोषणाओं से नहीं, बल्कि रोजाना किए गए छोटे-छोटे सार्थक कार्यों से बनता है। इसलिए, हमें हर दिन की शुरुआत आत्म-जागरूकता से करनी चाहिए। 'आज मैं क्या अच्छा काम करूंगा' यह प्रश्न हमें निष्क्रियता से बाहर लाता है और अपने दिन को सार्थक दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही, यह सवाल जीवन के प्रति सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बहता नहीं, बल्कि अपने मूल्यों व लक्ष्यों के अनुसार दिन का निर्माण करता है। याद रखें, सारे दिन की कामयाबी इस बात से मापी जानी चाहिए कि आज मैंने खुद अपने लिए और समाज के लिए कितना सकारात्मक काम किया। हमारे जीवन का हर दिन संयम, व्यवस्था, मेहनत, सत्यनिष्ठा और विनम्रता के अभ्यास का अवसर होना चाहिए। ज्यादातर लोग जीवन में असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे अपने दिन को बिना स्पष्ट उद्देश्य के व्यतीत करते हैं। यदि व्यक्ति हर दिन खुद से पूछे कि 'मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूं', तो वह अधिक रचनात्मक व अनुशासित बन सकता है। यह आदत धीरे-धीरे चरित्र का निर्माण करती है।*

*दरअसल, चरित्र कोई अचानक हासिल होने वाली चीज नहीं होती, बल्कि यह रोजाना किए गए सही फैसलों का ही समुच्चय होती है। इसी तरह रात को सोने से पहले भी हमें खुद से पूछना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया? बस फर्क यही है कि सुबह का प्रश्न संकल्प था और रात का प्रश्न आत्म-मूल्यांकन। इन दोनों के बीच पूरा दिन उद्देश्यपूर्ण जीवन का अभ्यास बन जाता है। यही आत्मनिरीक्षण सफलता का वास्तविक रहस्य है। ऐसा करते रहना हमें अपने आदर्शों के प्रति जवाबदेह बनाता है। जब मनुष्य दिन की शुरुआत इस विचार से करता है कि उसे कुछ अच्छा करना है, तो उसके निर्णय अधिक सजग और सकारात्मक होते हैं। खुद से पूछे जाने वाले ये दो सरल प्रश्न जीवन में स्पष्टता ला सकते हैं और दिन को केवल बिताने के बजाय उसे सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं।*

### खुद को चुनौती देते रहें

**सूत्र**

*जब दिन की शुरुआत संकल्प से और अंत आत्म-मूल्यांकन से होती है, तब जीवन में निरंतर सुधार संभव होता है। सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोज किए गए सकारात्मक कर्मों में छिपी होती है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को चुनौती देता है, वही अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाता है। इसलिए हर दिन को सार्थक बनाइए।*

**दूसरा पहलू**

बारहनाजा की खेती बिना लागत वाली है। इसमें फसलों की बुआई मई-जून में, जबकि कटाई सितंबर-अक्तूबर में होती है।

## खेती, जो बना रही किसानों को आत्मनिर्भर

**उत्तराखंड** के पर्यावरण कार्यकर्ता विजय जड़धारी बारहनाजा की परंपरागत फसलें न केवल उगाते हैं, बल्कि किसानों को भी उनकी खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका प्रचार-प्रसार करते हैं। जगह-जगह देसी बीजों की प्रदर्शनी लगाते हैं। इनका महत्व बताते हैं। इन पर लेख व किताबें लिखते हैं।

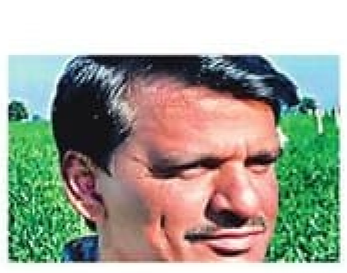

**बाबा मायाराम**

विजय जड़धारी ने अस्सी के दशक के आसपास 'बीज बचाओ आंदोलन' की भी शुरुआत की थी। इसकी प्रेरणा उन्हें 'चिपको आंदोलन' से मिली थी, जिसके वह कार्यकर्ता थे। परंपरागत देसी बीजों के लुप्त होने से चिंतित होकर उन्होंने बीजों के संरक्षण व संवर्धन का काम शुरू किया था। हेंवलघाटी के गांवों से शुरू हुई यह पहल अब देशभर में फैल चुकी है। विजय बताते हैं कि शुरुआत में जब वह गांवों में देसी बीजों की तलाश करने जाते थे, तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वह आगे कहते हैं कि बारहनाजा का शाब्दिक अर्थ बारह अनाज है, पर इसके अंतर्गत बारह से ज्यादा अनाज आते हैं। मंडुआ बारहनाजा परिवार का मुखिया कहलाता है। जब गेहूं नहीं था, तब लोग मंडुआ की ही रोटी खाते थे। पोषण की दृष्टि से यह बहुत पौष्टिक है। वह बताते हैं कि बारहनाजा मिश्रित फसल पद्धति है। इसकी फसलें अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे की सहायक हैं। बारहनाजा की फसलों की बुआई मई-जून में, जबकि कटाई सितंबर-अक्तूबर में होती है। यह बिना लागत वाली खेती है। बीज खुद किसानों का होता है, जिसे वे घर के बिजुड़े (पारंपरिक भंडार) से लेते हैं। पशुओं व फसलों के अवशेष से जैविक खाद मिल जाती है। परिवार के सदस्यों की मेहनत से फसलों की बुआई, निराई-गुड़ाई, देखरेख व कटाई आदि हो जाती है। बारहनाजा जैसी मिश्रित पद्धतियों में प्रतिकूल परिस्थिति में भी किसानों को कुछ न कुछ मिल जाता है, जबकि एकल फसलों में पूरी फसल का नुकसान होता है।

बारहनाजा का शाब्दिक अर्थ बारह अनाज है, पर इसके अंतर्गत इससे ज्यादा अनाज आते हैं। बारहनाजा परिवार का मुखिया मंडुआ है।

बारहनाजा जैसी मिश्रित पद्धतियों में प्रतिकूल परिस्थिति में भी किसानों को कुछ न कुछ मिल जाता है। इसकी फसलों की खेती से प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

कुल मिलाकर, बारहनाजा की फसलों से प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इससे पशुपालन व कृषि का समन्वय किया जा सकता है। इससे गांवों में स्थाई, टिकाऊ खेती से आजीविका व भोजन सुरक्षा की जा सकती है। दीर्घकालीन दृष्टि रखकर मिट्टी व पानी का संरक्षण भी किया जा सकता है। ऐसी पद्धतियां सूखे में भी उपयोगी हैं। ऐसी कई और मिश्रित पद्धतियां भी हैं, जो देश में अलग-अलग नामों से प्रचलित हैं। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी उपयोगी साबित हो सकती हैं।

**आंकड़े**

### सच की कीमत

समाज के गंभीर मुद्दों को उजागर करने की कीमत 'पत्रकारों' को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, फिर भी वे सच सामने लाने का साहस रखते हैं।

| | |
|---|---|
| 2013 | 145 |
| 2014 | 115 |
| 2023 | 56 |
| 2024 | 70 |
| 2025 | 60 |

आंकड़े दुनियाभर में जान गंवाने वाले पत्रकारों के, संख्या में। | स्रोत : रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

इंद्रदेव ने वर्षा रोक दी, तो अकाल पड़ गया। तब विद्वानों की सलाह पर ऋष्यशृंग को बुलाया गया। उनके आगमन से ही वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा।

## ऋष्यशृंग के तप

**पौराणिक** कथाओं के अनुसार ऋष्यशृंग, जिन्हें श्रृंगी ऋषि भी कहा जाता है, अत्यंत प्रभावशाली और तपस्वी ऋषियों में गिने जाते हैं। वह महर्षि विभांडक के पुत्र थे और उनका जन्म भी एक अद्भुत घटना से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार विभांडक ऋषि के तप के प्रभाव से उत्पन्न तेज जल में प्रवाहित हुआ, जिसे एक हिरणी ने ग्रहण किया और उसी से ऋष्यशृंग का जन्म हुआ।

ऋष्यशृंग का जीवन अत्यंत पवित्र और संयमित था। वह वन में रहकर कठोर तपस्या करते थे और सांसारिक मोहमाया से दूर रहते थे। एक समय अंगदेश के राजा रोमपद ने एक ब्राह्मण की उपेक्षा कर दी, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने वर्षा रोक दी। राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। तब विद्वानों की सलाह पर ऋष्यशृंग को बुलाया गया। उनके आगमन से ही वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा।

**अंतर्यात्रा**
संकलित

ऋष्यशृंग द्वारा किया गया यज्ञ अत्यंत विधिपूर्वक, शुद्ध मंत्रों और आस्था के साथ संपन्न हुआ। यह यज्ञ केवल वर्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रतीक था। यज्ञ पूर्ण होते ही घनघोर वर्षा हुई। ऋष्यशृंग के तप, ज्ञान और यज्ञ की शक्ति ने पूरे राज्य को पुनर्जीवित कर दिया।

**अमर उजाला**

**पुराने पन्नों से** — 6 मई, 1955

### अफगानिस्तान की पाक शासकों को गंभीर चेतावनी

हमारी बंदूकें स्वागत को तैया
अफगानिस्तान की पाकिस्तानी शासकों को गंभीर चेतावनी

**पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर लगातार हमले कर रहा है। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि पाक शासक हमसे भिड़ना ही चाहते हैं, तो हमारी बंदूकें उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।**

## नहीं मयस्सर रात को भी चैन

**फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिली है, पर अप्रैल में उसने जो तेवर दिखाए, उससे पता चलता है कि आगामी दिनों में हीट स्ट्रेस दिन के साथ रात का भी चैन छीन सकता है।**

**डॉ. सीमा जावेद** | **मुद्दा**

फिलहाल कुछ दिनों से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले महीने उसने जो तीखे तेवर दिखाए, उससे यही पता चलता है कि आने वाले समय में हीट स्ट्रेस दिन के साथ-साथ रात की नींद व सुकून भी छीन सकता है। अप्रैल में ही पारा चालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना भारत में लोगों की जिंदगी की एक हकीकत बन चुकी है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ेगी और मानसून सामान्य से कम बरसेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भी अप्रैल से जून के बीच सामान्य से ज्यादा हीटवेव (लू) दिनों की आशंका जताई है।

पिछले चार दशकों में भारत का औसत तापमान लगभग 0.5 से 0.9 डिग्री तक बढ़ा है। यही 'बेसलाइन वार्मिंग' अब हर हीटवेव को पहले से और तेज बना रही है। 28 अप्रैल को 'एक्यूआई डॉट इन' के रियल टाइम

डाटा के मुताबिक, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में नब्बे से भी ज्यादा भारत के थे। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमामीटर द्वारा किए गए वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब हीटवेव पहले से ज्यादा जल्दी-जल्दी आने लगी हैं। साथ ही, उसकी संभावना भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इस विश्लेषण में पिछले 10 वर्षों (2014-2023) में गर्मियों के दौरान 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली रातों की संख्या पर गौर किया गया है।

*कंपाउंड हीट वेव्स एक्रॉस इंडियन स्मार्ट सिटीज* (द साउथ फर्स्ट, अप्रैल 2026) अध्ययन में पाया गया कि दिन और रात, दोनों ही समय लगातार चलने वाले हीट स्ट्रेस भारतीय शहरों का पैटर्न बन गए हैं। वैज्ञानिक इसे इस तरह समझाते हैं, 'दरअसल जलवायु परिवर्तन स्वयं हीटवेव पैदा नहीं करता, पर जब मौसम गर्म होता है, तो उसका असर पहले से ज्यादा गर्म, लंबा और तीखा होता है।' कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतों से भरे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, नागपुर और हैदराबाद जैसे महानगरों में घनी आबादी व कम हरियाली के कारण दिन तो बेहद गर्म रहते ही हैं, रातें भी ठंडी नहीं हो पातीं। इसे 'अर्बन हीट आइलैंड' कहा जाता है। *नेचर इंडिया* में प्रकाशित वर्ष 2022 के एक अध्ययन में दक्षिण एशिया के कम आमदनी वाले नगरीय इलाकों के अंदरूनी तापमान के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसमें पाया गया कि घनी आबादी और कम आमदनी वाले ऐसे इलाके, जहां पर हरियाली नहीं है, वहां दिन में बाहर के मुकाबले घरों के अंदर ज्यादा गर्मी होती है और यह रात में भी बरकरार रहती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की 2025 की *स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट* के अनुसार, 2015-2025 सबसे गर्म 11 साल रहे हैं। 2025 दूसरा सबसे गर्म साल था, जो 1850-1900 के औसत से करीब 1.43 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था।

गर्मी का तनाव एक बढ़ती हुई समस्या है। वैश्विक कार्यबल का एक-तिहाई से अधिक हर साल कार्यस्थल पर गर्मी के जोखिम का सामना करता है, विशेष रूप से कृषि व निर्माण में लगे लोग। लंबे समय तक तेज गर्मी में रहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, थकान बढ़ने के साथ हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही, मजदूरों व कामगारों की काम करने की क्षमता और कमाई पर भी बुरा असर पड़ता है।

*अर्थ्स फ्यूचर* में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, 1980 से 2021 के बीच खुले आसमान के नीचे उत्पन्न होने वाला हीट स्ट्रेस उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है और इसकी वजह से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में श्रमिकों की कार्य क्षमता में करीब 10 फीसदी की गिरावट आई है। क्लाइमेट सेंट्रल के विश्लेषण से जाहिर होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू-कश्मीर व आंध्र प्रदेश में 2018 से 2023 के बीच हर साल तपिश से भरे तकरीबन 50 से 80 दिन जुड़ते जा रहे हैं। मुंबई में रात के तापमान में सबसे ज्यादा बदलाव देखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण इस शहर को 65 अतिरिक्त गर्म रातों का अनुभव करना पड़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अच्छी व आरामदायक नींद के लिए रात का तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे अधिक तापमान होने से नींद व स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह इन्सान के शरीर को ठंडा होने की क्षमता को कम कर देती है और गर्मीजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, गैर-संचारी रोग, जैसे मधुमेह और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां और भी जोर पकड़ लेती हैं।

## गेहूं बेचने को लेकर दुविधा में किसान 3,000 रुपये के भाव पर अटकी नजर

### मंगलवार को 2,713 प्रति क्विंटल के आसपास रही गेहूं की कीमत

बोनस डेस्क

**नई दिल्ली।** मंडियों में गेहूं की आवक के साथ किसानों की बेचैनी भी बढ़ गई है। सरकारी खरीद चल रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सहारा भी है, फिर भी कई किसान भाव का अगला रुख भांपने में लगे हैं। वजह है 2024-25 की वह तेजी, जब गेहूं देश के कई बाजारों में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गया था। दिल्ली में भी 20 जनवरी, 2025 को भाव 3,325 रुपये पहुंचा था, जबकि 5 मई, 2026 यानी मंगलवार को कीमत 2,713 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक के किसान इसी सवाल से जूझ रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार को गेहूं बेच दें या कुछ दिन ठहरकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल वाले भाव का इंतजार करें। हालांकि, हरियाणा और पंजाब में किसान फसल को रोकते नहीं, बल्कि समर्थन मूल्य पर सरकार को ही बेच देते हैं। पिछले सीजन में जिन किसानों ने गेहूं रुककर बेचा था, उन्हें अच्छा भाव मिला। इस बार भी कुछ किसान उसी अच्छे भाव के उम्मीद में हैं, लेकिन बाजार की जमीन अब बदल चुकी है।

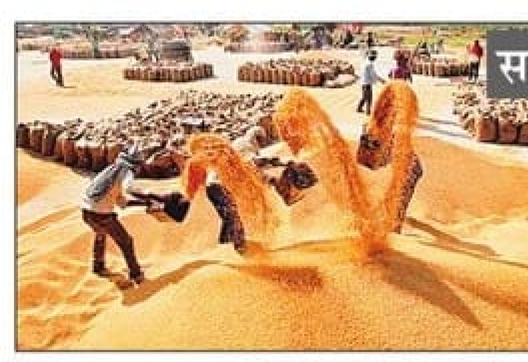

#### विशेषज्ञ बोले...भाव 3,300 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद न लगाएं

दिल्ली के भाव को बाजार संकेतक मानते हुए **एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल कहते हैं,** गेहूं के भाव में हालिया गिरावट की मुख्य वजह नई फसल की आवक से बढ़ी आपूर्ति और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता है। एमएसपी पर खरीद जारी है, लेकिन मंडियों में आने वाले पूरे माल का उठान नहीं हो पा रहा। आटा मिलों और ट्रेडर्स की खरीद भी जरूरत आधारित है।

■ पॉल कहते हैं, निकट अवधि में गेहूं 2,600-2,800 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रह सकता है। लंबी अवधि में सरकारी भंडार घटा, तो भाव को सहारा मिलेगा और भाव 2,800-3,000 रुपये तक जा सकता है। अभी 3,300 रुपये के भाव की उम्मीद लगाना सही नहीं है।

#### सरकार के पास पर्याप्त भंडार

**सबसे बड़ा फर्क सरकारी खरीद और भंडार का है।** एक मई तक सरकारी एजेंसियों के पास 3.6 करोड़ टन गेहूं का भंडार था, जो पांच साल में सबसे ज्यादा है। **यानी सरकार के पास बाजार में दखल देने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त गेहूं है।**

■ खरीद भी इस बार मजबूत है। केंद्र ने एमएसपी पर गेहूं खरीद लक्ष्य 3.03 करोड़ टन से बढ़ाकर 3.45 करोड़ टन कर दिया है। **पंजाब** में एक मई तक 116.98 लाख टन गेहूं खरीद हो चुकी है। इसमें निजी व्यापारियों का हिस्सा सिर्फ 1.01 फीसदी है, जो पिछले 7.92 फीसदी रही थी। यानी खुले बाजार में भाव को ऊपर ले जाने वाली निजी मांग कमजोर है।

■ **हरियाणा** में 56.13 लाख टन खरीद हो चुकी है। **मध्य प्रदेश** में भी खरीद लक्ष्य 78 लाख टन से बढ़ाकर 100 लाख टन किया गया है। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की समयसीमा 23 मई तक बढ़ाई है, ताकि ज्यादा किसान एमएसपी खरीद से जुड़ सकें।

■ ***मौसम की मार के बावजूद भाव के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान नहीं :*** *फसल पर मौसम की मार भी पड़ी है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 9 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में नुकसान हुआ है। इसके बावजूद 2025-26 में उत्पादन 11-12 करोड़ टन रह सकता है। यानी ऐसी कमी नहीं दिख रही, जो बाजार को फिर रिकॉर्ड स्तर तक ले जाए।*

## वाहनों की खुदरा बिक्री 13 फीसदी बढ़कर नए शिखर पर

### वाहन उद्योग के लिए 2026-27 की शुरुआत मजबूत, कारों समेत यात्री और दोपहिया वाहनों की भी रिकॉर्ड बिक्री

**नई दिल्ली।** घरेलू वाहन उद्योग ने बिक्री के लिहाज से नए वित्त वर्ष 2026-27 की मजबूत शुरुआत की है। देश में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अप्रैल, 2026 में करीब 13 फीसदी बढ़कर 26,11,317 इकाई के नए शिखर पर पहुंच गई। कारों समेत यात्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (फाडा) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने कुल 4,07,355 यात्री वाहन बिके। यह अप्रैल, 2025 के 3,63,028 इकाइयों के मुकाबले 12.21 फीसदी अधिक है। दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 13.01 फीसदी बढ़कर 19,16,258 इकाई पहुंच गई। तिपहिया वाहनों की बिक्री एक साल पहले के 99,741 इकाइयों से 7.19 फीसदी बढ़कर 1,06,908 इकाई पहुंच गई। वाणिज्यिक वाहन बिक्री भी 15.02 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 99,339 इकाई के नए शिखर पर पहुंच गई। ब्यूरो

#### इन वजहों से बिक्री को मिली रफ्तार

*फाडा उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, छह में से पांच वाहन श्रेणियों में बिक्री अप्रैल में अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। यह दर्शाता है कि 2025-26 की दूसरी छमाही में दिखी संरचनात्मक मांग नए वित्त वर्ष में भी जारी है। जीएसटी कटौती, आरबीआई की सहायक ब्याज दर नीति और मजबूत रबी फसल के बाद ग्रामीण नकदी प्रवाह जैसे सकारात्मक कारकों ने उद्योग को मजबूत प्रदर्शन करने में मदद की।*

#### शहरों के मुकाबले गांवों में तीन गुना तक अधिक बिक्री

गिरिधर ने कहा, शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। बीते महीने ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहनों की बिक्री में 20.40 फीसदी की वृद्धि रही, जो शहरों के 7.11 फीसदी से करीब तीन गुना अधिक है। यानी पर्सनल मोबिलिटी का दायरा छोटे शहरों और गांवों तक फैल रहा है। **इसकी वजह है...छोटी कारों की वापसी, एसयूवी की मांग और पेट्रोल-डीजल इंजन के अलावा अतिरिक्त विकल्प।**

■ यात्री वाहन बिक्री में सीएनजी का हिस्सा 22.62 फीसदी पर मजबूत बना रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 5.77 फीसदी पहुंच गई।

## भारत हर झटकों से निपटने में पूरी तरह सक्षम : मूडीज

### रेटिंग एजेंसी ने कहा...भारत उभरते बाजारों में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, पर भारी कर्ज बड़ा जोखिम

**नई दिल्ली।** पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत उभरते बाजारों में 2020 के बाद से सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है। देश के पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार है, जिसने वैश्विक झटकों के दौरान मुद्रा की अस्थिरता को नियंत्रित और भरोसा मजबूत करने में मदद की है। खास बात है कि देश किसी भी तनाव के समय मजबूत सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम है।

मूडीज रेटिंग्स ने मंगलवार को उभरते बाजारों पर जारी रिपोर्ट में कहा, स्पष्ट एवं भरोसेमंद मौद्रिक नीति, महंगाई स्थिर रहना और जरूरत पड़ने पर विनिमय दरों का

समायोजित हो पाना, इन सभी कारणों से भारत भविष्य के हर झटकों से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है। एजेंसी ने कहा, घरेलू वित्तपोषण पर भारत की निर्भरता स्थानीय बाजारों की मजबूती और बेहतर भंडार से संतुलित होती है। हालांकि, भारत पर कर्ज का भारी बोझ और कमजोर राजकोषीय संतुलन लगातार झटकों से निपटने के लिए उपलब्ध गुंजाइश को सीमित करता है।

मूडीज ने आगे कहा, पिछले पांच वर्षों में कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने कई बड़े वैश्विक झटकों को जोखिम उपाय बढ़ाए बिना और तेज वृद्धि या बाजार पहुंच खोए बिना सहन किया है। यह नीतिगत ढांचे में स्थायी सुधार, सुरक्षा उपायों और अनुकूल बाहरी हालात को दर्शाता है। इनमें भारत, ब्राजील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, मलयेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये और अर्जेंटीना जैसे बड़े उभरते बाजार शामिल हैं। एजेंसी

### न्यूज डायरी

#### रिलायंस रखरखाव के लिए बंद करेगी रिफाइनरी

**नई दिल्ली।** रिलायंस इंडस्ट्रीज इस महीने के मध्य तक 6.60 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफाइनरी की एक क्रूड सहित और कुछ अन्य इकाइयों को रखरखाव के लिए तीन से चार हफ्तों के लिए बंद करने जा रही है। इस दौरान नायरा एनर्जी 4 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफाइनरी में फिर उत्पादन शुरू करेगी, ताकि देश में ईंधन की कमी न हो। एजेंसी

#### एलएंडटी प्रति शेयर देगी 38 रुपये लाभांश

**नई दिल्ली।** एलएंडटी का 2025-26 की मार्च तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ तीन फीसदी घटकर 5,326 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, परिचालन राजस्व 11 फीसदी बढ़कर 82,762 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 38 रुपये प्रति शेयर अंतिम लाभांश देने की घोषणा की है। एजेंसी

#### पीएनबी का लाभ 14% बढ़ा, एनपीए में गिरावट

**नई दिल्ली।** पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 2025-26 की मार्च तिमाही में 14.4 फीसदी बढ़त के साथ 5,225 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। बैंक का एनपीए 3.95 फीसदी से घटकर 2.95 फीसदी रह गया। बैंक ने 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर लाभांश देने की घोषणा की है। एजेंसी

## दुनिया के पास बचा है केवल 101 दिनों की मांग के बराबर कच्चा तेल

**नई दिल्ली।** दुनिया में कच्चे तेल का भंडार आठ साल के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। चिंता केवल भंडार घटने की नहीं है, बल्कि उसके तेजी से खत्म होने की रफ्तार की है। इस संकट के केंद्र में होर्मुज है, जिसके कई महीनों से बाधित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ा है।

गोल्डमैन सैश के मुताबिक, आपूर्ति संकट के कारण दुनिया के पास सिर्फ 101 दिनों की मांग के बराबर तेल बचा है। मई अंत तक यह घटकर 98 दिन रह सकता है। यानी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले महीनों में तेल बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता रिफाइंड उत्पादों को लेकर है। पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन का वैश्विक भंडार युद्ध से पहले 50 दिनों की मांग के बराबर था, जो अब घटकर 45 दिन रह गया है। इसका मतलब है कि आसानी से उपलब्ध ईंधन का बफर तेजी से कम हो रहा है। गोल्डमैन सैश का मानना है कि इस गर्मी में भंडार पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन मौजूदा रफ्तार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। ■ बोनस डेस्क

#### गोल्डमैन सैश का दावा वैश्विक तेल भंडार आठ साल के निचले स्तर के करीब

## जेएलआर ने ब्रिटेन आयातित कारों के दाम 75 लाख तक घटाए

**नई दिल्ली।** जगुआर लैंडरोवर यानी जेएलआर की भारतीय इकाई ने मंगलवार को भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने की संभावना को देखते हुए ब्रिटेन में पूरी तरह निर्मित रेंज रोवर मॉडल की कीमतों में 75 लाख तक की कटौती की घोषणा की।

यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस कटौती के बाद ब्रिटेन से आयातित रेंज रोवर एसवी मॉडल की शुरुआती शोरूम कीमत 4.25 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ रुपये हो गई है। रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी मॉडल की कीमत 2.75 करोड़ रुपये से घटाकर 2.35 करोड़ रुपये कर दी गई है। एजेंसी

## लोगों के पास रिकॉर्ड 42.3 लाख करोड़ रुपये की नकदी, सिर्फ 15 दिन में 610 अरब बढ़ी

**नई दिल्ली।** डिजिटल लेनदेन के बावजूद नकदी का चलन बढ़ रहा है। देश में अप्रैल के पहले 15 दिनों में लोगों के पास मौजूद नकदी का मूल्य 610 अरब रुपये से अधिक बढ़कर 42.3 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले 11.8 फीसदी और नोटबंदी के बाद से सबसे ज्यादा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर यह बढ़ोतरी जारी रही, तो बैंकिंग प्रणाली में मौजूद तरलता के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप में उप-प्रमुख (शोध) अभिषेक उपाध्याय ने कहा, हाल के वर्षों में जीडीपी वृद्धि के मुकाबले नकदी की मांग कुछ हद तक कम रही थी, जिससे अब इसमें तेजी से उछाल आने का माहौल बना है। इसमें ग्रामीण इलाकों से आने वाली मजबूत मांग की भी बड़ी भूमिका है, जिसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में की गई कटौती से सहारा मिला है। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष का कहना है कि कम ब्याज दरों ने नकदी के इस्तेमाल को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसके अलावा, बढ़ती कीमतों की वजह से घरों में सोने और चांदी की रीसाइक्लिंग के जरिये भी चलन में मौजूद नकदी में बढ़ोतरी हो सकती है। एजेंसी

## बैंकों ने बांटे 212.9 लाख करोड़ के कर्ज, 15.9% वृद्धि

**नई दिल्ली।** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15.9 फीसदी की मजबूत कर्ज वृद्धि दर्ज की। वित्त मंत्रालय के अनुसार, मार्च 2026 तक बैंकों का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 212.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले के 29.2 लाख करोड़ रुपये अधिक है।

मंत्रालय ने कहा, कम ब्याज दरों, पूंजीगत व्यय और सुधारों के कारण निजी निवेश बढ़ा, जिससे कर्ज की मांग को मजबूती मिली। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक 19 फीसदी वृद्धि देखी गई। व्यक्तिगत ऋण 6.2 फीसदी और कृषि क्षेत्र के कर्ज में 15.7 फीसदी की वृद्धि रही। औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि 15 फीसदी रही, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 8.2 फीसदी थी। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए ऋणों की मजबूत हिस्सेदारी रही। ब्यूरो

अमर उजाला **Job Alert**

Real-time job alerts amarujala.com/jobs

### उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

वन रक्षक के पदों पर रिक्तियां

**708 पद**

आवेदन की अंतिम तिथि : 20 जुलाई, 2026
योग्यताएं : बारहवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : upsssc.gov.in

### बीपीसीएल में निकली भर्ती ■ 250 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 24 मई, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम उम्र 32 व 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : bharatpetroleum.in

### एलिम्को में करें आवेदन ■ 162 पद

आईटी कंसल्टेंट व अन्य पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 13 मई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : alimco.in

### यूपीईएसएससी की अधिसूचना ■ 107 पद

सहायक आचार्य/सहायक प्रोफेसर के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 27 मई, 2026
पात्रताएं : पोस्ट-ग्रेजुएशन, बीएड व अन्य योग्यताएं
यहां आवेदन करें : upessc.up.gov.in

### भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ■ 43 पद

कंप्यूटर ऑपरेटर-कम-टाइपिस्ट के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 13 जून, 2026
वेतनमान : रुपये 30,000 - रुपये 1,20,000 तक
यहां आवेदन करें : bel-india.in

### राष्ट्रीय जांच एजेंसी ■ 29 पद

अनुभाग अधिकारी आदि पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 18 मई, 2026
वेतनमान : रुपये 19,900 से लेकर रुपये 1,42,400 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : nia.gov.in

#### यहां भी हैं रोजगार के मौके...

**आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो : यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली भर्ती।**
■ वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 18 मई, 2026
■ nbpgr.org.in

**अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, दिल्ली : परियोजना तकनीकी सहायक-III का पद खाली।**
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई, 2026
■ aiims.edu

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

# एजुकेशन & कॅरिअर

निरंतर प्रयास से असंभव लगने वाली चीज भी संभव लगने लगती है।

एग्जाम टिप्स : आरआरबी एनटीपीसी-2026

## कल है परीक्षा, इन बातों का रखें ध्यान

देवाशीष उपाध्याय
एग्जाम एक्सपर्ट

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) परीक्षा भारत की सबसे बड़ी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य रेलवे में विभिन्न गैर-तकनीकी पदों जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर आदि के लिए योग्य और सक्षम उम्मीदवारों का चयन करना है। चूंकि यह परीक्षा कल आयोजित होने वाली है, इसलिए अब तैयारी के लिए समय बहुत सीमित रह गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को नई चीजें पढ़ने के बजाय पहले से तैयार किए गए विषयों का रिवीजन, मॉक टेस्ट का विश्लेषण और समय-प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सही रणनीति, आत्मविश्वास और शांत मन के साथ परीक्षा में बैठना सफलता की संभावना को काफी बढ़ा सकता है।

**■ रिवीजन की रणनीति**

यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में ली जाती है। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिन्हें 90 मिनट में हल करना होता है। इनमें सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 30 प्रश्न शामिल होते हैं। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए टॉपिक्स पढ़ने के बजाय पहले से पढ़े हुए विषयों का रिवीजन किया जाए। 80/20 नियम के अनुसार 20% महत्वपूर्ण टॉपिक्स से 80% अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को उन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, जिनसे परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं।

**■ बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें**

गणित सेक्शन में प्रतिशत, लाभ-हानि, समय और कार्य, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और औसत जैसे टॉपिक्स को जल्दी-जल्दी रिवाइज करना चाहिए। इस समय कठिन प्रश्नों में उलझने के बजाय आसान और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर फोकस करना बेहतर होता है। रीजनिंग में कोडिंग-डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन और पजल्स जैसे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। इनका अभ्यास करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है, जो परीक्षा में काफी मदद करती है।

**■ किसी एक प्रश्न पर न टिके रहें**

परीक्षा में समय-प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए किसी एक प्रश्न पर ज्यादा समय न लगाएं और पहले आसान प्रश्न हल करने की कोशिश करें। गलत उत्तरों से बचने के लिए अनुमान लगाकर उत्तर देने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, और समझदारी से सवाल चुनकर हल करना आपके कुल स्कोर को बेहतर बना सकता है।

- *परीक्षा के दौरान हर सेक्शन को संतुलित समय दें और किसी एक प्रश्न पर ज्यादा समय न लगाएं।*
- *घबराहट से बचें और पूरे ध्यान के साथ प्रश्नों को समझकर हल करें।*
- *पहले किए गए अभ्यास को याद रखें और उसी अनुभव का उपयोग परीक्षा में करें।*
- *परीक्षा में समय का सही उपयोग करें और शांत रहें।*

**■ नींद जरूरी है**

उम्मीदवारों को शांत मन से अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखना भी सफलता की दिशा में अहम कदम साबित होता है। इसके साथ ही, स्वस्थ दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम भी परीक्षा के दौरान एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं।

#### आवेदन आमंत्रित

**विजिटिंग फेलोशिप-2026**

- **पात्रताएं :** उम्मीदवार वैज्ञानिक, तकनीशियन, स्नातकोत्तर छात्र (पीएचडी को प्राथमिकता) या पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो हो सकते हैं, जो समुद्र विज्ञान पर काम कर रहे हों।
- **अवधि :** सितंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच
- **लाभ :** 5000 यूरो
- **आवेदन लिंक :** pogo-ocean.org
- **अंतिम तिथि :** 13 मई, 2026

#### स्कॉलरशिप प्रोग्राम

**जेकेएलयू व एचएसबी, एसएएस**

- **संस्थान :** जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय और हरि शंकर सिंघानिया स्कूल ऑफ बिजनेस
- **योग्यताएं :** बारहवीं, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं।
- **लाभ :** योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां
- **अंतिम तिथि :** 26 मई, 2026
- **आवेदन लिंक :** tinyurl.com/4cm6bbej

#### एग्जाम अलर्ट

**आरएसएसबी प्रयोगशाला सहायक (भूगोल) परीक्षा**

- **परीक्षा की तिथि :** 09 मई, 2026
- इस परीक्षा में भाग-I में राजस्थान का सामान्य ज्ञान (इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत) से 100 अंकों के प्रश्न व भाग-II में भूगोल से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** sso.rajasthan.gov.in

**भारतीय नौसेना अग्निवीर एसएसआर/एमआर परीक्षा**

- **परीक्षा की तिथि :** 13 से 15 मई, 2026
- इस परीक्षा में क्रमशः 100 और 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इनकी अवधि क्रमशः एक घंटा और 30 मिनट है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/4zusf7aw

#### खुद को परखें

1. उदयन किला किस राज्य में स्थित है?
(a) उत्तर प्रदेश (b) मध्य प्रदेश
(c) राजस्थान (d) गुजरात

2. स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी?
(a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(b) पंचायती राज मंत्रालय
(c) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
(d) कृषि मंत्रालय

3. कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है?
(a) इंडोनेशिया (b) ऑस्ट्रेलिया
(c) न्यूजीलैंड (d) चीन

4. डैम्पे उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है?
(a) चीन (b) रूस
(c) भारत (d) फ्रांस

5. गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
(a) राजस्थान (b) गुजरात
(c) कर्नाटक (d) केरल

उत्तर : 1.a, 2.b, 3.a, 4.a, 5.b

### आज का दिन

6 मई, 1954

ब्रिटिश एथलीट रोजर बैनिस्टर चार मिनट से कम समय में एक मील दौड़ने वाले पहले एथलीट बने। उन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में यह दूरी तय की थी।

■ **1957 :** टेलीविजन कॉमेडी शो 'आई लव लूसी' का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ था।
■ **1964 :** भारत के प्रसिद्ध तैराक खजान सिंह का जन्म हुआ था।
■ **1992 :** जर्मन-अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन डिट्रिच का पेरिस में निधन हुआ था।
■ **2010 :** मुंबई पर हमला करने वाले आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई।

#### व्रत त्योहार

**आज :** ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी/पंचमी।
**कल :** ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
**राहुकाल :** दिन में 13.30 से 15.00 तक।

■ सूर्योदय : 05.40
■ सूर्यास्त : 18.56
(भारतीय मानक समयानुसार)

#### कल का पंचांग

**विक्रमी संवत** 2083, 17 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 24 प्रविष्टे, 19 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी 10.13 तक उपरांत षष्ठी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 18.45 तक उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, साध्य योग 25.58 तक उपरांत शुभ योग, तैतिल करण 10.13 तक उपरांत गर करण, चंद्रमा मकर राशि में 25.23 बजे।

#### राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

**मेष :** उतावलेपन में निर्णय लेने से बचें। नौकरी में पूर्व में किए श्रम का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

**वृष :** मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी आ सकती है। कीमती वस्तु संभाल कर रखें।

**मिथुन :** सकारात्मक सोच बनाए रखें। नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। वाहन सुख मिलेगा।

**कर्क :** आत्मबल बनाए रखें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। विरोधी परास्त होंगे।

**सिंह :** सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा।

**कन्या :** दिनमान सामान्य रहेगा। संपत्ति संबंधी अटका कार्य बन सकता है। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा।

**तुला :** मानसिक तनाव से बचें। सामाजिक मान-सम्मान बना रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है।

**वृश्चिक :** दिनमान प्रतिकूल रहेगा। स्वजनों से वाद-विवाद संभव है। नौकरी में सावधानी बरतें।

**धनु :** मन प्रसन्न रहेगा। अटका कार्य बनेगा। नौकरी में प्रमोशन का अवसर मिल सकता है।

**मकर :** धैर्य बनाए रखें। नौकरी में दबदबा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी।

**कुंभ :** मन में आशा का संचार होगा। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में नूतन पदभार संभव है।

**मीन :** योजना में सफलता से हर्षित रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। नौकरी में सम्मान बना रहेगा।

#### सुडोकू

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | 7 | 9 | | | | |
| 7 | | 1 | | 4 | | | 9 | 6 |
| | | | | | | | | |
| 6 | | | | 7 | | | 8 | 1 |
| | | 8 | | | | 2 | | |
| 5 | 2 | | | 8 | | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| 8 | 3 | | | 1 | | 9 | | 4 |
| | | | | 6 | 9 | | 7 | |

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 |